पुनरीक्षण की परतें

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

अगर वर्ष 1991 से 1996 के बीच कोई जनमत संग्रह हुआ होता, तो भारत के निर्वाचन आयोग को निश्चित रूप से देश की श्रेष्ठ और सबसे प्रभावशाली संस्था चुना जाता- यहां तक कि संवैधानिक न्यायालयों से भी ऊपर। इसका श्रेय जाता है तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) टीएन शेषन को, जिनके कार्यकाल में आयोग की स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता (तीन 'आइ') की सर्वत्र सराहना हुई। शेषन के बाद जिन मुख्य चुनाव आयुक्तों ने तीन 'आइ' के मूल्यों का दृढ़तापूर्वक संरक्षण किया, वे थे एमएस गिल, जेएम लिंगदोह, टीएस कृष्णमूर्ति, नवीन चावला और एसवाई कुरैशी। इसके अलावा दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त आए और चले गए, वे कभी दबाव में झुकते दिखे और कभी न झुकने का दिखावा करते रहे। पिछले बारह वर्षों में नियुक्त किए गए मुख्य चुनाव आयुक्त संवैधानिक दृष्टि से कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए।

स्वतंत्रता

चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। शुरुआती वर्षों में चुनाव कराना कोई बड़ी चुनौती नहीं मानी जाती थी। लोग स्थानीय क्षत्रपों की इच्छा के अनुसार मतदान करते थे। कुछ वर्गों को मतदान से रोका जाता था, लेकिन वे इतने गरीब और कमजोर थे कि विरोध नहीं कर पाते थे और कांग्रेस के लिए कोई राजनीतिक चुनौती नहीं थी। वर्ष 1967 के बाद चुनाव चुनौतीपूर्ण हो गए। वर्ष 1965 से 2014 के बीच की सरकारों ने चुनाव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं किया और न ही मुझे हस्तक्षेप का कोई आरोप याद है। राज्य विधानसभाओं के कुछ चुनावों में धांधली के आरोप लगे, लेकिन ये आरोप केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की अयोग्यता के खिलाफ थे।

वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष था। तब से, लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के ज्यादातर चुनाव अयोग्यता, धांधली, धोखाधड़ी और उससे भी बदतर के लिए व्यापक आलोचना का विषय रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद से चुनाव आयोग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और उसकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा है।

नवंबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूचियां विवाद का विषय बन गईं। आरोप हैं कि (1) मतदाता सूचियों में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में नए और शायद फर्जी नाम जोड़े गए और (2) मतदान का समय समाप्त होने के काफी देर बाद भी असामान्य रूप से बड़ी संख्या में लोगों को मतदान करने की अनुमति दी गई। चुनाव आयोग ने दोनों आरोपों के खिलाफ अपना बचाव करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।

> विशेष गहन पुनरीक्षण अलग है। यह प्रभावी रूप से वर्तमान मतदाता सूची को रद्द कर देता है। अब जिम्मेदारी मतदाता पर डाल दी गई है: भले ही उसका नाम मौजूदा वर्तमान मतदाता सूची में हो और उसने वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव या 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया हो, मगर अब उसे फिर से नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा।

समग्रता

एक और कड़े मुकाबले वाला विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में। फिर अगले साल और भी चुनाव होने हैं। बिहार परीक्षा की एक कसौटी है। राज्य में चुनाव से बमुश्किल चार महीने पहले, चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) शुरू कर दिया है। यह असामान्य और अभूतपूर्व है। मतदाता सूची आमतौर पर वर्ष के पहले माह जनवरी की पहली तारीख को अद्यतन की जाती है और चुनावों के दौरान इसका एक संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाता है। संक्षिप्त पुनरीक्षण का मतलब है कि नए और अपंजीकृत मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे और मृत या स्थायी रूप से राज्य या क्षेत्र छोड़ चुके मतदाताओं को वर्तमान मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। वर्तमान मतदाता सूचियों का बड़ा हिस्सा बरकरार और अछूता रहेगा। इसके साथ ही, मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और हटाने का कार्य राजनीतिक दलों की जानकारी और भागीदारी से किया जाएगा। नाम जोड़ने के प्रत्येक मामले की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी और नाम हटाने के प्रत्येक मामले पर पूरी बहस और सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण अलग है। यह प्रभावी रूप से वर्तमान मतदाता सूची को रद्द कर देता है। इस दावे के बावजूद कि यह प्रक्रिया वर्ष 2003 की मतदाता सूची पर आधारित है, यह प्रभावी रूप से शून्य आधार से शुरू होकर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई मतदाता सूची तैयार करता है। इसके अलावा, अब जिम्मेदारी मतदाता पर डाल दी गई हैः भले ही उसका नाम मौजूदा वर्तमान मतदाता सूची में हो और उसने वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव या 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया हो, मगर अब उसे फिर से नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा। और यह सब 25 जून से 26 जुलाई के बीच पूरा होने की उम्मीद है।

निष्पक्षता

इस प्रक्रिया का मकसद नामांकन को सक्षम करना नहीं है, बल्कि नामांकन करने और मतदान करने के रास्ते में असाध्य बाधाएं डालना है। चुनाव आयोग ने नागरिकता के 'प्रमाण' के रूप में ग्यारह दस्तावेज निर्धारित किए हैंः उनमें से चार में जन्म स्थान की जानकारी नहीं है और दो दस्तावेज बिहार में किसी व्यक्ति को जारी नहीं किए गए हैं। इसलिए किसी व्यक्ति की नागरिकता साबित करने के लिए प्रभावी रूप से केवल पांच दस्तावेज (राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र सहित) हैं। पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र या सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र बिहार की आबादी के केवल 2.4 से पांच फीसद लोगों के पास उपलब्ध हैं। इनकी अनुपस्थिति में स्पष्ट है कि (1) आधार, (2) चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र और (3) राशन कार्ड ही बचते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि इन तीन दस्तावेजों को विशेष गहन पुनरीक्षण के उद्देश्य के लिए शामिल क्यों नहीं किया जा सकता है, तो उस वक्त आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। विडंबना यह है कि राजस्व अधिकारियों की ओर से 'आधार' के आधार पर निवास और जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं; जबकि निवास या जाति प्रमाणपत्र विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए वैध है, आधार अवैध है!

विशेष गहन पुनरीक्षण का एकमात्र तर्कसंगत पहलू यह है कि मृत व्यक्तियों और दोहरी प्रविष्टि वाले नामों को हटाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग का अनुमान है कि 17.5 लाख मतदाता राज्य से चले गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अब बिहार के मूल निवासी नहीं हैं या मतदान करने वापस नहीं आएंगे। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 15 जुलाई को बाहरी राज्यों के मतदाताओं के नामांकन के लिए एक फार्म जारी किया था और उम्मीद है कि यह प्रक्रिया 26 जुलाई तक पूरी हो जाएगी!

अनिवार्य निष्कर्ष यह है कि विशेष गहन पुनरीक्षण योग्य नागरिकों को नामांकन और मतदान करने में सक्षम बनाने का कोई प्रयास नहीं है। यह लाखों गरीब, हाशिये पर पड़े या प्रवासी नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने की एक भयावह साजिश है। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है।

दिखावे के आंसू

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री का यह नारा बहुत याद आया पिछले सप्ताह जब ओड़ीशा की बीस साल की एक बेटी ने आत्महत्या कर ली। इसलिए कि उसे पढ़ाने वालों ने ही उससे उसकी इज्जत का सौदा मांगा। बेटी ने हिम्मत दिखा कर कालेज प्रबंधन के सामने अध्यापक का नाम लेकर शिकायत दर्ज की, लेकिन उसे अपनी शिकायत वापस लेने को कहा गया। पुलिस में जाकर उसने प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भी उसका साथ नहीं दिया। फिर उसने सोशल मीडिया पर घोषित किया कि उसको न्याय नहीं मिलता है, तो वह आत्महत्या करने के लिए तैयार है। जब न सुनवाई हुई, न सहायता मिली और न संवेदनशीलता किसी ने दिखाई, तो यह बेटी बच न सकी। अपने शरीर में आग लगा कर उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। आखिरी जुल्म उस पर यह हुआ कि उसको अस्पताल ले जाने में कोई पांच घंटे की देरी हुई। उसका शरीर नब्बे फीसद से ज्यादा जल चुका था। शायद उसकी जान बच जाती अगर अस्पताल पहुंचती समय पर।

पढ़ने वाली बेटी के मरने के बाद अखबारों में लंबे-चौड़े लेख छपे। लिखने वालों ने खूब संवेदना जताई और घड़ियाली आंसू बहाए, लेकिन सच यह है कि इस तरह की कहानियां इतनी ज्यादा सुनने को मिलती हैं भारत में कि आंसू भी लोगों के सूख गए हैं। इस बेटी के मरने के कुछ दिन बाद एक वीडियो देखा मैंने, जिसमें दस साल की एक बच्ची को एक आदमी घसीट कर लेकर जाता है सुनसान सड़क के किनारे झाड़ियों में। उससे बलात्कार करता है। यह खबर तमिलनाडु से थी।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, छोटी बच्चियों से बलात्कार के मामले 2016 और 2022 के बीच 96 फीसद बढ़ गए। इन आंकड़ों के अनुसार, बलात्कार के सबसे अधिक मामले 2022 में राजस्थान मेंदर्ज हुए। आंकड़ा था 5399, नंबर दो पर आया उत्तर प्रदेश जहां 3690 मामले दर्ज हुए और तीसरे नंबर पर आया मध्य प्रदेश, जहां 3029 मामले दर्ज हुए राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के मुताबिक। रही बात पढ़ने वाली बेटियों से बलात्कार की, तो दो दर्दनाक मामले आए हैं पिछले महीनों में कोलकाता से। पहले वाले में एक बेटी जो मेडिकल कालेज में पढ़ रही थी जान से मारी गई बलात्कार के बाद। दूसरे में एक बेटी जो वकालत पढ़ रही थी उससे सामूहिक बलात्कार हुआ कालेज के अंदर। यह बेटी जीवित रही और जिन दरिंदों ने उससे बलात्कार किया वे गिरफ्तार हुए। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है उस देश में जिसके प्रधानमंत्री ने खुद बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है।

> बेटियों के खिलाफ जब दरिंदगी होती है, तो हमारे राजनेता वास्तव में असली संवेदना कभी नहीं जताते हैं, न असली दर्द होता है उन्हें। बंगाल या तमिलनाडु में जब किसी बेटी से बलात्कार होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खूब हाय-तौबा मचाते हैं। उत्तर प्रदेश या राजस्थान में जब कोई दरिंदगी का मामला सामने आता है, तो हल्ला मचाते हैं विपक्षी दल के नेता।

सवाल का जवाब है कि बेटियों के खिलाफ जब दरिंदगी होती है, तो हमारे राजनेता वास्तव में असली संवेदना कभी नहीं जताते हैं, न असली दर्द होता है उन्हें। बंगाल या तमिलनाडु में जब किसी बेटी से बलात्कार होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खूब हाय-तौबा मचाते हैं। उत्तर प्रदेश या राजस्थान में जब कोई दरिंदगी का मामला सामने आता है, तो हल्ला मचाते हैं विपक्षी दल के नेता। जब कुछ साल पहले कश्मीर में एक छोटी बच्ची से बर्बरता हुई थी, तो वहां के हिंदू संगठनों ने साथ दिया था उस पुजारी और उसके बेटे का, जिसने इस बच्ची को मंदिर में कैद कर-के भूखा-प्यासा रख कर कई दिनों तक उसको नशे की गोलियां देकर उससे ऐसी दरिंदगी की, जिसके लिए मेरी शब्दावली में शब्द नहीं हैं।

राजनीतिक अगर देश की बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो उससे भी अधिक अन्याय उनके साथ होता है हमारी अदालतों में। बलात्कार के मामले अगर पहुंचते भी हैं अदालतों तक, तो इतना लंबा चलता है कि शिकायत दर्ज करने वाली बेटी ही हार मान लेती है कई बार। अक्सर जमानत पर छूट जाते हैं बलात्कारी और कई बार तो वे पीड़िता को धमकाने-डराने में लग जाते हैं और कई बार तो उसको जान से मार देते हैं ताकि गवाही न दे सके। ऐसी भी बेटियां हैं इस देश में जिन्होंने शिकायत दर्ज करने के बाद तंग आकर खुदकुशी कर ली है। कुछ बेटियों पर तेजाब फेंका जाता है अगर वे शिकायत वापस लेने के लिए तैयार नहीं होती हैं।

राजनीति और न्याय के चक्र से रिहा होती हैं, तो इस देश की बेटियों का यह हाल है कि उनके परिजन ही उनको शर्मिंदा करने में लग जाते हैं। ऊपर से कई कहानियां ऐसी हैं जिनमें उनके बाप और भाई ही उनका यौन शोषण करने में लग जाते हैं। यानी सबसे बड़ी समस्या सामाजिक है, खासतौर पर देहातों में जहां छोटी कही जाने वाली जाति की बेटियों से ऊंची कही जाने वाली जाति के लड़के बलात्कार करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह ऐसी समस्या है जो अच्छे नारे से नहीं हल होने वाली है, लेकिन अगर हमारे राजनेता अच्छे शब्दों से आगे निकल कर वास्तव में बलात्कार के खिलाफ मुहिम चलाने की हिम्मत दिखाते हैं, तो शायद कुछ बदल सकता है। आज नहीं तो कम से कम कल या परसों।

शुरुआत अगर राजनेता करते हैं ईमानदारी से, तो हो सकता है कि कभी न कभी भविष्य में इस देश की बेटियों को वास्तव में बचाने और पढ़ाने का काम होगा। वर्तमान हाल यह है कि रोज बलात्कार का कोई न कोई नया मामला आता है और अक्सर इन बेटियों की कहानियां सुर्खियों में नहीं कही जाती है। छिपा कर लिखी जाती है संक्षिप्त में, जैसे हम सब मान चुके हैं कि ऐसा तो होता ही है हमारे देश में। इसलिए कब तक इसको लेकर दुखी होते रहेंगे।

रूढ़ियों का दुश्चक्र

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

समाज

मोनिका शर्मा

कुरीतियों या रूढ़ियों की जड़ें गहरी होती हैं। जीवनशैली में बदलाव मानसिकता बदलने की पुष्टि नहीं करता। न ही शिक्षा के आंकड़े संवेदनाओं और मानवीय समझ को पोषित करने की तस्दीक करते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में सत्ताइस वर्षीय एक युवती की आत्महत्या की घटना इन्हीं स्थितियों की बानगी है। इस तरह की घटनाएं न केवल समाज को झकझोर देने वाली हैं, बल्कि बदलाव के नाम पर आए मात्र सतही दिखावे की स्थिति को भी सामने रखती हैं। इस युवती की शादी दो महीने पहले ही हुई थी। आरोप है कि विवाह में दहेज के तौर पर सोना और महंगी गाड़ी दी गई थी। बावजूद इसके ससुरालवाले उसे कम दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिस कारण उसने जीवन से हार मान ली। खुदकुशी से पहले इस युवती ने अपने पिता को मोबाइल फोन पर सात आडियो संदेश भेजे और रोज की मानसिक प्रताड़ना को सहन करने में असमर्थ होने की बात कही।

मौजूदा दौर में किसी को दहेज के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करना बीते जमाने की बात लगती है। जबकि यह कटु सत्य है कि लालच की इस मानसिकता के कारण आज भी कई युवतियों की शादी उनके लिए एक बुरा सपना बन कर रह जाती है। कहीं जीवनभर की प्रताड़ना और ताने-उलाहने, तो कहीं जीवन का साथ छोड़ देने के हालात उनके हिस्से आ जाते हैं। चिंताजनक यह है कि ऊपरी तौर पर बदले सामाजिक-पारिवारिक परिवेश में स्थितियां और मुश्किल हो गई हैं। आज के बनावटी-दिखावटी परिवेश में तो विश्वास दिलाना भी मुश्किल हो गया है कि किसी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। अपने पिता को भेजे संदेश में इस युवती ने भी स्पष्ट किया कि वह झूठ नहीं बोल रही है और हर कोई उसके आसपास नाटक कर रहा है। ऐसे में यह संदेश एक शिक्षित-सजग युवती के मन की पीड़ा ही नहीं, परिवेश की तयशुदा सोच को भी उजागर करता है।

दहेज के लिए प्रताड़ित होने के कारण जीवन से हारने वाली युवतियां ऐसे संदेशों में समाज की कड़वी सच्चाई अपने पीछे छोड़ जाती हैं। कुछ वर्ष पहले अहमदाबाद में भी एक महिला ने वीडियो संदेश में स्त्री जीवन की त्रासद हकीकत से रूबरू करवाने के बाद नदी में छलांग दी थी। उसे भी ससुरालवालों की ओर से दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने का दावा किया गया था। दरअसल, हाल के बरसों में हर वर्ग एवं समुदाय में ठाट-बाट से शादी और मोटा दहेज देने का दिखावटी-बनावटी माहौल बन गया है। महंगी शादी से शुरू होने वाली इन मांगों का अक्सर कोई अंत ही नहीं होता। वहीं नवविवाहिता से लेकर गर्भवती तक, अनगिनत महिलाओं को दहेज की मांग के लिए आए दिन प्रताड़ित किया जाता है। दहेज केवल आर्थिक लेन-देन भर का मामला नहीं है। यह बेटियों के अस्तित्व को नकारने वाली मांग भी लगती है। ससुराल में उनकी स्वीकार्यता के बदले मोल स्वरूप धन देना मन कचोटने वाली कुरीति है। विशेषकर किसी परिवार की क्षमता से बढ़ कर की गई मांग तो सचमुच स्त्रियों के स्वतंत्र अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न लगाती है।

दहेज का दंश अपेक्षाओं और उपेक्षाओं का एक ऐसा कुचक्र है, जो अपने ही आंगन में औरतों का जीना दुश्वार कर देता है। महिलाएं अपनों के बीच भी खुद को दोयम दर्जे का महसूस करने लगती हैं, जो कि मानसिक रूप से बेहद पीड़ादायी है। साथ ही सामाजिक परिवेश में भी महिला और उसके परिवार को उपेक्षित तथा अपमानित करने की स्थितियां बना दी जाती हैं। मन को ठेस पहुंचाने वाला अपनों का यह बर्ताव जीवन को ही असुरक्षा के घेरे में ले आता है। नतीजतन, दहेज के दानव ने अबतक जाने कितनी बेटियों की बलि ले ली है। देश के हर हिस्से में इस कुरीति के कारण कभी घर टूटने, तो कहीं जीवन का साथ छूटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हालांकि दहेज प्रथा को रोकने के लिए हमारे यहां कड़े कानून बने हैं, पर वैवाहिक समारोहों में होने वाला यह लेन-देन आज भी जारी है। आमजन ही नहीं जन-प्रतिनिधियों और चर्चित चेहरों के परिवारों में भी वैवाहिक समारोहों का दिखावा और दहेज का लेन-देन आम बात है। स्पष्ट दिखता है कि समाज में संपन्नता बढ़ी है, तो शादियों में दिखावा भी बढ़ गया।

दुखद है कि बेटियों के आत्मनिर्भर और शिक्षित होने के बावजूद दहेज की कुरीति कायम है। गलतफहमी यह भी है कि दहेज की कुरीति केवल निचले या मध्यम तबके तक ही सीमित है। जबकि हमारे समाज में आर्थिक स्तर पर ऊंचे माने जाने वाले वर्गों में भी दहेज मांगने की रीत देखने को मिलती है। इसकी जड़ें सामाजिक-पारिवारिक व्यवस्था में गहरे तक फैली हुई हैं। जिसका सीधा-सा अर्थ है कि बुनियादी रूप से समाज और परिवार की मानसिकता में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। बहुत से परिवारों में माता-पिता बेटियों की उच्च शिक्षा में धन खर्च करने के बजाय उनके विवाह में खर्च करने को प्राथमिकता देते हैं।

> मौजूदा दौर में किसी को दहेज के लिए भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करना बीते जमाने की बात लगती है। जबकि यह कटु सत्य है कि लालच की इस मानसिकता के कारण आज भी कई युवतियों की शादी उनके लिए एक बुरा सपना बन कर रह जाती है। कहीं जीवनभर की प्रताड़ना और ताने-उलाहने, तो कहीं जीवन का साथ छोड़ देने के हालात उनके हिस्से आ जाते हैं।

इस समस्या का एक पक्ष दहेज के कानून का दुरुपयोग होने के आरोप भी हैं। कई वैवाहिक विवादों के संदर्भ में ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर ससुरालवालों और यहां तक कि उनके दूर के रिश्तेदारों पर भी आपराधिक मुकदमा कर देती हैं। हालांकि दुरुपयोग के आरोपों के कुछ मामलों के आधार पर इस समस्या की वास्तविकता को झुठलाया नहीं जा सकता। सच यह है कि दुरुपयोग के आरोपों के सामान्यीकरण के असर से इस समस्या के असल पीड़ितों को न्याय मिलने में अड़चन आ सकती है। गांवों-कस्बों में तो जो महिलाएं सचमुच दहेज के लिए परिवारजनों की प्रताड़ना झेल रही हैं, उन्हें दहेज विरोधी कानून की पूरी जानकारी तक नहीं है। किसी भी कुरीति को दूर करने के लिए परिवार और समाज की दकियानूसी सोच का बदलना भी आवश्यक है, क्योंकि दहेज की समस्या अब किसी जाति, वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं है।

जलेबी समोसा जिंदाबाद

बाखबर

सुधीश पचौरी

एक यात्री विमान ध्वस्त! 'ब्लैक बाक्स' की खोज! दुर्घटना का कारणः ईंधन बंद, तेल रुका, इंजन बंद, विमान गिरा... 'ब्लैक बाक्स' में एक पायलटः क्या तुमने बंद किया? दूसरा पायलटः मैंने नहीं बंद किया! फिर आई जांच रपट और बहसें दो फाड़। एक कहे कि पायलट दोषी... दूसरा कहे कि जहाज कंपनी, रखरखाव करने वाले दोषी। अब अंतिम रपट का इंतजार। अपने यहां हर कहानी आखिर ऐसे ही 'पाठ कुपाठ' में फंस जाती है। फिर, खबर कि पाक की हाकी टीम भारत नहीं आ रही..!

फिर एक दिन, बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए 'मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण' का विरोध करते एक नेता जी ने 'सूत्र' की तुक मिलाकर हास्य पैदा किया। विरोधियों को यह 'बेतुका' लगा। पूरे सप्ताह विपक्ष का नजला चुनाव आयोग के 'पुनरीक्षण अभियान' पर गिरता दिखा। विपक्ष कहता कि यह अभियान कमजोर गरीब और अल्पसंख्यकों को 'वोट से वंचित' करने की साजिश है, जो हम होने नहीं देंगे..! बहसों के बावजूद यह सवाल निरुत्तर ही रहा कि 'पुनरीक्षण' कराने की ऐसी जल्दी क्या थी?

फिर आई केरल से 'गुरु पूर्णिमा' के अवसर पर कुछ स्कूलों में 'छात्रों' द्वारा अपने गुरुजी की 'पाद पूजा' और माकपा द्वारा इस कृत्य के विरोध की खबर। वामपंथी कहिन कि ये 'सामंती संस्कृति' है।

फिर आई जलेबी और समोसे की आफत और 'फार्मास्यूटिकल कारपोरेटी' प्रभुओं द्वारा हम गरीबों के मोटापे की चिंता। भारत के 'देशज फास्ट फूड' से बढ़ते रोगों की चिंता कि कह दिए, आगे से जलेबी और समोसों के ऊपर यह लिखना होगा कि एक जलेबी और समोसे में इतने फीसद अच्छी या बुरी वसा है, इतनी चीनी, नमक, मिर्च-मसाले हैं और ये इनकी 'एक्सपायरी तारीख' है। गोरों को कौन बताए कि ये हमारे यहां ताजा-ताजा ही खाए जाते हैं, सूंघकर, चखकर खाए जाते हैं। खाने वाले जानते हैं कि जलेबी सिर्फ ताजा खाई जाती है और समोसे उतनी ही मात्रा में बनाए जाते हैं, जितने कि बिक जाएं। फिर एक ताजा जलेबी पर सामग्री में मैदा, 'वसा' और 'तारीख' आदि लिखोगे कैसे? जलेबी पर प्रिंट कैसे करोगे? जलेबी-समोसे के 'छपे हिस्से' को कैसे खाओगे? ऐसा लगता है कि हमारे स्वास्थ्य की चिंता में दुबले हुए जा रहे 'उपभोक्ता ब्रांड' बनाने वाले भूमंडलीय कारपोरेट हमें हमारे परंपरागत भोजन से वंचित कर अपनी चााकलेट, बर्गर, सैंडविच, स्टफ्ड रोल, कोक, पेप्सी, काफी आदि का उपभोक्ता बनाना चाहते हैं।

> खबरों के इस 'तुमुल कोलाहल कलह में' एक सकारात्मक खबर आई कि शुभांशु शुक्ला तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 'वापसी कैप्सूल' के जरिए सही-सलामत धरती पर उतर आए हैं। लगभग सभी चैनलों ने उनके विमान और कैप्सूल के अमेरिकी समुद्र में उतरने का सीधा प्रसारण दिखाया।

खबरों के इस 'तुमुल कोलाहल कलह में' एक सकारात्मक खबर आई कि शुभांशु शुक्ला तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 'वापसी कैप्सूल' के जरिए सही-सलामत धरती पर उतर आए हैं। लगभग सभी चैनलों ने उनके विमान और कैप्सूल के अमेरिकी समुद्र में उतरने का सीधा प्रसारण दिखाया। फिर वे सहायकों द्वारा कैप्सूल से बाहर निकाले जाते, फिर वे अपना बायां हाथ हिलाते और मुस्कुराते आगे जाते दिखे। उनके माता पिता भी भारत में उनको सकुशल वापस आते देखते चैनलों में दिखे। वे ताली बजाते और ईश्वर को धन्यवाद देते दिखे। एक चैनल पर पिता ने कहा कि यह 140 करोड़ देशवासियों का प्यार है। शुभांशु ने भी कहाः भारत सचमुच 'सारे जहां से अच्छा' दिखता है।

अपनी राजनीति भी अब पूरी तरह ईर्ष्या-द्वेष में बदल गई दिखती है। वरना भारत के विदेश मंत्री के चीन जाने और शी जिनपिंग से हाथ मिलाने पर विपक्ष परेशान न होता। इसे देख एक एंकर ने कहा कि आप शी जिनपिंग से मिलकर समझौता करें तो पुण्य और विदेश मंत्री शी जिनपिंग से मिलें तो पाप! ये कौन-सी सैद्धांतिक राजनीति है!

फिर एक किशोर ने गरीबों को गाड़ी से रौंदा..! एक बार फिर ऐसे को जमानत मिली और एंकरों व सामाजिक कार्यकर्ताओं में गुस्सा बढ़ा, लेकिन एक दूसरे मामले में महाराष्ट्र की अदालत ने लगभग छोड़ दिए गए 'किशोर' को 'बालिग' मानकर मुकदमा चलाने को कहा। कई एंकरों ने इस पर संतोष व्यक्त किया।

यों 'कांवड़ मार्ग' पर दुकानों पर 'क्यूआर कोड', 'नेमप्लेट' लगाने के आदेश पर विवाद जारी रहे और मामला सर्वोच्च अदालत पहुंचा। 'कांवड़ पक्ष' का मानना रहा कि कांवड़ियों को 'सात्विक भोजन' जरूरी है। कई 'गैर हिंदू' लोग हिंदू देवी-देवताओं के चित्र बनवाकर उनके नाम से रेस्तरां, होटल का नाम रखकर चलाते हैं। इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश प्रशासन का आदेश रहा कि दुकानदारों को 'नेमप्लेट' लगानी चाहिए, लेकिन विरोधी पक्ष कहता रहा कि यह एक समुदाय को निशाना बनाना है।

फिर एक दिन महाराष्ट्र के 'विधान भवन' में एक 'थप्पड़ लीला' दिखी। एक विपक्षी नेता ने सत्ता पक्ष के नेता के बारे में कुछ ऐसा कह दिया कि प्रतिक्रिया में थप्पड़ बरसने लगे।

संपादकीय जागरण
(10) रविवार, 20 जुलाई, 2025: श्रवण कृष्ण - 10 वि. 2082

क्रोध धन और यश, दोनों का नाश करता है

बचकानी राजनीति

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति संभवतः यह अच्छे से समझ गया होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप विचित्र दावे करते रहते हैं। वे कई बार निराधार टिप्पणियां करते हैं और फिर उनसे पीछे भी हट जाते हैं, लेकिन शायद भारत के विपक्षी दलों और विशेष रूप से कांग्रेस को ट्रंप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। ट्रंप ने यह दावा किया कि पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारत की सेना के आपरेशन सिंदूर के चलते भारत-पाकिस्तान में हुए टकराव के दौरान पांच लड़ाकू विमान मार गिराए गए। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये विमान किस देश के थे, लेकिन कांग्रेस के नेता तत्काल इस नतीजे पर पहुंच गए कि ये लड़ाकू विमान भारत के रहे होंगे। उन्होंने ट्रंप के इस बेकार के दावे की सच्चाई जानने की जरूरत जता दी। यह जरूरत कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने नहीं, बल्कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जताई। ऐसा लगता है कि उन्हें न तो भारत की सरकार पर भरोसा है और न ही भारतीय सेना पर। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस आपरेशन सिंदूर के मामले में उन अधकचरे एवं भारत विरोधी दावों को तूल दे रही है जो पाकिस्तान और चीन के नेताओं ने किए और यदाकदा अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी। सब जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दावा खोखला है कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाया और दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की आशंका को टाला। उनके इस दावे पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। खुद भारतीय प्रधानमंत्री उनसे फोन पर दोटूक यह कह चुके हैं कि कथित संघर्ष विराम में अमेरिका की वैसी कोई भूमिका बिल्कुल भी नहीं थी जिसका दावा किया जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से यह भी कहा था कि कश्मीर पर भारत की जो नीति है, वह यथावत है और उसमें कोई बदलाव होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन कांग्रेस यह समझने को तैयार नहीं। कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि कश्मीर, आपरेशन सिंदूर एवं अन्य अनेक मामलों में उनके बयानों का पाकिस्तान, चीन एवं अन्य भारत विरोधी ताकतों ने इस्तेमाल किया है और अपने पक्ष में भुनाया भी है, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जो कांग्रेस लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रही और विदेश नीति की बारीकियों से परिचित है, वह बचकाना व्यवहार कर रही है। ऐसा तो कई क्षेत्रीय दल भी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस एवं कुछ अन्य दलों के नेता इस इंतजार में बैठे दिखते हैं कि पाकिस्तान, चीन, अमेरिका अथवा किसी अन्य देश से कब भारतीय हितों के प्रतिकूल बयान आए और वे सरकार को घेरें। यह वह रवैया है जो इन नेताओं की विश्वसनीयता पर चोट भी कर रहा है।

अपराध नियंत्रण की चुनौती

गया जिले के शेरघाटी में शनिवार की सुबह अपराधियों ने एक डाक्टर को गोली मार कर घायल कर दिया। यह स्थिति ठीक नहीं है। इस तरह की घटनाएं विधि व्यवस्था पर प्रश्न उठा रही हैं। पुलिस तंत्र क्या कर रहा है। दो दिन पहले पटना में अस्पताल में बेड पर भर्ती एक कैदी की गोली मार हत्या कर दी गई थी। इससे पहले राजधानी में ही एक व्यवसायी की हत्या कर दी गई। घटना की जड़ में कई कारण हो सकते हैं, संपत्ति से लेकर विभिन्न विवाद हो सकते हैं, पर इसका अर्थ यह कतई नहीं कि कोई किसी को कहीं भी गोली मार दे। यह पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाल के दिनों में कुछ कड़ी कार्रवाई जरूर की गई है। व्यवसायी हत्याकांड में एक अपराधी एनकाउंटर में मारा भी गया है। पुलिस ने अपराधियों से मुठभेड़ में कई के पैरों में भी गोली मारी है, पर अपराध रुक नहीं रहा। इसकी गहन विवेचना कर रणनीति बनाने की जरूरत है। सुपारी किलिंग की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कम उम्र के लड़कों को इसमें शामिल किया जा रहा है। इसके पीछे कौन है। उन सरगनाओं को पकड़ना होगा। आश्चर्य तो यह है कि अपराध करने के बाद ये लोग अपनी फोटो और वीडियो तक पोस्ट करते हैं। यह कहीं न कहीं समाज में दहशत फैलाने का एक कुत्सित प्रयास है। पुलिस हर जगह नहीं रह सकती है, पर उसका निगरानी तंत्र मजबूत हो तो अपराधियों में इतनी हिम्मत नहीं कि वह क्षेत्र में उत्पात कर सके। वैसे थाना क्षेत्रों की भी समीक्षा की जरूरत है, जहां आए दिन घटनाएं हो रही हैं।

> रणनीति बना करअपराधियों के मनोबल को तोड़ना होगा, ताकि विधि-व्यवस्था बनी रहे।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या लश्कर के मुखौटा संगठन टीआरएफ को अमेरिका द्वारा आतंकी संगठन घोषित करना भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है?

आज का सवाल
क्या आइएनडीआइए से आम आदमी पार्टी का बाहर निकलना विपक्षी मोर्चे के लिए झटका है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

सुधरने का नाम नहीं ले रहा है सरकारी तंत्र

संजय गुप्त

नौकरशाही के भ्रष्टाचार ने जनता के समक्ष परेशानी पैदा करने के साथ ही देश के विकास में बाधाएं डालने का भी काम किया है

अपने देश में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी सिलसिले के बीच पिछले दिनों लखनऊ के परिवहन आयुक्त ने केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा कि कामर्शियल वाहनों को कहीं से भी फिटनेस प्रमाणपत्र लेने की जो सुविधा प्रदान की गई है, उससे अराजकता फैल रही है। उन्होंने इंगित किया कि यदि एक वाहन पुलिस के कब्जे में हो तो उसका सर्टिफिकेट कहीं और से भी मिल गया। उन्होंने गोरखपुर, कानपुर समेत सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े ऐसे मामलों का जिक्र किया। उनका सुझाव था कि फिटनेस सर्टिफिकेट देने की पुरानी व्यवस्था फिर से लागू करना ठीक होगा। ये सर्टिफिकेट क्षेत्रीय आरटीओ प्रदान करते थे। यह अपने देश में चलन बन गया है कि यदि सरकार नागरिकों को कोई सुविधा प्रदान करती है तो अनेक लोग उसका दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। इसके चलते सरकारों को नागरिकों की सहूलियत के लिए प्रदान की गई सुविधाओं अथवा सेवाओं में फेरबदल करने को मजबूर होना पड़ता है। आखिर लोगों को अपनी कामर्शियल गाड़ियों की फिटनेस सही तरीके से कराने में क्या समस्या है? यदि उनके वाहन फिट नहीं होंगे तो दुर्घटना का खतरा रहेगा और सर्विस एवं मरम्मत खर्च भी बढ़ेगा। जिस भी गाड़ी की समय पर सर्विस होती है, उसमें ईंधन की भी खपत कम होती है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतते हैं। चूंकि पहले वाहनों की फिटनेस जांच में घपले होने और पैसे देकर फर्जी सर्टिफिकेट देने के मामले सामने आते रहते थे और वाहन मालिकों को आरटीओ से फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने में कठिनाई भी होती थी, इसलिए सरकार ने एक सुविधा प्रदान की, लेकिन बात बनी नहीं। बात इसलिए नहीं बनी, क्योंकि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

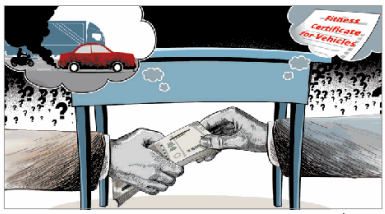

बात केवल इसकी ही नहीं है कि भ्रष्टाचार के चलते कामर्शियल वाहनों की फिटनेस के मामले में उपयोगी नियम-कानून पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति अन्य मामलों में भी है और इसका एक कारण औसत सरकारी कर्मचारियों की अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार है। यह किसी से छिपा नहीं कि आधारभूत ढांचे के निर्माण और रखरखाव से लेकर अन्य क्षेत्रों में गैरजिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के मामले सामने आते ही रहते हैं। किसी की सरकार हो, ऐसे मामले थमने का नाम नहीं लेते। इसका एक कारण तो यह है कि आजादी के बाद से ही नौकरशाही की जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। चूंकि सरकारी सेवा में आने के बाद कामचोर और भ्रष्ट लोगों की नौकरी भी मुश्किल से जाती है, इसलिए नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पा रही है। इस भ्रष्टाचार ने जनता के समक्ष परेशानी खड़ी करने के साथ देश के विकास में बाधाएं डालने का भी काम किया है। शासन-प्रशासन के कई क्षेत्रों में समय के साथ सुधार होने के बजाय पहले जैसी स्थितियां हैं और जहां तक बुनियादी ढांचे के निर्माण की बात है, वहां तो भ्रष्टाचार न पहले नियंत्रित था और न आज है। आखिर क्या कारण रहा कि मोदी सरकार ने नए संसद भवन का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी या ऐसी ही किसी अन्य एजेंसी के बजाय टाटा की कंपनी से कराया? क्या अब सरकारों को अपनी ही एजेंसियों पर भरोसा नहीं या उन्हें आभास हो गया है कि वे सुधरने वाली नहीं? आमतौर पर निजी क्षेत्र की ओर से किए जाने वाले निर्माण की गुणवत्ता अपेक्षाकृत अच्छी होती है, लेकिन सरकारी एजेंसियों की ओर से कराए जाने वाले निर्माण की गुणवत्ता सुधरने का तो नाम ही नहीं ले रही है। समस्या यह है कि निर्माण क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों वाला भ्रष्टाचार अब निजी क्षेत्र में भी देखने को मिलने लगा है।

अवधेश राजपूत

सरकारें सबसे बड़ी नियोक्ता हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रालय भी मानकों के हिसाब से काम नहीं करा पा रहे हैं। सत्ताधारी यह जानते हैं कि बुनियादी ढांचे की योजनाओं का जिस तरीके से निर्माण एवं संचालन होना चाहिए, वैसा मुश्किल से हो पा रहा है। इसके चलते ही सरकारों की ओर से कंसल्टिंग कंपनियों को विभिन्न कामों का ठेका देने का चलन बढ़ रहा है। आखिर सरकारों को कंसल्टिंग कंपनियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या शीर्ष नौकरशाह और खासकर आइएएस काबिल नहीं या फिर उनकी भर्ती प्रक्रिया सही नहीं? पिछले दिनों दिल्ली में सीवरलाइन और पेयजल पाइपलाइन के रखरखाव के लिए एक कंसल्टेंट कंपनी की सेवाएं लेने का फैसला किया गया। इसका मतलब है कि संबंधित सरकारी विभागों के इंजीनियर एवं अन्य कर्मचारी सीवर और पाइपलाइन बिछाने या उनका रखरखाव करने का साधारण सा भी काम नहीं कर पा रहे हैं। आज ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे लोग यह मानकर चल रहे हैं कि औसत सरकारी कर्मचारी आगे भी ढंग से काम नहीं करेंगे। समझना कठिन है कि केंद्र अथवा राज्य सरकारों की निर्माण अथवा सेवा प्रदान करने संबंधी जो एजेंसियां हैं, वे अपने ही मानकों के हिसाब से काम क्यों नहीं कर पा रही हैं? होना तो यह चाहिए कि कुशलता एवं कार्य की गुणवत्ता के मामले में मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम एवं अन्य सरकारी एजेंसियां निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करतीं और कोई उदाहरण पेश करतीं। इसका प्रभाव निजी क्षेत्र के साथ आम लोगों पर भी पड़ता और वे भी नियम-कानून के हिसाब से चलने की आवश्यकता समझते, लेकिन अपने देश में तो उलटी गंगा बह रही है।

फिलहाल केंद्र और राज्यों की एजेंसियों की कार्यप्रणाली में बुनियादी बदलाव एवं सुधार की जरूरी इच्छाशक्ति भी नहीं दिख रही है। नौकरशाही एक बड़ी हद तक अपने पुराने ढर्रे पर चल रही है। इसके चलते विकसित भारत का लक्ष्य कठिन होता जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री बार-बार यह कहते हैं कि उत्पादकता, गुणवत्ता एवं सेवाओं की बेहतरी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन चंद क्षेत्रों को छोड़कर उसका बहुत असर होता नहीं दिख रहा है। भारत में विकसित देशों के मानकों के अनुरूप मुश्किल से ही कुछ दिखाई देता है। यदि यही स्थिति रही तो भारत विकसित कैसे बन सकेगा? अच्छा हो कि इस पर दलगत राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर विचार किया जाए। राष्ट्र का निर्माण तो सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए-शासन की भी, प्रशासन की भी और आम लोगों की भी।

response@jagran.com

सिस्टम के जलवे की जय हो

हास्य-व्यंग्य

संतोष त्रिवेदी

> जैसे ही सिस्टम ने नए बजट की फाइल आगे बढ़ाई, वैसे ही पुल, गड्ढा एवं नाला उसकी जय-जयकार करने लगे

सिस्टम पर बहुत प्रेशर था। अब तो उसके लोग भी शिकार होने लगे थे। अगर ये नहीं बचेंगे तो फिर वह जी किसलिए रहा है। ज्यादा चिंता इस बात की थी कि फिर सिस्टम संभालेगा कौन? उसके कमजोर होने की सूचना पता नहीं कैसे लीक हो गई। यही बात उसे चुभ रही थी। यही सोचकर उसने कड़ा कदम उठाने का निश्चय किया। बिना देरी किए उसने शुरुआती तौर पर जिम्मेदार पुल, गड्ढे और नाले को अपने दरबार में तलब कर लिया।

दरबार में सबसे पहले पुल की पेशी हुई। सिस्टम ने उससे जवाब मांगा, 'क्यों जी! तुम क्यों बह गए? तुम्हें तो लोगों को पार उतारने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, फिर तुम स्वयं क्यों बहक गए और सीधे जमीन पर उतर आए?' पुल ने कहा, 'हुकुम! मेरे हाथ बंधे हुए थे। इंजीनियर साहब और ठेकेदार जी ने दिन-रात मेहनत की। उन्होंने मुझे दर्शनीय बनाया, पर लोग ही उतावले निकले। जिसे देखो, वही मेरे सीने पर दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया आदि दौड़ाने लगा। मेरी भी जमीन से जुड़ाव की उत्कंठा मन में आ गई थी जनाब। मेरा साथ देते हुए कुछ लोग भी जमीन पर आ गए। दुर्भाग्य से मैंने उन्हें नदी के बजाय वैतरणी पार करा दी। बस यही दोष है मेरा।'

सिस्टम जोर से झल्लाया, 'सिस्टम को तुमने अंधा समझा है क्या? हमें सब दिखता है। तुम मिट्टी में मिल चुके हो। तुम्हारी वजह से मुझे ऐरों-गैरों को जवाब देना पड़ रहा है। मैं नदी को भी तलब करूंगा। उसे उफान पर नियंत्रण रखना था।' इतना कहकर उसने गड्ढे का रुख किया।

बिना कुछ पूछे ही गड्ढा अपनी सफाई देने लगा, 'सरकार! मुझे यहां जबरिया लाया गया है। मैं तो राजधानी का सम्मानित गड्ढा हूं। अभी पिछले दिनों ही गाजे-बाजे के साथ मेरा अस्तित्व मिटाने की कोशिश हुई थी। वर्षा देवी ने मुझे पुनर्जीवन प्रदान कर दिया। मेरी प्रकृति ही गिरी हुई है। पहले अफसर और नेता 'गिरते' हैं, फिर लोग गिरते हैं। इस तरह सड़क बनने के साथ ही मेरा जन्म हो जाता है। राजधानी से लेकर दूर-दराज के गांवों तक मेरी पहुंच है। कई जगह तो सड़कों की पहचान ही मेरे कारण है। मुझमें जो खालीपन दिखता है, उसकी वजह है कि मैंने कइयों के पेट भरे हैं। मुझ पर लोग गिर-गिरकर मुक्ति पा रहे हैं, इसमें मेरा कुसूर क्या है? अच्छी बात यह कि अफसर, नेता और ठेकेदार को फिर से काम मिलता है। मुझे तो आपको सम्मानित करना चाहिए!'

गड्ढे के तर्क सुनकर सिस्टम ने लंबी सांस भरी। यह देखकर नाले को और घबराहट हुई। उसे लगा कि सारा दोष उसी पर मढ़ने की तैयारी है। नाले के सोच से सिस्टम का सोच अलग निकला। उसने सवाल करने के बजाय जवाब दे दिया, 'हर साल तुम्हारे रख-रखाव में करोड़ों का खर्च होता है, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। लगता है अब बजट और बढ़ाना पड़ेगा। सिस्टम एक नाले से हार मान ले, यह मंजूर नहीं।'

नाले ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, 'हुजूर, आप माई-बाप हैं। अगर बजट बढ़ा ही रहे हैं तो थोड़ा और बढ़ा लें। मुझसे बिजली और गैस दोनों बन सकती है। वैसे मैं अकेले नहीं उफनता। नदी और नाले का संयोग बहुत पुराना है। जब नदी उफनती है तो उसे नाव की सुविधा मिलती है। मेरी गुजारिश है कि मुझे भी नाव से नवाजा जाए! पानी खूब बरस रहा है, बस आपकी कृपा भी बरस जाए तो मैं धन्य हो जाऊं।'

सिस्टम की आंखें चमक उठीं। उसने नए बजट की फाइल तुरंत आगे बढ़ाने की अनुशंसा कर दी। पुल, गड्ढा और नाला सिस्टम की जय-जयकार करने लगे। यही सिस्टम का जलवा है।

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

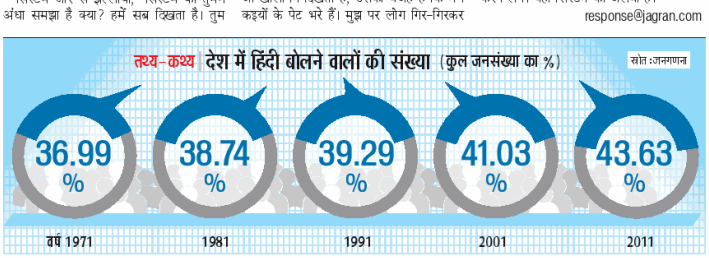

तथ्य-कथ्य | देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या (कुल जनसंख्या का %)

ऊर्जा

याचना

याचना दो प्रकार की होती है-एक निजी हित के लिए और दूसरी लोकहित के लिए। निजी हित की याचना व्यक्ति को भिखारी की श्रेणी में रखती है, क्योंकि इसमें मांगी गई वस्तु केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए होती है। इसके विपरीत लोकहित के लिए की गई याचना को उत्तम माना जाता है, क्योंकि इससे समाज के कल्याण के कार्य होते हैं।

महामना मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना के लिए धन की याचना की। कहा जाता है कि हैदराबाद के निजाम ने उन्हें दान में चप्पल दी। मालवीय जी ने उस चप्पल की नीलामी की। अंततः निजाम ने अपनी चप्पल वापस लेकर उन्हें पर्याप्त धन दिया। एक और किंवदंती है जिसमें एक शासक ने मालवीय जी को धन देने से इन्कार कर दिया। जब वे उस शासक की चौखट से बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि एक शव-यात्रा जा रही है, जिसमें पैसे लुटाए जा रहे थे। मालवीय जी ने उस पैसे को लेने का निर्णय लिया। यह खबर सुनकर उस शासक ने अपने नौकर को भेजकर मालवीय जी को बुलवाया और कहा, 'क्यों पंडित जी, आपकी असलियत तो प्रकट हो गई। आप तो मुर्दे का पैसा लूटने लगे?' इस पर मालवीय जी ने उत्तर दिया, 'धन्य है वह मुर्दा, जिसने लोकहित के लिए पैसा दिया, जबकि जिंदा ने पैसा देने से इन्कार कर दिया था।' इस उत्तर ने उस शासक को लज्जित कर दिया और उसने मालवीय जी को पर्याप्त धन दिया। वास्तव में मालवीय जी एक बड़े अभियान को लक्ष्य बनाकर याचक बने थे, जिसमें लोकहित समाहित था। उनके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय आज विश्वभर में प्रसिद्ध है।

स्पष्ट है कि याचना का अर्थ केवल मांगना नहीं, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरना भी है। लोकहित के लिए की गई याचना न केवल व्यक्तिगत, बल्कि यह समाज के उत्थान का भी माध्यम बनती है।

सलिल पांडेय

'सर' पर दांव-पेच

विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जारी विशेष मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण यानी 'सर' के फैसले को लेकर विवादों में घिरा चुनाव आयोग वैसे तो डैमेज कंट्रोल के लिए रोजाना कुछ न कुछ कवायद कर रहा है। इस पहल की मंशा पर सवाल उठाते हुए विरोध कर रहीं विपक्षी पार्टियों की सक्रियता भी कोई कम नहीं है। आयोग जैसे ही अभियान को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी करता है तो विपक्षी दल बिना देरी किए अपने तर्कों और तथ्यों के हिसाब से इसका विरोधाभास उजागर करने में देर नहीं करते। ऐसे में आयोग कई बार सूत्रों के हवाले से अनाधिकारिक तौर पर अपने दृष्टिकोण रखता है। यहां भी विपक्ष ने अपने संचार तंत्र को ऐसा चौकस रखा है कि उसे आयोग का दृष्टिकोण मालूम होने में बहुत देर नहीं लगती। कांग्रेस का इंटरनेट मीडिया विभाग आयोग के ऐसे सूत्र पर तत्काल ही निशाना साध उसे सांस नहीं लेने देता। बताया जाता है कि आयोग ने भी इसका रास्ता निकाल कर सूत्र के हवाले से खबरें जारी करने के लिए कुछ चुनिंदा भरोसेमंदों का एक समूह बना लिया है। बहरहाल इस दांव-पेच के बीच सियासी गलियारों में चर्चा गरम है कि आयोग और विपक्ष में 'सर' पर जारी घमासान की अंतिम दिशा सुप्रीम कोर्ट में तय होगी, मगर चुनाव से पहले महागठबंधन की जमीनी सक्रियता नई छलांग मार रही है।

राजरंग

ट्रेड डील पर सस्पेंस!

वाणिज्य मंत्रालय के गलियारों में सबसे अधिक चर्चा भारत-अमेरिका ट्रेड डील की है। इसमें भी खास सरगर्मी इसे लेकर है कि आखिर इस डील की घोषणा कौन करेगा। अमूमन ऐसी घोषणाएं दोनों देशों के मंत्रियों या प्रतिनिधियों की साझा मौजूदगी में होती हैं, लेकिन जिस अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अन्य देशों के साथ एकतरफा डील की घोषणा कर रहे हैं, उसे देखते हुए भारत से संबंधित डील को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर सरकार के मंत्रियों तक ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि इशारों-इशारों में संकेत दे रहे हैं कि उन्हें भी यह पता नहीं है कि इस ट्रेड डील की घोषणा कब होगी। रोचक यह है कि वे भी हर वक्त ट्रंप के इंटरनेट मीडिया हैंडल को चेक करते रहते हैं कि कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से डील का एलान तो नहीं कर दिया। इन संकेतों से साफ है कि भारतीय वार्ताकार भी लगभग मान बैठे हैं कि ट्रेड डील की अंतिम खबर तो शायद ट्रंप से ही मिलेगी।

समझो इशारा

सुप्रीम कोर्ट सिर्फ लोगों के मुकदमे सुनकर न्याय ही नहीं देता, बल्कि कई बार जूनियर वकीलों को वकालत के गुर भी सिखाता है। कुछ ऐसा ही वाकया पिछले दिनों देखने को मिला। एक अदालत में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। एक जूनियर वकील ने स्थगन मांगते हुए कहा कि 'इस मामले की सुनवाई फिलहाल टाल दी जाए, क्योंकि इस मामले में मेरे वरिष्ठ बहस करेंगे।' न्यायाधीश ने बहस के लिए जूनियर वकील को प्रोत्साहित किया, मगर वह स्थगन की मांग पर कायम रहा। दो वर्ष से वकालत कर रहे नए वकील से पीठ ने कहा कि 'उन्हें कोर्ट का इशारा समझना चाहिए। भले चैंबर में वरिष्ठ वकील आपके बास हैं, लेकिन कोर्ट में हम बास हैं और कह रहे हैं कि बहस नहीं करेंगे तो केस खारिज कर देंगे।' बहरहाल वकील के नौसिखियापन को देखते हुए न्यायाधीश ने पहली बार में नरमी बरती, मगर भविष्य के लिए इशारा साफ कर दिया।

पवार और उद्धव पर नजर

आम आदमी पार्टी के आइएनडीआइए से बाहर होने के एलान के बाद संसद में राकांपा (शरद पवार गुट) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) पर नजर रहेगी। चाचा-भतीजे के बीच कम होती दूरी और परिवार के एकजुट होने के संकेत के बाद माना जा रहा है कि शरद पवार गुट शायद मोदी सरकार पर पहले की तरह हमलावर न दिखे। आपरेशन सिंदूर पर पहले ही शरद पवार संसद में बहस नहीं किए जाने का तर्क दे चुके हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में नई सियासी खिचड़ी पकने की अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसे में हर मुद्दे पर मोदी सरकार पर तीखा हमला करने वाले संजय राउत के तेवर ढीले दिखें तो आश्चर्य नहीं।

X पोस्ट

ब्रिटेन में 16 साल की उम्र से युवा वोट डाल सकेंगे। सरकार संसद में प्रस्ताव ला रही है। अभी 18 साल की सीमा है। सरकार का तर्क है कि 16 साल की उम्र से आप काम कर सकते हैं। टैक्स चुकाते हैं तो वोट क्यों नहीं डालें? संभव है कल भारत में भी कुछ लोग इसकी मांग करें। मिलिंद खांडेकर@milindkhandekar

आम आदमी पार्टी का आइएनडीआइए से बाहर निकलना उसकी अदूरदर्शिता और अवसरवाद की राजनीति का ही प्रतीक है।

आशुतोष@ashutosh83B

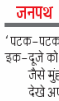

डोनाल्ड ट्रंप का यह कहते रहना कि व्यापार का डर दिखाकर उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम करा दिया तो फिर अभी तक भारत के साथ अमेरिका का व्यापार समझौता क्यों नहीं हो पाया? बार-बार यही राग अलापने का मतलब है कि वह भारत पर इसके लिए दबाव डालना चाहते हैं। अमेरिका को बखूबी पता है कि पाकिस्तान के साथ तो ऐसी कोई संभावना नहीं, क्योंकि वह तो केवल आतंक के मामले में ही अव्वल है।

प्रियंका चतुर्वेदी@priyankac19

जनपथ

'पटक-पटक' के बाद अब 'डुबो-डुबो' का दौर,
इक-दूजे को मारना जैसे मुंह का कौर।
जैसे मुंह का कौर रखें क्या इनसे आशा,
देखे अपना देश राजनेता की भाषा!
सही समय पर लोग इन्हें देते हैं झटके,
ईवीएम पर जाय मारते 'पटक-पटक' के!!
- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 99

****

दैनिक जागरण

क्रोध धन और यश, दोनों का नाश करता है

बचकानी राजनीति

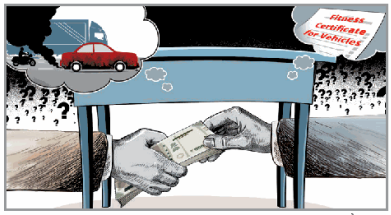

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति संभवतः यह अच्छे से समझ गया होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप विचित्र दावे करते रहते हैं। वे कई बार निराधार टिप्पणियां करते हैं और फिर उनसे पीछे भी हट जाते हैं, लेकिन शायद भारत के विपक्षी दलों और विशेष रूप से कांग्रेस को ट्रंप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। ट्रंप ने यह दावा किया कि पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारत की सेना के आपरेशन सिंदूर के चलते भारत-पाकिस्तान में हुए टकराव के दौरान पांच लड़ाकू विमान मार गिराए गए। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये विमान किस देश के थे, लेकिन कांग्रेस के नेता तत्काल इस नतीजे पर पहुंच गए कि ये लड़ाकू विमान भारत के रहे होंगे। उन्होंने ट्रंप के इस बेकार के दावे की सच्चाई जानने की जरूरत जता दी। यह जरूरत कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने नहीं, बल्कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जताई। ऐसा लगता है कि उन्हें न तो भारत की सरकार पर भरोसा है और न ही भारतीय सेना पर। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस आपरेशन सिंदूर के मामले में उन अधकचरे एवं भारत विरोधी दावों को तूल दे रही है जो पाकिस्तान और चीन के नेताओं ने किए और यदाकदा अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी।

सब जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दावा खोखला है कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाया और दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की आशंका को टाला। उनके इस दावे पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। खुद भारतीय प्रधानमंत्री उनसे फोन पर दोटूक यह कह चुके हैं कि कथित संघर्ष विराम में अमेरिका की वैसी कोई भूमिका बिल्कुल भी नहीं थी जिसका दावा किया जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से यह भी कहा था कि कश्मीर पर भारत की जो नीति है, वह यथावत है और उसमें कोई बदलाव होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन कांग्रेस यह समझने को तैयार नहीं। कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि कश्मीर, आपरेशन सिंदूर एवं अन्य अनेक मामलों में उनके बयानों का पाकिस्तान, चीन एवं अन्य भारत विरोधी ताकतों ने इस्तेमाल किया है और अपने पक्ष में भुनाया भी है, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जो कांग्रेस लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रही और विदेश नीति की बारीकियों से परिचित है, वह बचकाना व्यवहार कर रही है। ऐसा तो कई क्षेत्रीय दल भी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस एवं कुछ अन्य दलों के नेता इस इंतजार में बैठे दिखते हैं कि पाकिस्तान, चीन, अमेरिका अथवा किसी अन्य देश से कब भारतीय हितों के प्रतिकूल बयान आए और वे सरकार को घेरें। यह वह रवैया है जो इन नेताओं की विश्वसनीयता पर चोट भी कर रहा है।

भविष्य की बने रणनीति

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में झारखंड ने साफ-सफाई के मामले में देश में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। जमशेदपुर ने तीन से दस लाख आबादी वाले शहरों में तृतीय स्थान हासिल किया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सम्मानित किया। वहीं, बुंडू को प्रामिसिंग स्वच्छ शहर का खिताब मिला। यह राज्य सरकार के दिशा-निर्देश और स्वच्छता कर्मियों की मेहनत का परिणाम है। 2016 में झारखंड की स्थिति चिंताजनक थी, लेकिन 2017 से निरंतर सुधार के साथ राज्य ने स्वच्छता के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। जमशेदपुर को फाइव स्टार रैंकिंग और कई शहरों को ओडीएफ डबल प्लस श्रेणी प्राप्त हुई है। यह उपलब्धि सामुदायिक सहभागिता, प्रभावी कचरा प्रबंधन और जागरूकता अभियानों का नतीजा है। हालांकि राजधानी रांची का स्वच्छता रैंकिंग में लगातार निचले पायदान पर खिसकना चिंताजनक है। भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए कुछ रणनीति जरूरी हैं। सबसे पहले, कचरे के स्रोत का पृथक्करण बढ़ाने की जरूरत है, जो वर्तमान में कई शहरों में कमजोर है। इसके लिए स्कूलों और समुदायों में जागरूकता अभियान चलाए जाएं। दूसरा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल (ट्रिपल आर) थीम को अपनाते हुए एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करने और कंपोस्टिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है। साफ-सफाई का स्वास्थ्य से भी सीधा संबंध है। जहां स्वच्छता होती है वहां लोगों को कम बीमारियां होती हैं।

समावेशी स्वच्छता पर ध्यान देना होगा, जिसमें महिलाओं, बुजुर्गों, और दिव्यांगों के लिए सुलभ शौचालयों का निर्माण शामिल है

सुधरने का नाम नहीं ले रहा है सरकारी तंत्र

संजय गुप्त

नौकरशाही के भ्रष्टाचार ने जनता के समक्ष परेशानी पैदा करने के साथ ही देश के विकास में बाधाएं डालने का भी काम किया है

अवधेश राजपूत

अपने देश में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी सिलसिले के बीच पिछले दिनों लखनऊ के परिवहन आयुक्त ने केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा कि कामर्शियल वाहनों को कहीं से भी फिटनेस प्रमाणपत्र लेने की जो सुविधा प्रदान की गई है, उससे अराजकता फैल रही है। उन्होंने इंगित किया कि यदि एक वाहन पुलिस के कब्जे में हो तो उसका सर्टिफिकेट कहीं और से भी मिल गया। उन्होंने गोरखपुर, कानपुर समेत सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े ऐसे मामलों का जिक्र किया। उनका सुझाव था कि फिटनेस सर्टिफिकेट देने की पुरानी व्यवस्था फिर से लागू करना ठीक होगा। ये सर्टिफिकेट क्षेत्रीय आरटीओ प्रदान करते थे। यह अपने देश में चलन बन गया है कि यदि सरकार नागरिकों को कोई सुविधा प्रदान करती है तो अनेक लोग उसका दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। इसके चलते सरकारों को नागरिकों की सहूलियत के लिए प्रदान की गई सुविधाओं अथवा सेवाओं में फेरबदल करने को मजबूर होना पड़ता है। आखिर लोगों को अपनी कामर्शियल गाड़ियों की फिटनेस सही तरीके से कराने में क्या समस्या है? यदि उनके वाहन फिट नहीं होंगे तो दुर्घटना का खतरा रहेगा और सर्विस एवं मरम्मत खर्च भी बढ़ेगा। जिस भी गाड़ी की समय पर सर्विस होती है, उसमें ईंधन की भी खपत कम होती है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतते हैं। चूंकि पहले वाहनों की फिटनेस जांच में घपले होने और पैसे देकर फर्जी सर्टिफिकेट देने के मामले सामने आते रहते थे और वाहन मालिकों को आरटीओ से फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने में कठिनाई भी होती थी, इसलिए सरकार ने एक सुविधा प्रदान की, लेकिन बात बनी नहीं। बात इसलिए नहीं बनी, क्योंकि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

बात केवल इसकी ही नहीं है कि भ्रष्टाचार के चलते कामर्शियल वाहनों की फिटनेस के मामले में उपयोगी नियम-कानून पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति अन्य मामलों में भी है और इसका एक कारण औसत सरकारी कर्मचारियों की अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार है। यह किसी से छिपा नहीं कि आधारभूत ढांचे के निर्माण और रखरखाव से लेकर अन्य क्षेत्रों में गैरजिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के मामले सामने आते ही रहते हैं। किसी की सरकार हो, ऐसे मामले थमने का नाम नहीं लेते। इसका एक कारण तो यह है कि आजादी के बाद से ही नौकरशाही की जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। चूंकि सरकारी सेवा में आने के बाद कामचोर और भ्रष्ट लोगों की नौकरी भी मुश्किल से जाती है, इसलिए नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पा रही है। इस भ्रष्टाचार ने जनता के समक्ष परेशानी खड़ी करने के साथ देश के विकास में बाधाएं डालने का भी काम किया है। शासन-प्रशासन के कई क्षेत्रों में समय के साथ सुधार होने के बजाय पहले जैसी स्थितियां हैं और जहां तक बुनियादी ढांचे के निर्माण की बात है, वहां तो भ्रष्टाचार न पहले नियंत्रित था और न आज है। आखिर क्या कारण रहा कि मोदी सरकार ने नए संसद भवन का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी या ऐसी ही किसी अन्य एजेंसी के बजाय टाटा की कंपनी से कराया? क्या अब सरकारों को अपनी ही एजेंसियों पर भरोसा नहीं या उन्हें आभास हो गया है कि वे सुधरने वाली नहीं? आमतौर पर निजी क्षेत्र की ओर से किए जाने वाले निर्माण की गुणवत्ता अपेक्षाकृत अच्छी होती है, लेकिन सरकारी एजेंसियों की ओर से कराए जाने वाले निर्माण की गुणवत्ता सुधरने का तो नाम ही नहीं ले रही है। समस्या यह है कि निर्माण क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों वाला भ्रष्टाचार अब निजी क्षेत्र में भी देखने को मिलने लगा है।

सरकारें सबसे बड़ी नियोक्ता हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रालय भी मानकों के हिसाब से काम नहीं करा पा रहे हैं। सत्ताधारी यह जानते हैं कि बुनियादी ढांचे की योजनाओं का जिस तरीके से निर्माण एवं संचालन होना चाहिए, वैसा मुश्किल से हो पा रहा है। इसके चलते ही सरकारों की ओर से कंसल्टिंग कंपनियों को विभिन्न कामों का ठेका देने का चलन बढ़ रहा है। आखिर सरकारों को कंसल्टिंग कंपनियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या शीर्ष नौकरशाह और खासकर आइएएस काबिल नहीं या फिर उनकी भर्ती प्रक्रिया सही नहीं? पिछले दिनों दिल्ली में सीवरलाइन और पेयजल पाइपलाइन के रखरखाव के लिए एक कंसल्टेंट कंपनी की सेवाएं लेने का फैसला किया गया। इसका मतलब है कि संबंधित सरकारी विभागों के इंजीनियर एवं अन्य कर्मचारी सीवर और पाइपलाइन बिछाने या उनका रखरखाव करने का साधारण सा भी काम नहीं कर पा रहे हैं। आज ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे लोग यह मानकर चल रहे हैं कि औसत सरकारी कर्मचारी आगे भी ढंग से काम नहीं करेंगे। समझना कठिन है कि केंद्र अथवा राज्य सरकारों की निर्माण अथवा सेवा प्रदान करने संबंधी जो एजेंसियां हैं, वे अपने ही मानकों के हिसाब से काम क्यों नहीं कर पा रही हैं? होना तो यह चाहिए कि कुशलता एवं कार्य की गुणवत्ता के मामले में मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम एवं अन्य सरकारी एजेंसियां निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करतीं और कोई उदाहरण पेश करतीं। इसका प्रभाव निजी क्षेत्र के साथ आम लोगों पर भी पड़ता और वे भी नियम-कानून के हिसाब से चलने की आवश्यकता समझते, लेकिन अपने देश में तो उलटी गंगा बह रही है।

फिलहाल केंद्र और राज्यों की एजेंसियों की कार्यप्रणाली में बुनियादी बदलाव एवं सुधार की जरूरी इच्छाशक्ति भी नहीं दिख रही है। नौकरशाही एक बड़ी हद तक अपने पुराने ढर्रे पर चल रही है। इसके चलते विकसित भारत का लक्ष्य कठिन होता जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री बार-बार यह कहते हैं कि उत्पादकता, गुणवत्ता एवं सेवाओं की बेहतरी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन चंद क्षेत्रों को छोड़कर उसका बहुत असर होता नहीं दिख रहा है। भारत में विकसित देशों के मानकों के अनुरूप मुश्किल से ही कुछ दिखाई देता है। यदि यही स्थिति रही तो भारत विकसित कैसे बन सकेगा? अच्छा हो कि इस पर दलगत राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर विचार किया जाए। राष्ट्र का निर्माण तो सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए-शासन की भी, प्रशासन की भी और आम लोगों की भी।

response@jagran.com

सिस्टम के जलवे की जय हो

हास्य-व्यंग्य

संतोष त्रिवेदी

जैसे ही सिस्टम ने नए बजट की फाइल आगे बढ़ाई, वैसे ही पुल, गड्ढा एवं नाला उसकी जयकार करने लगे

सिस्टम पर बहुत प्रेशर था। अब तो उसके लोग भी शिकार होने लगे थे। अगर ये नहीं बचेंगे तो फिर वह जी किसलिए रहा है। ज्यादा चिंता इस बात की थी कि फिर सिस्टम संभालेगा कौन? उसके कमजोर होने की सूचना पता नहीं कैसे लीक हो गई। यही बात उसे चुभ रही थी। यही सोचकर उसने कड़ा कदम उठाने का निश्चय किया। बिना देरी किए उसने शुरुआती तौर पर जिम्मेदार पुल, गड्ढे और नाले को अपने दरबार में तलब कर लिया।

दरबार में सबसे पहले पुल की पेशी हुई। सिस्टम ने उससे जवाब मांगा, 'क्यों जी! तुम क्यों बह गए? तुम्हें तो लोगों को पार उतारने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, फिर तुम स्वयं क्यों बहक गए और सीधे जमीन पर उतर आए?' पुल ने कहा, 'हुकुम! मेरे हाथ बंधे हुए थे। इंजीनियर साहब और ठेकेदार जी ने दिन-रात मेहनत की। उन्होंने मुझे दर्शनीय बनाया, पर लोग ही उतावले निकले। जिसे देखो, वही मेरे सीने पर दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया आदि दौड़ाने लगा। मेरी भी जमीन से जुड़ाव की उत्कंठा मन में आ गई थी जनाब। मेरा साथ देते हुए कुछ लोग भी जमीन पर आ गए। दुर्भाग्य से मैंने उन्हें नदी के बजाय वैतरणी पार करा दी। बस यही दोष है मेरा।' सिस्टम जोर से झल्लाया, 'सिस्टम को तुमने अंधा समझा है क्या? हमें सब दिखता है। तुम मिट्टी में मिल चुके हो। तुम्हारी वजह से मुझे ऐरों-गैरों को जवाब देना पड़ रहा है। मैं नदी को भी तलब करूंगा। उसे उफान पर नियंत्रण रखना था।' इतना कहकर उसने गड्ढे का रुख किया।

बिना कुछ पूछे ही गड्ढा अपनी सफाई देने लगा, 'सरकार! मुझे यहां जबरिया लाया गया है। मैं तो राजधानी का सम्मानित गड्ढा हूं। अभी पिछले दिनों ही गाजे-बाजे के साथ मेरा अस्तित्व मिटाने की कोशिश हुई थी। वर्षा देवी ने मुझे पुनर्जीवन प्रदान कर दिया। मेरी प्रकृति ही गिरी हुई है। पहले अफसर और नेता 'गिरते' हैं, फिर लोग गिरते हैं। इस तरह सड़क बनने के साथ ही मेरा जन्म हो जाता है। राजधानी से लेकर दूर-दराज के गांवों तक मेरी पहुंच है। कई जगह तो सड़कों की पहचान ही मेरे कारण है। मुझमें जो खालीपन दिखता है, उसकी वजह है कि मैंने कइयों के पेट भरे हैं। मुझ पर लोग गिर-गिरकर मुक्ति पा रहे हैं, इसमें मेरा कुसूर क्या है? अच्छी बात यह कि अफसर, नेता और ठेकेदार को फिर से काम मिलता है। मुझे तो आपको सम्मानित करना चाहिए!'

गड्ढे के तर्क सुनकर सिस्टम ने लंबी सांस भरी। यह देखकर नाले को और घबराहट हुई। उसे लगा कि सारा दोष उसी पर मढ़ने की तैयारी है। नाले के सोच से सिस्टम का सोच अलग निकला। उसने सवाल करने के बजाय जवाब दे दिया, '[illegible] तुम्हारे रख-रखाव में करोड़ों का खर्च होता है, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। लगता है अब बजट और बढ़ाना पड़ेगा। सिस्टम एक नाले से हार मान ले, यह मंजूर नहीं।' नाले ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, 'हुजूर, आप माई-बाप हैं। अगर बजट बढ़ा ही रहे हैं तो थोड़ा और बढ़ा लें। मुझसे बिजली और गैस दोनों बन सकती हैं। वैसे मैं अकेले नहीं उफनता। नदी और नाले का संयोग बहुत पुराना है। जब नदी उफनती है तो उसे नाव की सुविधा मिलती है। मेरी गुजारिश है कि मुझे भी नाव से नवाजा जाए! पानी खूब बरस रहा है, बस आपकी कृपा भी बरस जाए तो मैं धन्य हो जाऊं।'

सिस्टम की आंखें चमक उठीं। उसने नए बजट की फाइल तुरंत आगे बढ़ाने की अनुशंसा कर दी। पुल, गड्ढा और नाला सिस्टम की जय-जयकार करने लगे। यही सिस्टम का जलवा है।

response@jagran.com

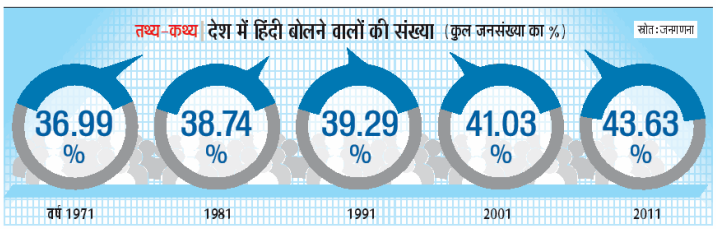

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

ऊर्जा

याचना

याचना दो प्रकार की होती है-एक निजी हित के लिए और दूसरी लोकहित के लिए। निजी हित की याचना व्यक्ति को भिखारी की श्रेणी में रखती है, क्योंकि [illegible] लिए होती है। इसके विपरीत लोकहित के लिए की गई याचना को उत्तम माना जाता है, क्योंकि इससे समाज के कल्याण के कार्य होते हैं।

महामना मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना के लिए कई बड़े घरानों से धन देने की याचना की। कहा जाता है कि हैदराबाद के निजाम ने उन्हें दान में चप्पल दी। मालवीय जी ने उस चप्पल की नीलामी की। अंततः निजाम ने अपनी चप्पल वापस लेकर उन्हें पर्याप्त धन दिया। एक और किंवदंती है जिसमें एक शासक ने मालवीय जी को धन देने से इन्कार कर दिया। जब वे उस शासक की चौखट से बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि एक शव-यात्रा जा रही है, जिसमें पैसे लुटाए जा रहे थे। मालवीय जी ने उस पैसे को लेने का निर्णय लिया। यह खबर सुनकर उस शासक ने अपने नौकर को भेजकर मालवीय जी को बुलवाया और कहा, 'क्यों पंडित जी, आपकी असलियत तो प्रकट हो गई। आप तो मुर्दे का पैसा लूटने लगे?' इस पर मालवीय जी ने उत्तर दिया, 'धन्य है वह मुर्दा, जिसने लोकहित के लिए पैसा दिया, जबकि जिंदा ने पैसा देने से इन्कार कर दिया था।' इस उत्तर ने उस शासक को लज्जित कर दिया और उसने मालवीय जी को पर्याप्त धन दिया। वास्तव में मालवीय जी एक बड़े अभियान को लक्ष्य बनाकर याचक बने थे, जिसमें लोकहित समाहित था। उनके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय आज विश्वभर में प्रसिद्ध है। याचना का अर्थ केवल मांगना नहीं, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरना भी है। लोकहित के लिए की गई याचना न केवल व्यक्तिगत, बल्कि यह समाज के उत्थान का भी माध्यम बनती है।

सलिल पांडेय

खाद्य अपशिष्ट से प्लास्टिक का निर्माण

मुकुल व्यास

विज्ञानियों ने बर्बाद भोजन का उपयोग कर कुदरती तौर पर नष्ट होने वाली प्लास्टिक बनाने में सफलता प्राप्त की है

हर वर्ष विश्व में लगभग 1.05 अरब टन भोजन बर्बाद होता है, जो उपभोक्ता स्तर पर उपलब्ध कुल भोजन का लगभग 17 प्रतिशत है। इस बर्बादी के गंभीर आर्थिक और पर्यावरणीय परिणाम होते हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को सालाना लगभग एक लाख करोड़ डालर का नुकसान होता है और यह वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 8-10 प्रतिशत का योगदान करता है। बर्बाद भोजन का अधिकांश हिस्सा लैंडफिल में चला जाता है, जहां यह सड़कर मीथेन और कार्बन डाइआक्साइड छोड़ता है। खाद्य अपशिष्ट की समस्या के साथ-साथ दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण से भी जूझ रही है। प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां और फिल्म सूक्ष्म प्लास्टिक कणों में बदल जाती हैं, जो जल, मिट्टी और अंततः हमारे शरीर में समा जाते हैं। इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए अमेरिका के बिंगहैमटन विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने यह दर्शाया है कि बर्बाद भोजन का उपयोग कुदरती तौर पर नष्ट होने वाली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए किया जा सकता है। हम खाद्य अपशिष्ट को एक संसाधन के रूप में उपयोग करके कई उत्पादों में बदल सकते हैं।

शोधकर्ताओं का लक्ष्य न केवल खाद्य अपशिष्ट का मूल्यवर्धन करना है, बल्कि पर्यावरण-अनुकूल पालीमर की निर्माण लागत को भी कम करना है। इससे जैव ईंधन और जैव रसायन भी बना सकते हैं। आधुनिक समय में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाना महंगा है। उत्पादक आमतौर पर परिष्कृत चीनी फीडस्टाक से शुरुआत करते हैं और सूक्ष्मजीवों को उगाते हैं, जिससे लागत बढ़ती है और उत्पादन के पैमाने में कमी आती है। शोधकर्ताओं ने खाद्य अपशिष्ट का किण्वन कर लैक्टिक एसिड बनाया और नाइट्रोजन के लिए अमोनियम सल्फेट मिलाया। इस प्रक्रिया में बने सूप को क्यूप्रियाविडस नेकेटर नामक जीवाणु को दिया गया, जो पालीहाइड्राक्सीएल्कानोएट (पीएचए) के रूप में कार्बन जमा करने के लिए जाना जाता है। शोधकर्ता सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादित लगभग 90 प्रतिशत पीएचए को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और उसे फिल्म, पैकेजिंग या सांचे में ढाल सकते हैं, जो सही परिस्थितियों में बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों के किण्वन से ठोस पदार्थों के साथ-साथ अम्ल भी उत्पन्न होते हैं। शोधकर्ता बचे हुए पेस्ट को एक जैविक उर्वरक के रूप में भी विकसित कर रहे हैं।

प्रयोगशाला के परिणाम आशाजनक हैं। शोधार्थियों का अगला लक्ष्य इस प्रक्रिया को तेज करना और यह सुनिश्चित करना है कि बड़े रिएक्टरों और विविध खाद्य अपशिष्टों का इस्तेमाल करते समय उपज, लागत और उत्पाद की गुणवत्ता स्थिर रहे। बिंगहैमटन की टीम अतिरिक्त अनुदान जुटाएगी या उद्योग भागीदार की तलाश करेगी, जो कैफेटेरिया के अपशिष्ट को उपयोगी उत्पाद में बदल सके।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

'सर' पर दांव-पेच

विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जारी विशेष मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण यानी 'सर' के फैसले को लेकर विवादों में घिरा चुनाव आयोग वैसे तो डैमेज कंट्रोल के लिए रोजाना कुछ न कुछ कवायद कर रहा है। इस पहल की मंशा पर सवाल उठाते हुए विरोध कर रहीं विपक्षी पार्टियों की सक्रियता भी कोई कम नहीं है। आयोग जैसे ही अभियान को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी करता है तो विपक्षी दल बिना देरी किए अपने तर्कों और तथ्यों के हिसाब से इसका विरोधाभास उजागर करने में देर नहीं करते। ऐसे में आयोग कई बार सूत्रों के हवाले से अनाधिकारिक तौर पर अपने दृष्टिकोण रखता है। यहां भी विपक्ष ने अपने संचार तंत्र को ऐसा चौकस रखा है कि उसे आयोग का दृष्टिकोण मालूम होने में बहुत देर नहीं लगती। कांग्रेस का इंटरनेट मीडिया विभाग आयोग के ऐसे सूत्र पर तत्काल ही निशाना साध उसे सांस नहीं लेने देता। बताया जाता है कि आयोग ने भी इसका रास्ता निकाल कर सूत्र के हवाले से खबरें जारी करने के लिए कुछ चुनिंदा भरोसेमंदों का एक समूह बना लिया है। बहरहाल इस दांव-पेच के बीच सियासी गलियारों में चर्चा गरम है कि आयोग और विपक्ष में 'सर' पर जारी घमासान की अंतिम दिशा सुप्रीम कोर्ट में तय होगी, मगर चुनाव से पहले महागठबंधन की जमीनी सक्रियता नई छलांग मार रही है।

राजरंग

ट्रेड डील पर सस्पेंस!

वाणिज्य मंत्रालय के गलियारों में सबसे अधिक चर्चा भारत-अमेरिका ट्रेड डील की है। इसमें भी खास सरगर्मी इसे लेकर है कि आखिर इस डील की घोषणा कौन करेगा। अमूमन ऐसी घोषणाएं दोनों देशों के मंत्रियों या प्रतिनिधियों की साझा मौजूदगी में होती हैं, लेकिन जिस अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अन्य देशों के साथ एकतरफा डील की घोषणा कर रहे हैं, उसे देखते हुए भारत से संबंधित डील को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर सरकार के मंत्रियों तक ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि इशारों-इशारों में संकेत दे रहे हैं कि उन्हें भी यह पता नहीं है कि इस ट्रेड डील की घोषणा कब होगी। रोचक यह है कि वे भी हर वक्त ट्रंप के इंटरनेट मीडिया हैंडल को चेक करते रहते हैं कि कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से डील का एलान तो नहीं कर दिया। इन संकेतों से साफ है कि भारतीय वार्ताकार भी लगभग मान बैठे हैं कि ट्रेड डील की अंतिम खबर तो शायद ट्रंप से ही मिलेगी।

समझो इशारा

सुप्रीम कोर्ट सिर्फ लोगों के मुकदमे सुनकर न्याय ही नहीं देता, बल्कि कई बार जूनियर वकीलों को वकालत के गुर भी सिखाता है। कुछ ऐसा ही वाकया पिछले दिनों देखने को मिला। एक अदालत में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। एक जूनियर वकील ने स्थगन मांगते हुए कहा कि 'इस मामले की सुनवाई फिलहाल टाल दी जाए, क्योंकि इस मामले में मेरे वरिष्ठ बहस करेंगे।' न्यायाधीश ने बहस के लिए जूनियर वकील को प्रोत्साहित किया, मगर वह स्थगन की मांग पर कायम रहा। नए वकील से पीठ ने कहा कि 'उन्हें कोर्ट का इशारा समझना चाहिए। भले चैंबर में वरिष्ठ वकील आपके बास हैं, लेकिन कोर्ट में हम बास हैं और कह रहे हैं कि बहस नहीं करेंगे तो केस खारिज कर देंगे।' बहरहाल वकील के नौसिखियापन को देखते हुए न्यायाधीश ने पहली बार में नरमी बरती, मगर भविष्य के लिए इशारा साफ कर दिया।

पवार और उद्धव पर नजर

आम आदमी पार्टी के आइएनडीआइए से बाहर होने के एलान के बाद संसद में राकांपा (शरद पवार गुट) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) पर नजर रहेगी। चाचा-भतीजे के बीच कम होती दूरी और परिवार के एकजुट होने के संकेत के बाद माना जा रहा है कि शरद पवार गुट शायद मोदी सरकार पर पहले की तरह हमलावर न दिखे। आपरेशन सिंदूर पर पहले ही शरद पवार संसद में बहस नहीं किए जाने का तर्क दे चुके हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में नई सियासी खिचड़ी पकने की अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसे में हर मुद्दे पर मोदी सरकार पर तीखा हमला करने वाले संजय राउत के तेवर ढीले दिखें तो आश्चर्य नहीं।

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

एक्स से

भाषा संवाद का विषय है, विवाद का नहीं। भारत तो इतना परिपक्व और अद्भुत देश है कि इसने सभी को स्वीकार किया है। भारत हमेशा संवाद में विश्वास रखता है, विवाद में नहीं- आशुतोष राणा/अभिनेता

माननीय, कृपया ध्यान दें

मामला 'इन' या 'उन' का नहीं है। एक अवांछित परंपरा जब-तब संसद को 'मत्स्य न्याय' का शिकार बनाती रहती है, जबकि जरा-सा सामंजस्य बहुत कुछ करा सकता है। माननीय सदस्यों को आज उनके दायित्वों का ध्यान दिलाना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि संसद का पावसकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है।

आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

शशि शेखर

आजकल

इस कॉलम के सभी शब्द देश के उन माननीय सांसदों को समर्पित हैं, जिन्हें उनके मतदाताओं ने प्यार और सम्मान के साथ चुना है। वे यकीनन संसद सदस्य कहलाने का गौरव रखते हैं, पर उन्हें हर क्षण याद रखना चाहिए कि यह संसद देश के आम आदमी की धरोहर है। इस नाते उन पर आम आदमी की आकांक्षाओं और उसकी हित-रक्षा की जिम्मेदारी है।

क्या वे इस महत्वपूर्ण दायित्व का पालन कर रहे हैं?

ऐसा लगता है, जैसे सड़कों पर उपजी कड़वाहट संसद में कब्जा जमाकर बैठ गई है। भरोसा न हो, तो इस आंकड़े पर नजर डाल देखिए। पिछली, यानी 17वीं लोकसभा में सिर्फ 1,354 घंटे काम हुए। इसके 15 में 11 सत्र समय से पहले अवसान के शिकार बने। उस दौरान लोकसभा में 222 विधेयक पारित हुए, जिनमें से मात्र 16 प्रतिशत स्थायी समिति के पास गए। पहली लोकसभा में साल में 135 दिन सदन जुटता था, जबकि 17वीं लोकसभा में औसतन 55 दिन ही काम हो सका।

17वीं लोकसभा एक और वजह से चर्चा में रही। इस दौरान विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में एक राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस की बेहद तेजतर्रार महुआ मोइत्रा सहित छह सांसदों की सदस्यता कुछ कारणों से रद्द कर दी गई। हालांकि, महुआ के अलावा सभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लोकसभा में लौट आए। यही नहीं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों से कुल जमा 146 सदस्यों की सदस्यता 'कई वजहों' से निलंबित कर दी गई। इस दौरान विपक्ष का आरोप था कि जिन पर सदन चलाने की जिम्मेदारी है, वे ही सांसदों की आवाज का गला घोंट रहे हैं।

यह सिलसिला पुराना है।

जनवरी 1985 में राजीव गांधी 404 सीटों के तूफानी बहुमत के साथ साउथ ब्लॉक में दाखिल हुए थे। उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए ठक्कर आयोग का गठन किया था। उस आयोग की जांच रिपोर्ट आज तक पूर्ण रूप से सार्वजनिक नहीं की गई है। विपक्षी सांसदों ने उस वक्त आयोग के निष्कर्ष सार्वजनिक करने के लिए जबरदस्त तरीके से आवाज उठाई थी। बदले में लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने 63 सांसदों को निलंबित कर दिया था। मीडिया और सामाजिक विमर्श में हो-हल्ला मचता देख निलंबन तो अगले दिन वापस ले लिया गया, लेकिन संख्या बल के 'दुरुपयोग' की प्रवृत्ति जन्म ले चुकी थी।

यही वजह है कि आगे चलकर 14वीं और 15वीं लोकसभा में कुल जमा 50 सदस्य निलंबित किए गए। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यह आंकड़ा 16वीं और 17वीं लोकसभा में आश्चर्यजनक तौर पर बढ़ा। पिछली बार 115 सदस्य निलंबित किए गए थे।

साफ है कि मामला 'इन' या 'उन' का नहीं है। एक अवांछित परंपरा जब-तब संसद को 'मत्स्य न्याय' का शिकार बनाती रहती है, जबकि जरा-सा सामंजस्य बहुत कुछ करा सकता है। माननीय सदस्यों को आज उनके दायित्वों का ध्यान दिलाना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि संसद का पावसकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है।

यह सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान से हमारी फौजी झड़प हुई है। हर झड़प, हर युद्ध अपने पीछे कुछ सुझाव, शिकायतें और सीखें छोड़ जाता है। इस संघर्ष ने क्या छोड़ा? हमने क्या हासिल किया और हमें भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार रखना है? देश के आम जन इन सवालों के जवाब अपनी संसद और सरकार से साझा तौर पर चाहते हैं, क्योंकि यह पक्ष या विपक्ष का नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा का मामला है। इसके अलावा तमाम आंतरिक मुद्दे और महत्वपूर्ण बिल इस सत्र का इंतजार कर रहे हैं। सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा होने के नाते मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

हमारे सांसद चाहें, तो आसानी से इसी सत्र में सारे समाधान हासिल कर सकते हैं। कैसे?

एक वाकया सुनाता हूं। सन् 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। उस दौरान जब हमारे फौजी बर्फीली सीमाओं पर बिना पर्याप्त साधनों के जूझ रहे थे, तब हमारी संसद में विपक्ष के तमाम दिग्गज सरकार पर तरह-तरह के आरोप लगा रहे थे। ओजस्वी अटल बिहारी वाजपेयी भी उस टोली में शामिल थे। विपक्ष की दृढ़ मान्यता थी कि नेहरू सरकार ने अपने कर्तव्यों का भली-भांति पालन नहीं किया। ध्यान रहे, वे महज विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे थे।

अगर ऐसा होता, तो वाजपेयी कुछ बरस बाद 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 'दुर्गा' न घोषित करते। उस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध निर्णायक मुकाम की ओर बढ़ चला था। तय है, एक राष्ट्रभक्त होने के नाते अटल बिहारी वाजपेयी चुनी हुई सरकार का खैरमकदम कर रहे थे। कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। उसके प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने भी 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी को उस प्रतिनिधिमंडल का नेता चुना, जिस पर कश्मीर के मुद्दे पर मानवाधिकार आयोग में भारत का पक्ष रखने का दायित्व था। वाजपेयी ने इस नेक काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाया।

वाजपेयी और नेहरू की बात चली, तो याद आया कि पहले प्रधानमंत्री जब-तब उन्हें 'अच्छे वक्तव्य' की शाबाशी देते। इन भाषणों में नेहरू की जबरदस्त आलोचना होती थी। अटल बिहारी ने भी जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उन्हें जो श्रद्धांजलि दी, वह इतिहास बन गई। उन्होंने कहा था- एक सपना टूट गया, एक गीत खामोश हो गया, एक ज्योति अनंत में विलीन हो गई। यह भय और भूख से मुक्त एक संसार का स्वप्न था, यह एक महाकाव्य का गीत था, जिसमें *गीता* की गूंज और गुलाब की सुगंध थी। यह एक दीपक की लौ थी, जो पूरी रात जलती रही, हर अंधकार से लड़ी, हमें राह दिखाई और एक सुबह निर्वाण प्राप्त कर लिया। मृत्यु निश्चित है, शरीर क्षणभंगुर है। कल जिस स्वर्णिम शरीर को हमने चंदन की चिता पर समर्पित किया था, उसका अंत तो होना ही था। पर क्या मृत्यु को इतने चुपके से आना था? जब मित्र सो रहे थे और पहरेदार सुस्त थे, तब हमसे जीवन का अमूल्य उपहार छीन लिया गया। भारतमाता आज शोक से व्याकुल है- उसने अपना प्रिय राजकुमार खो दिया है। मानवता आज दुखी है- उसने अपना भक्त खो दिया है। शांति आज अशांत है- उसका रक्षक नहीं रहा। दलितों ने अपना आश्रय खो दिया है। आम आदमी की आंखों की रोशनी चली गई है। पर्दा गिर गया है!

वह कटुताओं का नहीं, कड़वाहटों को भुलाकर आगे बढ़ने का वक्त था।

ऐसा नहीं है कि वह रवायत पूरे तौर पर दम तोड़ चुकी है। बहुत दूर जाए बिना पिछले बजट सत्र का उदाहरण देना चाहूंगा। संसद के दोनों सदनों ने गजब की एकजुटता का प्रदर्शन किया था। उस सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 118 और राज्यसभा की 119 फीसदी दर्ज की गई। राज्यसभा ने तो अनूठा इतिहास ही रच दिया। सत्र के अंतिम दो दिन, यानी 3 अप्रैल को सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्यवाही अगली सुबह 4.02 बजे तक चलती रही। तय है, सब कुछ संभव है, बस नीयत चाहिए।

क्या हमारे माननीय अपने इस सकारात्मक कीर्तिमान को इस सत्र में जारी नहीं रखना चाहेंगे? वक्त इस सवाल के जवाब को अपने बही-खाते में दर्ज करने को बेताब है।

@shekharkahin
@shashishekhar.journalist

जीने की राह

डॉ एन जेन्सी
असिस्टेंट प्रोफेसर

जेन्सी ने दुनिया का सबसे बड़ा महाज जीत लिया

कॉलेज के उदार माहौल, प्रोफेसरों के साथ और जेन्सी की मेहनत ने मिलकर इतिहास रच दिया। तमिलनाडु में पहली बार कोई ट्रांस जेंडर विद्यार्थी गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएट हुआ। यही इतिहास एमए में भी रचा गया। फिर एमफिल में उन्होंने अपनी मूल पहचान के साथ जीने का फैसला किया।

महाभारत में एक बेहद सशक्त किरदार है- बृहन्नला। एक किन्नर। संसार के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन को अज्ञातवास में बृहन्नला क्यों बनना पड़ा? यह एक लंबी कहानी है, मगर यहां उनका संदर्भ इसलिए, क्योंकि यह बताया जा सके कि द्वापर युग में भी किन्नरों को उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर ऊंचा स्थान मिल जाता था। बृहन्नला राजा विराट की पुत्री उत्तरा की संगीत-नृत्य गुरु थीं। मगर आधुनिक भारत में किन्नरों के साथ क्या किया गया? उन्हें सिर्फ हिकारत मिली। आज की कहानी इसी समुदाय की एक ऐसी शख्सीयत की है, जिसने तमाम तकलीफें उठाकर समाज में ऐसा मुकाम हासिल किया है, जिस पर इंसानियत हमेशा नाज करेगी। ट्रांस जेंडर समुदाय की डॉ एन जेन्सी हाल ही में चेन्नई के प्रतिष्ठित लोयोला कॉलेज में अंग्रेजी की प्राध्यापिका नियुक्त की गई हैं।

तिरुवल्लूर जिले के एक बेहद छोटे से गांव में जन्मे जेन्सी की काया लड़के की थी, मगर उसमें रूह लड़की की बसती थी। छुटपन से ही उन्हें लड़कियों की सोहबत अच्छी लगती। होश संभाला, तो गांव की बच्चियों के साथ ही खेला-कूदा, यहां तक कि उनके साथ ही समूह में पारंपरिक गीत गाए। इन सबके लिए किसी ने उन्हें कभी प्रोत्साहित नहीं किया था, यह आकर्षण कुदरती था। शुरू-शुरू में परिवार के लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, मगर जब पड़ोस से शिकायतें आने लगीं, तब माता-पिता, परिजनों की सख्ती शुरू हो गई। उन्हें स्त्री-पुरुष के अलावा तीसरा कोई जेंडर मंजूर ही नहीं था!

जेन्सी को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या गलती कर दी? एक बार मजाक उड़ाने और दुत्कारे जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह साल-दर-साल बढ़ता ही गया। जेन्सी को कक्षा में आखिरी कतार में बैठना पड़ता, क्योंकि कोई लड़का उनसे बात नहीं करना चाहता था। लड़कों को लगता कि अगर उन्होंने जेन्सी से बात की, तो शिक्षक उन्हें डांटेंगे। उपेक्षित जेन्सी को किताबों के बीच पनाह मिली। छोटी अवस्था में ही उन्हें यह अच्छी तरह एहसास हो गया कि किताबों से बेहतर साथी उनको कोई और नहीं मिलेगा? जहीन दिमाग को कठिन परिश्रम का साथ मिला, तो नतीजे कमाल के आने लगे। वह कक्षा में अव्वल आने लगे।

लगातार क्लास में टॉप करते जाने के कारण न सिर्फ शिक्षकों का जेन्सी के प्रति नजरिया बदला, बल्कि जो लोग उनकी पहचान को लेकर उनका उपहास उड़ाते थे, वे भी थोड़ी संजीदगी से उन्हें लेने लगे। कुछ लोग तो यदा-कदा तारीफ भी कर दिया करते। जाहिर है, यह आंशिक बदलाव भी बेहद सुखद था। जेन्सी अच्छी तरह समझ गए थे कि तालीम के जरिये ही वह गांव-परिवार और समाज के दबावों का मुकाबला कर सकते हैं। लिहाजा, पूरी शिद्दत से पढ़ाई में जुट गए। मगर 'अंग्रेजी' भाषा एक फांस बनी रही।

दरअसल, जेन्सी जिस सरकारी हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, वहां इंग्लिश शिक्षक की नियुक्तियां तो होतीं, मगर वे शिक्षक वहां रुकते नहीं थे। कुछ ही दिनों में वे अपना तबादला चेन्नई के किसी स्कूल में करा लेते। इस तरह उनका स्कूल अंग्रेजी शिक्षक से महरूम ही रहता। अन्य बच्चों की तरह जेन्सी को भी खुद ही अंग्रेजी की पढ़ाई करनी पड़ती। बहरहाल, अब तक उन्हें यह पता चल चुका था कि अंग्रेजी बहुत सारी वर्जनाओं से मुक्ति दिला सकती है, क्योंकि जिस गांव में वह रहते थे, वहां भी इसका बहुत रौब था। बारहवीं के जब परिणाम आए, तो जेन्सी को अंग्रेजी में सबसे कम अंक मिले। इस कमी ने इसके प्रति आकर्षण और बढ़ा दिया।

हाईस्कूल के बाद जेन्सी चेन्नई के डॉ आंबेडकर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज पहुंचे, जहां उन्हें अपने पसंदीदा विषय- अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य में दाखिला मिल गया। इस भाषा को लेकर पहले से चाव था ही और बारहवीं के कम अंकों ने एक चुनौती भी फेंक दी थी। बालिग हो चुके जेन्सी को देश के आईन से अपने तईं फैसला लेने का पूरा अख्तियार मिल चुका था। जो वह थे नहीं, उसका दिखावा करते-करते भी ऊब चुके थे और इस चोले को झटक देने को व्याकुल हो उठे थे। वह जानते थे कि उनका परिवार इसमें साथ नहीं देगा, लिहाजा सबसे पहले उन्हें अपना करियर बनाना होगा।

बेहतरीन प्रोफेसरों के साथ, कॉलेज के उदार माहौल और जेन्सी की मेहनत ने मिलकर इतिहास रच दिया। तमिलनाडु में पहली बार कोई ट्रांस जेंडर विद्यार्थी गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएट हुआ। यही इतिहास एमए में भी रचा गया। जब वह एमफिल में थे, तब उन्होंने अपनी मूल पहचान के साथ जीने का फैसला किया। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर, एंकरिंग करके और अलग-अलग कार्यक्रमों की मेजबानी के जरिये जेन्सी ने इतने पैसे जोड़ लिए थे, जिससे वह सर्जरी करा सकें। सर्जरी के बाद उन्होंने अपनी मां और बड़ी बहन को बताया कि अब वह उनका बेटा और भाई नहीं, उनकी बेटी और बहन हैं।

जेन्सी का परिवार हैरान रह गया था, मगर जेन्सी दोहरी जिंदगी से मुक्त हो चुकी थीं। प्रतिष्ठित लोयोला कॉलेज से अंग्रेजी भाषा और साहित्य में पीएचडी करने के बाद जब वहां की फैकल्टी में एक अंशकालिक व्याख्याता की नियुक्ति-प्रक्रिया शुरू हुई, तो जेन्सी ने भी आवेदन किया। कुल पांच लोगों का साक्षात्कार हुआ और काबिलियत के बल पर जेन्सी चुनी गईं। तमिलनाडु में एक ट्रांस जेंडर महिला के इस मुकाम

प्रतिष्ठित लोयोला कॉलेज से अंग्रेजी भाषा और साहित्य में पीएचडी करने के बाद जब वहां की फैकल्टी में एक अंशकालिक व्याख्याता की नियुक्ति-प्रक्रिया शुरू हुई, तो जेन्सी ने भी आवेदन किया। कुल पांच लोगों का साक्षात्कार हुआ और काबिलियत के बल पर जेन्सी चुनी गईं।

पर पहुंचने की यह पहली घटना थी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट करके जेन्सी की भरपूर सराहना की और उन्हें मिलने के लिए बुलाया।

जेन्सी के वरिष्ठ विभागीय सहयोगी और बच्चे उनके ज्ञान व पढ़ाने की शैली से अभिभूत हैं। बच्चे जब कहते हैं- मैम, आप सचमुच श्रेष्ठ (बृहन्नला, यानी महान, श्रेष्ठतम) हैं, आपके लिए हम सब हरदम हाजिर हैं, तो इस स्वीकृति से लगता है कि जेन्सी ने दुनिया का सबसे बड़ा महाज जीत लिया।

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

वो लम्हा

श्रीधर वेम्बू
कंप्यूटर वैज्ञानिक व उद्यमी

हिन्दुस्तान और हिंदी की मजबूत वकालत

हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया में बस जाने का मौका था। शिक्षक की नौकरी मतलब पूरी सुरक्षा। कोई फेल हो या पास, कोई तनाव नहीं। ज्यादातर युवा ऐसे प्रस्ताव पर खुशी से झूमने लगते हैं, पर यहां युवा इंजीनियर महोदय उदास हो गए। उनके मन में अनेक सवाल उमड़ने लगे।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

वह फूलों का मौसम था। सारे फूल खिले हुए थे या खिलने को मचल रहे थे। अमेरिका में बसंत की बहार थी। देखकर मन खिल उठता था, खिले हुए मन में अच्छे-अच्छे विचार आते थे। उस 26 वर्षीय युवा के मन में भी यादें उमड़ आती थीं कि कैसे अपने तमिलनाडु के गांवों में भी फूल खिले होंगे। बसंत की बहार ने वहां भी अपनी हरियाली-खुशहाली से कोना-कोना सजा दिया होगा! और, यहां परदेश में मुझे कितने बरस बीत गए!

आईआईटी की पढ़ाई के बाद मद्रास क्या छूटा, अपना देश भारत ही छूट गया। यहां एमएस और पीएचडी की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, तो अब तय करना है कि दुनिया में कहां बसना है। वैसे भी, भारत के प्रतिभावान युवाओं को दुनिया के तमाम देश अपने यहां रखना चाहते हैं। वह युवा इंजीनियर महोदय शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में शामिल होने का प्रस्ताव सामने रखा था। एक तरह से हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया में बस जाने का मौका था। शिक्षक की नौकरी मतलब पूरी सुरक्षा और कोई फेल हो या पास, कोई तनाव नहीं। ज्यादातर युवा ऐसे प्रस्ताव पर खुशी से झूमने लगते हैं, पर यहां युवा इंजीनियर महोदय उदास थे। लगने लगा था कि एक इंजीनियर के रूप में सेवा करना ज्यादा बेहतर होगा। मन में अचानक यह भाव भी आया कि क्या भारत ने जिस फूल को खिलने लायक बनाया, वह ऑस्ट्रेलिया में खिलेगा? इस फूल पर तो अमेरिका से भी ज्यादा हक भारत का है।

सौभाग्य से उनके एक भाई भी अमेरिका में साथ थे, उनको भी वतन की याद सताती थी। बसंत के समय ही दोनों भाइयों के बीच बातचीत हुई। सूचना प्रौद्योगिकी केवल अमेरिका में ही नहीं, भारत में भी करवट ले रही है। अपने देश में भी आईटी पर बहुत काम होगा। यहां का क्या है? यहां कितनी भी सेवा कर लो, हम तो रहेंगे भारतीय ही। यहां हमें मन से अपना कौन मानेगा? देश से पलायन की इस प्रथा को तोड़ने की जरूरत है। आज एक योग्य युवा गांव से शहर आता है, शहर में जब उसकी योग्यता बढ़ जाती है, तो वह विदेश चला जाता है। फिर तो अमेरिकी बसंत में ही रम जाता है, भूल जाता है कि अपने देश में भी फूल खिले होंगे, चांद निकला होगा। अपनी माटी भी इंतजार करती होगी कि इल्म हासिल करने गए हैं जो बच्चे बाहर, कभी तो घर लौटेंगे।

बसंत के प्रवाह में युवा ने दृढ़ता से तय किया कि हर हाल में भारत लौट जाना है और उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया से आए ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया। तय किया कि असली दुनिया में जाना है और ऐसी कंपनी में असली इंजीनियरिंग करनी है, जो असली उत्पाद बनाकर असली दुनिया में बेचती हो।

तत्काल भारत लौटने के बजाय अनुभव लेना जरूरी था, तो उन्होंने एक नामी अमेरिकी आईटी कंपनी में काम शुरू किया। काम कुछ समझ में आया, तो अचानक नौकरी छोड़ अलग-अलग तरह के काम सीखने की शुरुआत की। कोडिंग से मार्केटिंग तक सीखने के बाद उन्होंने अपने भाइयों और एक पार्टनर के साथ मिलकर एक आईटी कंपनी की नींव रखी।

चार साल में ही उनकी कंपनी ने आईटी बाजार में पैर जमा लिए और लोग उन्हें युवा उद्यमी श्रीधर वेम्बू के नाम से जानने लगे। बाजार में हमेशा फायदे के फूल नहीं खिलते, पतझड़ भी आता है, पर श्रीधर में यह काबिलियत थी कि पतझड़ के दिनों में भी उनकी कंपनी फूल खिलाती थी। दूसरों से आगे बढ़कर सोचने, देश, देश के युवाओं और उनकी योग्यता के बारे में सोचने का सिलसिला चल पड़ा। श्रीधर वेम्बू की कंपनी जोहो आज एक अरब डॉलर से भी ज्यादा की कंपनी है। दुनिया के 140 से ज्यादा देशों में अपने सॉफ्टवेयर उत्पाद बेचती है। चालीस से ज्यादा कारगर व्यावसायिक एप चलाती है। पिछले साल इस कंपनी को 2,800 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का शुद्ध मुनाफा हुआ था। पारंपरिक वस्त्र लुंगी पहनने वाले खांटी तमिल श्रीधर वेम्बू भारत के चालीस सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं।

उनकी कहानी यहीं नहीं रुकती। वह स्थायी रूप से अमेरिका से भारत आ चुके हैं। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में अपने गांव से ही अपनी विशाल कंपनी का संचालन करते हैं। वह हिन्दुस्तान ही नहीं, हिंदी के भी बड़े पैरोकार हैं। जिस तमिलनाडु में हिंदी विरोध की राजनीति जहर उगलती रहती है, वहां श्रीधर वेम्बू तमिल युवाओं को बार-बार सलाह देते हैं कि राजनीति में मत पड़ो, हिंदी सीखो। नहीं सीखोगे, तो नुकसान होगा। हिंदी बोलने-समझने में ही तमिलनाडु और देश की तरक्की है। आज वेम्बू की कामयाबी तमाम भारतीय युवाओं के लिए एक संदेश है कि अपने फूलों के सौंदर्य, अपने फलों की मिठास और अपने फलदार पेड़ों की छांव पर सबसे ज्यादा हक अपने देश का है।

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

मतिमंदों का मनोरथ और अपनी हिंदी

तिरछी नजर

सुधीश पचौरी हिंदी साहित्यकार

एक थे समय से आगे के कवि। जाने किस पिनक में एक दिन अपने समय के 'डॉक्टर फिक्सइट' उर्फ फिक्साचार्य ने एक कवि को समय से आगे का कवि 'फिक्स' कर दिया, तो वह हो गए नए डॉ फिक्सइट! उनको देख साहित्य के हम नौनिहाल कोरस सा गाते- देखो वो आ रहा है आगे का कवि... देखो वो जा रहा है आगे का कवि। वह जब तक रहे, आगे के कवि के नाम से ही जाने जाते रहे।

वह अपने समय से कितने आगे रहे, कैसे रहे, इसकी न किसी ने छानबीन की, न आगे के कवि महोदय ने ही चाहा कि कोई बताए कि वह अपने समय से ठीक कितने आगे हैं? कोई पूछता कि वह कितने आगे के हैं? तो उनके 'फैन' कहते, वह आगे तो हैं, लेकिन कितने हैं, यह कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कभी किसी ने नापा ही नहीं और नापा इसलिए नहीं कि नापने का कोई पैमाना ही नहीं था।

हिंदी में हर बंदा इसी तरह नापा जाता रहा है और मजा यह कि सब बिना पैमाने के नपते रहे हैं। सब मानते रहे हैं कि हम सब आगे हैं या हम ही आगे हैं। आगे जी ने भी कभी किसी से न पूछा कि वह समय से आगे हैं, तो कितने? ऐसे मौके पर वह उदात्त होकर 'जाकी रही भावना जैसी' वाली अर्धाली गाने लगते हैं। हिंदी में 'फिक्सिंग' इसी तरह चलती है। जिसे किसी फिक्साचार्य ने कहीं फिक्स कर दिया, वह हमेशा के लिए वहीं फिक्स हो गया।

यूं सिद्धांत बताते हैं कि साहित्य अपने समय की पहचान होता है, अपने समय का आईना होता है, अपने समय का हलफनामा होता है, गवाह होता है, अभिव्यक्ति होता है। फिर भी कई आचार्य ऐसे हुए, जिन्होंने जिस-तिस को अपने वक्त से आगे का कवि, कथाकार कहकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। शायद इसीलिए हिंदी में अब भी गुरु-शिष्य परंपरा बनी हुई है।

इतिहास गवाह है कि हिंदी के एक ऐसे फिक्साचार्य भी हो चुके हैं, जो जिस-तिस को फिक्स कर जमाते और बनाते रहते थे! हिंदी में इसे कहते हैं : 'बनाना'! यह क्रिया मात्र नहीं है, बल्कि यह मुहावरा भी है। बनते-बनाते हिंदी ने यही सीखा है कि जैसे बनो, जिस तरह बनो, उसी तरह बनो और बनाओ, क्योंकि तुमको भी कोई बनाने वाला है, फिक्स करने वाला है। किसी को बुद्धू बनाना, बेवकूफ बनाना, उसमें हवा भरना, ईगो को फुलाना... आदि सब बनाने की पर्याय-क्रियाएं हैं। यही हिंदी की अपनी 'बनाना कल्चर' है, जिसमें हर बंदा एक-दूसरे को हर समय बनाता रहता है।

हिंदी में दो-तीन तरह की प्रतिभाएं होती हैं। एक, जो जेनेटिकली प्रातिभ हैं। दूसरी, जो व्युत्पन्न हैं, यानी व्युत्पन्न मति हैं, ज्ञानी हैं। तीसरी, जो अभ्यासी हैं। ये *करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान* की श्रेणी में आते हैं। पर एक चौथी श्रेणी भी है, जो साहित्य सेवकों की होती है। ये सेवक भाव में इतने लीन रहते हैं कि करत-करत अभ्यास के भी सुजान नहीं बन पाते, यद्यपि इनकी भी हजारों ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि हर ख्वाहिश पूरा करने के लिए ये बड़े-बड़े फिक्साचार्यों के दम निकालते रहते हैं।

ये उनके पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं और नाना प्रकार से उनकी नवधा भक्ति करते हुए, धूप-दीप-नैवेद्य, फल-फूल, पान व आपानक चढ़ाते हुए उनके नाम की पंजीरी भी बांटते रहते हैं! फिर, *सत्संगति किम न करोति पुंसाम्* के अनुसार, कुछ लोग किशोरोचित कविताएं-कहानी लिख-लिखवाकर, फिर उनको अपने इष्ट फिक्साचार्य व उनके बाल-बच्चों को समर्पित कर, उनको सेवक सेव्य भाव की याद दिलाकर एक दिन 'आगे के कवि होने' का आशीर्वाद प्राप्त कर ही लेते हैं।

बेचारे फिक्साचार्य भी क्या करें? वे भी सेवक *सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरुगारि* के विरुद को निभाते हुए ऐसे सेवक को 'समय से आगे का कवि' बना डालते हैं। सच! मतिमंदों का मनोरथ भी पूरा करती है हिंदी!

कटाक्ष

राजेंद्र धोड़पकर

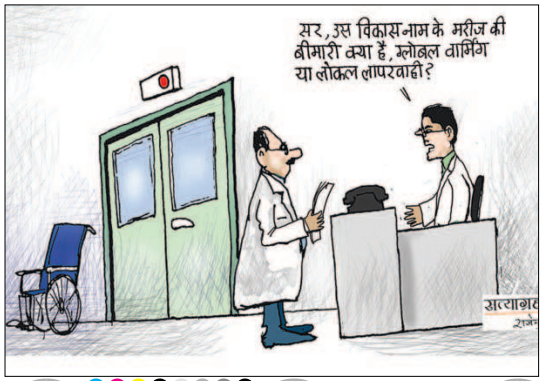

मीडिया की इतनी ताकत है कि तटस्थ न होने की सूरत में यह बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। दुर्भाग्य से यह आम तौर पर तटस्थ नहीं होता। इसे उन रिपोर्टों से समझा जा सकता है जो एआई 171 विमान हादसे को लेकर पश्चिम में छप रही हैं, जिनमें कहा गया है कि दोनों में से एक पाइलट आत्महत्या करना चाहता था। यह बेबुनियाद कयासबाजी है, लेकिन अनेक लोग इसे सच भी मान सकते हैं।

मारिया रिथ, लेखिका @mariawrith1

पर्यावरण

भारत डोगरा

जलवायु बदलाव के समाधान की न्यायसंगत राह

जलवायु बदलाव का संकट विश्व स्तर पर गंभीर समस्या के रूप में स्वीकृत है। बढ़ती आपदाओं के रूप में इसके गंभीर दुष्परिणाम सामने आ ही रहे हैं, पर उचित उपाय समय पर न होने पर ये दुष्परिणाम इससे कहीं अधिक बढ़ सकते हैं। अतः जहां इसके समाधान के उपाय बहुत जरूरी हैं, पर इनको लेकर धनी देश व वहां की बहुराष्ट्रीय कंपनियां न्यायसंगत नीति नहीं बनने दे रही हैं। जहां एक ओर वे जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहे हैं वहां दूसरी ओर विकासशील देशों पर अधिक बोझ डाला जा रहा है और ऐसी विसंगतिपूर्ण नीतियों के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिनसे इन विकासशील देशों के किसानों और अन्य जनसाधारण को क्षति हो सकती है।

हमे वह राह अपनानी है जिस पर चलते हुए जलवायु बदलाव के न्यायसंगत समाधान प्राप्त हों। जलवायु बदलाव के संकट को नियंत्रण करने के उपायों में जनसाधारण की भागेदारी प्राप्त करने का सबसे असरदार उपाय यह है कि विश्व स्तर पर ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में पर्याप्त कमी उचित समय-अवधि में लाए जाने की ऐसी योजना बनाई जाए जो सभी लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से जुड़ी हो और फिर इस योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में तेजी से बढ़ा जाए। यदि इस तरह की योजना बना कर कार्य होगा तो ग्रीनहाऊस गैस उत्सर्जन में कमी के जरूरी लक्ष्य के साथ-साथ करोड़ों अभावग्रस्त लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य अनिवार्य तौर पर जुड़ जाएगा और इस तरह ऐसी योजना के लिए करोड़ों लोगों का उत्साहवर्धक समर्थन प्राप्त हो सकेगा। दुनिया के सब लोगों की जरूरतों को पूरा करने की योजना बनाते हैं, तो स्पष्ट है कि वर्तमान अभाव की स्थिति को देखते हुए करोड़ों गरीब लोगों के लिए पौष्टिक भोजन, वस्त्र, आवास, दवाओं, कापी-किताब आदि का उत्पादन बढ़ाना होगा। इस उत्पादन को बढ़ाने में हम पूरा प्रयास कर सकते हैं कि ग्रीनहाऊस गैस के उत्सर्जन को कम करने वाली तकनीकों का उपयोग हो पर यह एक सीमा तक ही संभव होगा।

अतः यदि गरीब लोगों के लिए जरूरी उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए जरूरी प्राकृतिक संसाधन और कार्बन स्पेस प्राप्त करने के लिए साथ ही जरूरी हो जाता है कि विलासिता की वस्तुओं और गैर-जरूरी वस्तुओं का उत्पादन कम किया जाए। यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि गरीब लोगों के लिए जरूरी उत्पादन को प्राथमिकता देने वाला नियोजन न किया गया तो फिर विश्व स्तर पर बाजार की मांग के अनुकूल ही उत्पादन होता रहेगा। वर्तमान विषमताओं वाले समाज में विश्व के धनी व्यक्तियों के पास क्रय शक्ति बेहद अन्यायपूर्ण हद तक केंद्रित है, अतः बाजार में उनकी गैर-जरूरी और विलासिता की वस्तुओं की मांग को प्राथमिकता मिलती रहेगी। अतः इन्हीं वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता मिलेगी। सीमित प्राकृतिक संसाधनों और कार्बन स्पेस का उपयोग इन गैर जरूरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए होगा। गरीब लोगों की जरूरी वस्तुएं पीछे छूट जाएंगी, उनका अभाव बना रहेगा या और बढ़ जाएगा। अतः यह बहुत जरूरी है कि ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की योजना से विश्व के सभी लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की योजना को जोड़ दिया जाए और उपलब्ध कार्बन स्पेस में बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देना एक अनिवार्यता बना दिया जाए। इस योजना के तहत जब गैर-जरूरी उत्पादों को प्राथमिकता से हटाया जाएगा तो यह जरूरी बात है कि सब तरह के हथियारों के उत्पादन में बहुत कमी लाई जाएगी। मनुष्य और अन्य जीवों की भलाई की दृष्टि से देखें तो हथियार न केवल सबसे अधिक गैर-जरूरी हैं अपितु सबसे अधिक हानिकारक हैं। इसी तरह अनेक हानिकारक उत्पाद हैं (शराब, सिगरेट, कुछ बेहद खतरनाक केमिकल्स आदि) जिनके उत्पादन को कम करना करना जरूरी है।

पहले कहा जाता था कि संसाधन सीमित हैं, उनका सही वितरण करो। पर अब तो ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन से जुड़ी कार्बन की सीमा है। इस सीमा के बीच में ही हमें सब लोगों की जरूरतों को टिकाऊआधार पर पूरा करना है। अतः विषमता को दूर करना, विलासिता और अपव्यय को दूर करना, समता और न्याय को ध्यान में रखना, भावी पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखना पहले से भी कहीं अधिक जरूरी हो गया है। सही व विस्तृत योजना बनाना इस कारण और जरूरी हो गया है कि ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को तेजी से कम करते हुए ही सब लोगों की बुनियादी जरूरतों को भी न्यायसंगत ढंग से और टिकाऊ तौर पर पूरा करना है। यह बड़ी चुनौती है जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी और बहुत रचनात्मक समाधान ढूंढने होंगे। ऐसे प्रयासों से विश्व के लिए कल्याणकारी संदेश मिल सकते हैं

जलवायु बदलाव के नियंत्रण को प्रायः एक तकनीकी मुद्दे के रूप में देखा जाता है, ऐसे तकनीकी उपायों के रूप में जिनसे ग्रीनहाऊस गैसों का उत्सर्जन कम हो सके। यह एक संकीर्ण नजरिया है। यह सच है कि अनेक तकनीकी बदलाव जरूरी हैं पर जलवायु बदलाव का मुद्दा केवल इन तक सीमित नहीं है। जलवायु बदलाव को नियंत्रित करने के लिए जीवन-शैली में बदलाव जरूरी है, और इसके साथ जीवन-मूल्यों में बदलाव जरूरी है। उपभोक्तावाद का विरोध जरूरी है, विलासिता और नशे का विरोध जरूरी है। युद्ध और हथियारों की दौड़ और होड़ का विरोध करना बहुत जरूरी है। पर्यावरण पर अधिक बोझ डाले बिना सबकी जरूरतें पूरी करनी है तो न्याय और साझेदारी की सोच जरूरी है, पर्यावरण को क्षति से बचाना है तो आपसी भागेदारी से कार्य करना जरूरी है। अतः जलवायु बदलाव नियंत्रण का सामाजिक पक्ष बहुत महत्त्वपूर्ण है। आज विश्व के अनेक बड़े मंचों से बार-बार कहा जा रहा है कि जलवायु बदलाव को समय रहते नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, पर क्या मात्र कह देने से या आह्वान करने से समस्या हल हो जाएगी। वास्तव में लोग तभी बड़ी संख्या में इसके लिए आगे आएंगे जब आम लोगों में, युवाओं और छात्रों में, किसानों और मजदूरों के बीच न्यायसंगत और असरदार समाधानों के लिए तीन-चार वर्षों तक धैर्य से, निरंतरता और प्रतिबद्धता से कार्य किया जाए। तकनीकी पक्ष के साथ इस सामाजिक पक्ष को समुचित महत्त्व देना बहुत जरूरी है। एक अन्य सवाल यह है कि क्या मौजूदा आर्थिक विकास और संवृद्धि के दायरे में जलवायु बदलाव जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान हो सकता है? मौजूदा विकास की गंभीर विसंगतियां और विकृतियां ऐसी ही बनी रही तो क्या जलवायु बदलाव जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं नियंत्रित हो सकेंगे। इस प्रश्न का उत्तर है 'नहीं'। वजह यह है कि मौजूदा विकास की राह में विषमता और अन्याय और प्रकृति का निर्मम दोहन है।

पहले यह कहा जाता था कि संसाधन सीमित हैं, उनका सही वितरण करो। पर अब तो ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन से जुड़ी कार्बन की सीमा है। इस सीमा के बीच में ही हमें सब लोगों की जरूरतों को टिकाऊआधार पर पूरा करना है। अतः अब विषमता को दूर करना, विलासिता और अपव्यय को दूर करना, समता और न्याय को ध्यान में रखना, भावी पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखना पहले से भी कहीं अधिक जरूरी हो गया है। सही व विस्तृत योजना बनाना इस कारण और जरूरी हो गया है कि ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को तेजी से कम करते हुए ही सब लोगों की बुनियादी जरूरतों को भी न्यायसंगत ढंग से और टिकाऊ तौर पर पूरा करना है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी और बहुत रचनात्मक समाधान ढूंढने होंगे।

इस तरह के प्रयास से ऐसे परिणाम मिल सकते हैं जो विश्व के लिए बहुत कल्याणकारी संदेश दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे किसी मॉडल के नियोजन से ऐसा संदेश मिलने की बहुत संभावना है कि युद्ध और हथियारों की होड़ को समाप्त किया जाए या न्यूनतम किया जाए। एक अन्य संदेश यह मिलने की संभावना है कि जो बहुत वेस्टफुल उत्पादन और उपभोग हैं, उन्हें समाप्त किया जाए या बहुत नियंत्रित किया जाए। इस तरह से स्थिति स्पष्ट होने से युद्ध, हथियारों व वेस्टफुल उत्पादन-उपभोग पर नियंत्रण के पक्ष में बड़ा जनमत बनेगा। यह अपने आप में बहुत उपयोगी होगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी।

ब्रांड और राजनीति

मीडिया

सुधीश पचौरी

भाजपा का 'भगवा अंगवस्त्र' या कांग्रेस की 'गांधी टोपी', इसी तरह सपा की 'लाल टोपी' और आरजेडी की 'हरी टोपी' भी ब्रांड हैं। कह सकते हैं कि अपनी दलीय राजनीति 'ब्रांड युग' में आज नहीं आई, बल्कि पहले दिन से ऐसी है, लेकिन इन दिनों की राजनीति अपने काम से कम, 'ब्रांड' से अधिक पहचानी जाती है

आज के 'मीडिया आक्रांत' समय में समकालीन राजनीति को भी 'ब्रांड' की पदावली में परिभाषित किया जा सकता है। मसलन, अमेरिका के राष्ट्रपति 'ट्रंप' स्वयं एक 'सुपर ब्रांड' कहे जाते हैं। उनके सहयोगी/असहयोगी 'एलन मस्क' भी अपने आप में ब्रांड माने जाते हैं। ऐसे 'ब्रांड' जब कुछ 'उल जलूल' कर बैठते हैं, तो इनकी 'स्टॉक वैल्यू' कभी उठ जाती है, कभी गिर जाती है। इनके उठने-गिरने से दुनिया के मारकेट पर असर पड़ता है।

आजकल कई नेता भी अपने-अपने 'दल' को एक 'ब्रांड' की तरह परिभाषित करने लगे हैं, और उसी तरह उसे 'मारकेट' करने लगे हैं यानी बेचने लगे हैं। 'जनता' और 'दलों' का 'नया संबंध' बन रहा है। इससे, दलीय राजनीति की हमारी 'दैनिक पदावली' भी बदल रही है। उदाहरण के लिए, जब जब मोदी जी विदेशों में सम्मानित किए जाते हैं, और चैनल प्रसारित करते हैं, तो विपक्ष कहने लगता है कि ये सब 'ब्रांड निर्माण' है...हम सोचने लगते हैं कि ये 'मोदी ब्रांड' क्या है? और पाते हैं कि मोदी अपनी 'ब्रांड' को स्वयं एक से एक 'हिट कैच लाइन' देकर बनाते आए हैं, उनके समर्थक व उनके निंदक भी बनाते आए हैं, और सर्वोपरि मीडिया और सोशल मीडिया बनाता आया है। इस 'मोदी ब्रांड' को परिभाषित करने वाली एक बड़ी 'कैच लाइन' है, जिसे मोदी जी ने स्वयं बनाया व स्थापित किया है। यह 'कैच लाइन' है 'मोदी है तो मुमकिन है' और इसी से मिलती-जुलती दूसरी 'कैच लाइनें' हैं:'ये मोदी की गारंटी की गारंटी है'...इसी क्रम में एक और 'कैच लाइन' है:'आजादी का अमृतकाल'...फिर एक और 'कैच लाइन' कि 'एक भारत विकसित भारत', फिर एक और 'कैच लाइन' कि 'विरासत भी विकास' भी!

कहने की जरूरत नहीं कि अपने 'ब्रांड' की 'कैच लाइन' को लगातार बदलने और पॉपूलर करने में मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं। जितनी कैच लाइनें उनकी 'हिट' हैं, उतनी 'ट्रंप जी' की भी नहीं। यों 'ट्रंप जी' की भी कई 'कैच लाइन' रही हैं, लेकिन उनके द्वारा दी गई 'सबसे बड़ी कैच लाइन' है 'मागा' यानी 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन'। उनके विपक्ष ने भी उनको कई प्रतिक्रियात्मक 'कैच लाइनों' से नवाजा है जैसे कि वो एक 'गेट डिसरप्टर' यानी 'सबसे बड़े उलट पुलट करने वाले' हैं, 'ट्रांजेक्शनल' हैं यानी 'कठोर सौदेबाज' हैं, 'व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट' यानी 'गोरों को श्रेष्ठ' मानने वाले हैं...मोदी जी की तरह राहुल जी ने भी अपना 'ब्रांड' बनाया है जैसे कि वे 'संविधानवादी' हैं, जब दिखते हैं 'संविधान की कापी' हाथ में लिए दिखते हैं। उनकी एक कैच लाइन है 'भारत बचाओ' है। यों तो अपना जनतंत्र स्वयं 'ब्रांड प्रिय' है।

'चुनाव आयोग' हर दल को एक 'चुनाव चिह्न' प्रदान करता है, और वही उसका 'ब्रांड' और 'पहचान' बन जाता है। कई बार कोई 'चुनाव चिह्न' किसी दल की पूरी 'पहचान' नहीं बता पाता इसलिए भी बहुत से दल अपने 'मेनीफैस्टो' में कुछ 'कैच लाइन' डाल कर 'पहचान' बनाते हैं। 'ब्रांड विशेषज्ञ' जानते हैं कि 'ब्रांड' की असली 'जान', 'सबका ध्यान खींचने वाली कैच लाइन' में तो बसती ही हैं, उससे भी अधिक 'ब्रांड' की 'व्यावहारिक उपयोगिता' में बसती है। इसका मतलब यह है कि 'ब्रांड' अपनी 'कैच लाइन' या 'छवि' से ही नहीं चलता। किसी 'ब्रांड' में 'गुणवत्ता' नहीं यानी 'यथा नाम तथा गुण' नहीं तो आप लाख 'विज्ञापन' कर लो, लाख बड़े-बड़े 'पोस्टर' लगा दो, लाख बड़ी 'होर्डिंग' टंगवा दो, तो भी वह दो दिन नहीं टिकने वाला।

'ब्रांड' का मतलब है 'बाजार' यानी बाजार का 'कंपटीशन' और 'कंपटीशन' में टिके रहने या आगे-आगे रहने की 'ब्रांड' की 'क्षमता'! 'ब्रांड' की एक और विशेषता है, और वह है उसकी 'कैच लाइन' में व्यंजित 'पूर्ण आश्वस्ति' यानी 'पूरा भरोसा'! लेकिन अच्छे और टिकाऊ 'ब्रांड' की सबसे बड़ी विशेषता उसकी 'रिकॉल वैल्यू' होती है यानी वह स्मृति में 'टिका' रहता है। 'ब्रांड' की इस 'क्षणभंगुरता' में भी 'अमरता' होती है। 'लाइफ बाय','कोलगेट', 'लक्स', 'पार्लेजी', 'विक्स', 'ठंडा माने कोका कोला', 'ये दिल मांगे मोर' कुछ ऐसे 'ब्रांड' व 'कैच लाइनें' हैं, जो कान में पड़ते ही हमें उस ब्रांड की याद दिला देती हैं और हम आंख मूंद कर उसे खरीदने लगते हैं। इसी तरह भाजपा का 'भगवा अंगवस्त्र' या कांग्रेस की 'गांधी टोपी', इसी तरह सपा की 'लाल टोपी' और आरजेडी की 'हरी टोपी' भी ब्रांड हैं। कह सकते हैं कि अपनी दलीय राजनीति 'ब्रांड युग' में आज नहीं आई, बल्कि पहले दिन से ऐसी है, लेकिन इन दिनों की राजनीति अपने काम से कम, 'ब्रांड' से अधिक पहचानी जाती है!

जब पथ्य ही जहर हो जाए

सामयिक

पंकज चतुर्वेदी

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के कीटनाशक प्रबंधन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत 40 से अधिक देशों ने पैराक्वाट को प्रतिबंधित किया है। इसे पीआईसी अर्थात 'पूर्व सूचित सहमति' सूची में शामिल करने की कई बार मांग की गई लेकिन भारत सहित कुछ देशों के विरोध के कारण यह स्वीकृत नहीं हो सका

बीमार व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर होता है, इसलिए उसे सुपाच्य आहार की जरूरत होती है। डॉक्टर अक्सर मरीजों को मूंग दाल खाने की सलाह देते हैं, लेकिन अधिक मुनाफे के लोभ में अब जो मूंग बाजार में आ रही है, वह सामान्य बीमार व्यक्ति को गंभीर जानलेवा रोग का शिकार बना सकती है। चूंकि मध्य प्रदेश में देश में मूंग की फसल का 35% उत्पादन होता है और शुरुआत में राज्य सरकार ने मूंग की सरकारी खरीदी पर हिचकिचाहट दिखाई थी तो सियासत भी गरमा गई थी।

सरकार अपनी जगह ठीक ही थी, यह बात तंत्र समझ गया था कि अधिक फसल और इसे जल्दी पकाने के लिए किसान जिस रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं, असल में वह जहर है। समझना होगा कि यदि मध्य प्रदेश के किसान यह अनुचित तरीका अपना रहे हैं, तो देश के अन्य राज्यों में भी यही हो रहा होगा। विदित हो मप्र में इस वर्ष मूंग का सरकारी खरीद मूल्य 8558 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह दाम बीते चार साल में 1362 बढ़ा है। बढ़ते दाम, तीसरी फसल की लालसा और कम रकबे में अधिक उत्पाद के चलते किसान का मूंग की तरफ आकर्षण भी बढ़ा और लालच भी।

मप्र के कृषि विभाग ने राज्य शासन को बताया कि किसान मूंग की फसल में खरपतवारनाशक दवा पैराक्वाट डाइक्लोराइड, जिसे स्थानीय रूप से 'सफाया' भी कहा जाता है, का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। कई देशों में यह प्रतिबंधित है, पर हमारे यहां किसान इसका उपयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। किसान जानते हैं कि मूंग की फसल खेतों में एक साथ नहीं पकती। कुछ पौधे जल्दी तो कुछ देर से पकते हैं। ऐसे में मजदूरों से तुड़ाई में समय, खर्च ज्यादा लगता है। फसल को एक साथ सुखाने के लिए पैराक्वाट तत्काल असर करती है। इससे एक दिन में पूरी फसल सूख जाती है, फिर हार्वेस्टर से कटाई हो जाती है। इसके इस्तेमाल से कच्ची मूंग के दाने भी चमकीले हरे दिखते हैं। इस तरह इनका वजन अधिक लगता है और दाम अधिक मिल जाते हैं। दरअसल, किसान रबी और खरीफ की फसल के बीच तीन महीनों में मूंग की फसल तैयार करने के लिए यह जहरीला जतन कर रहे हैं। भारत में कोई तीस लाख मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन होता है और यह समूचे देश में बीमारों के लिए पथ्य भोजन मानी जाती है। ऐसे खाद्य उत्पाद में जाने-अनजाने जहर घोला जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार पैराक्वाट डाइक्लोराइड के इस्तेमाल से उगाई गई मूंग के सेवन से कैंसर, लंग्स, किडनी, लिवर फेल्योर, पार्किंसंस रोग का खतरा रहता है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि मूंग के दानों में पैराक्वाट के अवशेष रह जाते हैं। जब इन दानों का सेवन किया जाता है, तो ये सीधे मानव शरीर में पहुंचते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी 2024 में प्रकाशित शोध के अनुसार पैराक्वाट डाइक्लोराइड की रासायनिक संरचना एमपीपी प्लस नामक जहरीले पदार्थ से मिलती-जुलती है, जो एमपीटीपी नामक रसायन से बनता है। यह वही रसायन है, जिससे 1983 में मनुष्यों में पार्किंसंस जैसा रोग पैदा हुआ था।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के कीटनाशक प्रबंधन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत 40 से अधिक देशों ने पैराक्वाट को प्रतिबंधित किया है। इसे पीआईसी अर्थात 'पूर्व सूचित सहमति' सूची में शामिल करने की कई बार मांग की गई लेकिन भारत सहित कुछ देशों के विरोध के कारण यह स्वीकृत नहीं हो सका। हालांकि यह मिट्टी में आंशिक रूप से निष्क्रिय हो जाता है, फिर भी यह लंबे समय तक मिट्टी में बना रह सकता है, जिससे मिट्टी के सजीव जीवाणु, कवक, कृमि, और अन्य सूक्ष्म जीवों पर इसका प्रतिकूल असर होता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यह नदी, नहर, तालाबों में उपस्थित मछलियों, मेंढकों और जल जीवों के लिए विषैला है। जल-जनित जीवों में श्वसन विकार, जनन क्षमता में गिरावट और मृत्यु दर में वृद्धि देखी गई है।

भारत सरकार ने पैराक्वाट को प्रतिबंधित रसायनों की सूची में नहीं डाला है, जबकि केरल और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि इन प्रतिबंधों का असर सीमित है, क्योंकि इसका अवैध या गलत उपयोग अब भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। पूर्ण प्रतिबंध में दिक्कत है तो इसके इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी हो। मूंग का जहर होना एक प्रकार से दवा का बेअसर होना है।

चांद पर मानव के पहले कदमों का सम्मान

चंद्रमा दिवस

योगेश कुमार गोयल

चंद्रमा की सतह पर मानव द्वारा पहली लैंडिंग की वर्षगांठ के रूप में 20 जुलाई को वर्ष 2022 से 'अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस' मनाया जा रहा है। यह दिवस पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पर मनुष्य के पहले कदमों का सम्मान है।

इस वर्ष चौथा अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 'एक चंद्रमा, एक दृष्टि, एक भविष्य' विषय के साथ मनाया जा रहा है, जो वैश्विक सहयोग और चंद्र अन्वेषण तथा मानवता के लिए इसके लाभों के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर जोर देता है। यह चंद्रमा की क्षमता को सितारों के प्रवेश द्वार और स्वयं के लिए एक दर्पण के रूप में उजागर करता है तथा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए चिंतन और एकीकृत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। तीसरा चंद्रमा दिवस 'छाया को रोशन करना' थीम के साथ मनाया गया था, जिसका लक्ष्य आम जनता को यह बताना था कि स्थायी चंद्र अन्वेषण करना कितना महत्त्वपूर्ण है। जैसे-जैसे अधिक मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेंगे, वैसे-वैसे इसका रहस्य उजागर होता जाएगा और छायाएं हमेशा के लिए प्रकाशित हो जाएंगी, जिससे मानव जाति के लिए चंद्रमा की खोज और उससे लाभ उठाने का मार्ग प्रशस्त होगा। 2023 में यह दिवस 'मानवता के लिए नई चंद्र यात्रा की शुरुआत' थीम के साथ मनाया गया था।

भारत के लिए इस दिवस का महत्त्व बहुत ज्यादा है क्योंकि 14 जुलाई, 2023 को चंद्र मिशन के तहत 'चंद्रयान-3' लॉन्च किया गया था, जिसके जरिए 23 अगस्त, 2023 को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अविस्मरणीय अध्याय लिखते हुए भारत ने ऐसा स्वर्णिम इतिहास रचा था, जिससे अभी तक दुनिया के तमाम देश कोसों दूर है। दरअसल, चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के जिस बेहद रहस्यमयी और गुमनाम दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखे थे, वह चंद्रमा का बेहद खतरनाक क्षेत्र माना जाता है, और भारत को छोड़ कर दुनिया का कोई भी देश चांद के दक्षिणी ध्रुव को नहीं छू सका था। इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया था। चंद्रयान-3 मिशन की बड़ी सफलता के बाद इसरो अब चंद्रयान-4 मिशन को लॉन्च करने की तैयारियों जुटा है। भारत के इस चौथे मून मिशन को 2028 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। चंद्रयान-4 को चांद से मिट्टी के नमूने लाने के लिए बनाया जा रहा है, जो 'शिव शक्ति' बिंदु से पृथ्वी पर चंद्र नमूने वापस लाएगा। ऐसे में भारत के चंद्र मिशनों पर पूरी दुनिया की नजरें केंद्रित हैं।

अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाने का उद्देश्य चंद्रमा के सतत उपयोग और अन्वेषण तथा चंद्र ग्रह पर और उसके आसपास की गतिविधियों के नियमों की आवश्यकता को शिक्षित करना और बढ़ावा देना है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि सौरमंडल में जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब वह आज की भांति हरी-भरी नहीं थी, बल्कि एक धधकता हुआ आग का गोला थी और उसकी गति, घूर्णन तथा दिन-रात की अवधि भी पूरी तरह अलग थी, लेकिन उस टक्कर की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन के उद्भव के लिए अनुकूल पर्यावरण का जन्म हुआ। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मुताबिक यदि हमें पृथ्वी को समझना है, तो उसके लिए पहले चंद्रमा को समझना जरूरी है क्योंकि उसके बगैर हम अपने सौरमंडल को भी सही ढंग से कदापि नहीं समझ सकते।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से जूझते गरीब देश

चिंता

संजीव ठाकुर

भारत जैसे कई विकासशील देशों में ही जहां गरीबी ने अपना परचम फैला रखा है, वहीं शहरों में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन चालित गाड़ियों और वातानुकूलित यंत्रों यानी एसी की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने से वातावरण में उष्णता बढ़ती जा रही है। वनों का विनाश भयानक समस्या के रूप में फैलता जा रहा है।

अंधाधुंध फैक्ट्रियों एवं मशीनों के उपकरणों से निकलने वाले धुएं से वातावरण विषैला बना कर मनुष्य और जीव-जंतुओं का जीना दूभर कर दिया है। वनों की कटाई के साथ-साथ कंक्रीट के जंगल धीरे-धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगे हैं, ऐसे में शुद्ध वायु और तापमान में आश्चर्यजनक बदलाव जिसके परिणामस्वरूप वर्षा ऋतु के परिवर्तन एवं बारिश में न्यूनता आने से धरती के तापमान में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसी के चलते देश के कई शहरों में तापमान 48 से 50 सेल्सियस होने के कारण पशु-पक्षी एवं मनुष्य की हीट स्ट्रोक से मृत्यु हो जाती है। पानी की कमी तथा शरीर में डिहाइड्रेशन से लोगों व वन्य पशुओं की लगातार मृत्यु हो रही है।

वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे विश्व में बहुत बढ़ गया है और ऐतिहासिक तौर पर पिछले दो से तीन सौ वर्षों की तुलना की जाए तो बीते वर्षों में धरती का तापमान आश्चर्यजनक रूप से तीव्र गति से बढ़ गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के पास ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए कुल मिला कर 10 से 15 वर्ष ही शेष हैं। वैज्ञानिकों की ये बातें और रहस्योद्घाटन मानवता को डराने वाला जरूर है पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके उपायों की जो घोर अनदेखी की जा रही है, वह चिंतनीय है। मानवता के लिए खतरनाक भी है। ग्लोबल वार्मिंग न सिर्फ मनुष्य के लिए खतरा है, बल्कि जीव-जंतुओं समुद्र में पाए जाने वाले जीवो के लिए भी यह विषैला तथा खतरनाक हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार जीवाश्म ईंधन के दशक ने एवं जलने से ग्लोबल वार्मिंग का तापमान तेजी से बढ़ा है एवं पूरी पृथ्वी जीवाश्म ईंधन जलने से तेजी से धड़क रही है। वैज्ञानिकों की चेतावनी तथा दिए गए प्रमाण के बाद भी अनेक देश, जो कार्बन उत्सर्जन के बड़े जिम्मेदार हैं, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करने या खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और तो और इसके आसार भी निकट भविष्य में भारत को छोड़कर अन्य यूरोपीय देशों, जिनमें अमेरिका ब्रिटेन के अलावा 32 देशों ने जो कार्बन उत्सर्जन एवं जीवाश्म ईंधन के उपयोग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार हैं, ने सम्मेलन कर चिंता जरूर जताई है पर इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान चीन, रूस की स्पष्ट दादागिरी दिखती है

देखा जाए तो दुनिया के अमीर देश विश्व के कुल गैस उत्सर्जन के लिए बड़े जिम्मेदार पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले आठ-दस सालों में अपने गैस उत्सर्जन में कटौती को आधा यानी 50 फीसद से कम नहीं करते हैं तो 2050 तक उसे शून्य स्तर पर लाना होगा। ऐसा नहीं किया तो पृथ्वी को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो भारत मोटे तौर पर ग्रीन हाऊस गैसों के कुल वैश्विक उत्सर्जन में सहित 6.8 प्रतिशत का हिस्सेदार है। 2013-2021 के बीच देश के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की मात्रा 17 फीसद बढ़ी है, राहत की बात है कि अब भी भारत का उत्सर्जन स्तर जी-20 देशों के औसत स्तर से बहुत नीचे है

ये छोटे गरीब देशों पर सारी जिम्मेदारी लादने का काम कर रहे हैं। विश्व के कुल देशों में से लगभग 50 देश ऐसे हैं, जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर पृथ्वी को धधकाने में 60% तक हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन इन देशों को ग्लोबल वार्मिंग की चिंता की बजाय विकासशील देश एवं गरीब देशों पर पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर दोषारोपण कर के इतिश्री कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग तथा पर्यावरण चिंतन जितने भी सम्मेलन हुए हैं, उनमें बड़े देशों की नीति एवं दादागिरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चीन, जो सबसे बड़ा कार्बन का उत्सर्जक देश है, ने पर्यावरण पर हुए सम्मेलनों में हिस्सेदारी तो दूर उसकी तरफ ध्यान देना भी उचित नहीं समझा। इंटरनेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने चेतावनी दी है कि धरती के तापमान की वृद्धि को डेढ़ डिग्री तक रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन में 43-50% तक कटौती करनी होगी। 2010-2021 तक दुनिया का औसत वार्षिक ग्रीनहाऊस गैस उत्सर्जन मानव इतिहास में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया जो सर्वाधिक खतरे के निशान से भी ऊपर है। फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें अपने उत्सर्जन को लगभग शून्य पर लाना होगा और इस कार्य के लिए पूरी दुनिया को ऊर्जा क्षेत्र में बड़े और कार्यकारी बदलाव लाने होंगे।

विगत 3 वर्षों में अक्षय ऊर्जा स्रोतों में जैसे सौर एवं पवन ऊर्जा साथी स्टोरेज बैटरी की लागत में आश्चर्यजनक गिरावट आई है, जो लगभग गैस तथा कोयले की कीमत के बराबर हो गई है। कार्बन उत्सर्जन अभी 54% अधिक है। देखा जाए तो दुनिया के अमीर देश विश्व के कुल गैस उत्सर्जन के लिए बड़े जिम्मेदार पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले आठ-दस सालों में अपने गैस उत्सर्जन में कटौती को आधा यानी 50% से कम नहीं करते हैं तो 2050 तक उसे शून्य स्तर पर लाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो पृथ्वी को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो भारत मोटे तौर पर ग्रीन हाऊस गैसों के कुल वैश्विक उत्सर्जन में सहित 6.8 प्रतिशत का हिस्सेदार है। 2013-2021 के बीच देश के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की मात्रा 17 फीसद बढ़ी है, राहत की बात है कि अब भी भारत का उत्सर्जन स्तर जी-20 देशों के औसत स्तर से बहुत नीचे है। भारत की कुल ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन आधारित प्लांट का योगदान 74% है। यदि कार्बन उत्सर्जन को रोका नहीं गया और जीवाश्म ईंधन के उपयोग की रफ्तार यही रही तो भारत सहित विश्व के अधिकांश देश अपनी धरती को बचाने में सक्षम नहीं होंगे।

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - रत्लेश मिश्र* ।

दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

वर्ष-34, अंक 332

आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

सनातन धर्म का इतिहास या संस्कृति से कुछ लेना-देना नहीं है। यह तो इस सच को बयां करता है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। मौसम बदलते हैं। लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। संस्कृतियों का उत्थान और पतन होता है। यहां तक कि मृत्यु भी स्थायी नहीं होती। इस तरह पुनः जन्म की अवधारणा सनातम धर्म का अभिन्न हिस्सा है।
@devduttmyth धर्म मर्मज्ञ

मुद्दा

प्रियंका सौरभ

अश्लीलता की रील और संस्कृति का 'फ्रेम'

हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, जहां स्क्रीन पर दिखना असल में जीने से ज्यादा जरूरी हो गया है। जहां जिंदगी कैमरे के फ्रेम में सिमट गई है, और इंसान का मूल्य उसके 'लाइक', 'फॉलोवर' और 'व्यूज' से तय होता है। इसी डिजिटल होड़ में स्त्रियों की अभिव्यक्ति भी एक अजीब से मोड़ पर आ खड़ी हुई है-जहां रील बनाना कोई बुरा काम नहीं, लेकिन रील के बहाने स्त्री की गरिमा और उसकी सामाजिक छवि का बेशर्म चीरहरण किया जा रहा है।

जिम, मॉल, सड़क, बाथरूम और बेडरूम-हर कोना अब कंटेंट स्टूडियो बन चुका है। कुछ लड़कियां सोशल मीडिया पर जिस तरह की अश्लील और भद्दी रील्स बना रही हैं, वे केवल खुद की नहीं, समूची नारी जाति की गरिमा पर धब्बा बन रही हैं। क्या आपको सच में लगता है कि महज 'वायरल' हो जाने से कोई ताकतवर बन जाता है?

एक औरत के पास उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका आत्मसम्मान और विवेक होता है। आज जो लड़कियां एक्सरसाइज के नाम पर ऐसे कपड़े पहन रही हैं कि देखना भी शर्मिंदगी पैदा करे, वे शायद यह नहीं जानतीं कि वे नारी मुक्ति नहीं, बल्कि नारी बाजारीकरण का प्रचार कर रही हैं। शरीर दिखा कर पहचान बनाना कोई गर्व की बात नहीं है। अगर रील्स ही बनानी हैं, तो क्यों न ऐसी रील बनाओ जिसमें आपकी कला, मेहनत, सोच और संवेदना झलके?

आज हर तीसरी रील में 'पिछवाड़ा' फ्रेम के बीच में है, कैमरा कमर पर जूम करता है, और कैप्शन होता है-'क्लासी एंड सेक्सी!' क्या यही स्त्री की परिभाषा बनती जा रही है?

स्त्री आंदोलन कभी इस उद्देश्य से नहीं चला था। हमने शिक्षा, समानता, आजादी और आत्मनिर्भरता की लड़ाई लड़ी थी, न कि मंच पर खड़े होकर अंग प्रदर्शन की। जो लोग कहते हैं, 'यह स्त्रियों की आजादी है', उनसे पूछिए-क्या शरीर को उत्पाद बनाना आजादी है या आधुनिक गुलामी?

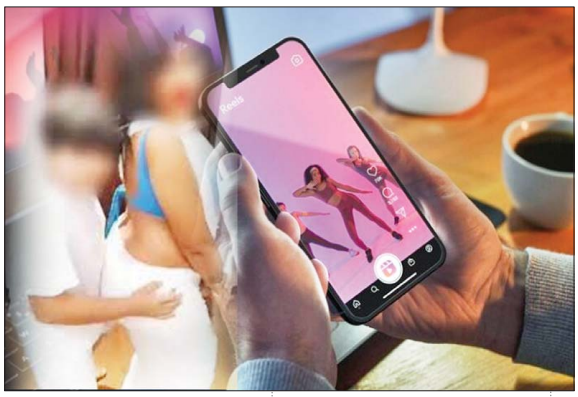

और यह दोष सिर्फ उन लड़कियों का नहीं है, जो ऐसी रील्स बनाती हैं। यह समाज का भी अपराध है-खास तौर पर पुरुषों का। यही पुरुष ऐसी वीडियो पर मिलियन-मिलियन व्यूज देते हैं, लाइक ठोकते हैं, फिर कमेंट में नैतिकता का भाषण भी पेलते हैं। एक ही वीडियो में पुरुष की आंखें भी डोलती हैं, और उंगलियां भी नैतिकता टाइप करती रहती हैं। यह दोगलापन बंद होना चाहिए।

सोचिए, क्या होगा जब कोई छोटी बच्ची यह सब देख कर बढ़ेगी? जब वह देखेगी कि ज्यादा अंग दिखाने वाली को ज्यादा लाइक मिलते हैं, तो वह किस दिशा में जाएगी? यह रील संस्कृति और स्त्रीत्व को छीन लेने की चुपचाप होती साजिश है। डिजिटल ग्लैमर की इस दौड़ में हम स्त्री को फिर से उस स्थान पर ले जा रहे हैं, जहां उसे सिर्फ 'देखे जाने' की वस्तु बना दिया गया था।

आजादी की सही परिभाषा वो होती है, जिसमें स्त्री खुद के लिए जीती है, न कि समाज के क्लिकबाजी वाले बाजार के लिए। एक लड़की सुंदर हो सकती है, फैशनेबल भी, लेकिन क्या जरूरी है कि वह हर बार अपनी देह को ही सेल करे? क्या सोच, क्या विचार, क्या चरित्र, क्या संघर्ष-ये सब सिर्फ उपन्यासों की बातें भर रह गई हैं?

दूसरी तरफ, जिन प्लेटफॉर्म्स को सामाजिक सुधार का औजार माना गया था-जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक-उन्हें हमने डिजिटल कोठा बना डाला है। यह केवल सरकार की असफलता नहीं है, बल्कि हम सब की चुप्पी का भी परिणाम है।

यह लड़ाई सिर्फ महिलाओं की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की होनी चाहिए जो एक स्वस्थ, गरिमामय, और नैतिक समाज की कल्पना करता है। जो चाहता है कि उसकी बेटी, बहन, दोस्त या पत्नी डिजिटल दुनिया में अपने टैलेंट से पहचानी जाए, न कि अपनी कमर के घुमाव से। अब समय आ गया है कि स्त्रियां खुद आगे बढ़ कर कहें-'बस बहुत हुआ।' रील्स बनानी हैं, बनाओ, लेकिन सोच से बनाओ। डांस करो, पर आत्मा से-न कि कैमरे की भूख से।

हंसाओ, सुनाओ, सिखाओ, जोड़ो-क्योंकि स्त्री सिर्फ आकर्षण नहीं, प्रेरणा होती है। और पुरुषों से भी यही कहना है-अब अपने क्लिक से समाज को मत चलाओ। अगर अश्लीलता बंद करनी है, तो उसे देखना बंद करो। रील्स वायरल तब होती हैं, जब उन्हें देखे जाने वाले अपनी आंख मूंद लेते हैं, और दिल खोल देते हैं।

एक बात और-जो लड़कियां यह सोचती हैं कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, वे यह समझें कि पसंद और उपभोग में फर्क होता है। एक को देख कर सम्मान मिलता है, दूसरे को देख कर हवस जागती है। आप खुद तय करें, आप कौन सी नजरों में आना चाहती हैं?

शायद अब वक्त है एक नई डिजिटल क्रांति का, जहां स्त्री के हाथ में मोबाइल हो-पर कैमरे के सामने न शरीर, बल्कि विचार हों-

'रील में न खोओ बहना, सोच को आवाज दो
जो तुम हो भीतर से, वही असली साज दो।
बदन की नहीं, बुद्धि की बनाओ पहचान,
यही है स्त्री की सबसे ऊंची उड़ान!'

■

एक औरत के पास उसकी सबसे बड़ी पूंजी आत्मसम्मान और विवेक होता है। जो लड़कियां एक्सरसाइज के नाम पर ऐसे कपड़े पहन रही हैं कि देखना भी शर्मिंदगी पैदा करे, वे शायद यह नहीं जानतीं कि वे नारी मुक्ति नहीं, बल्कि नारी बाजारीकरण का प्रचार कर रही हैं। शरीर दिखा कर पहचान बनाना कोई गर्व की बात नहीं। रील्स ही बनानी हैं, तो क्यों न ऐसी रील बनाओ जिसमें आपकी कला, मेहनत, सोच और संवेदना झलके? आज हर तीसरी रील में 'पिछवाड़ा' फ्रेम के बीच में है, कैमरा कमर पर जूम करता है, और कैप्शन होता है-'क्लासी एंड सेक्सी!' क्या यही स्त्री की परिभाषा बनती जा रही है? स्त्री आंदोलन कभी इस उद्देश्य से नहीं चला था

दादी-नानी की कहानियों में छिपा संदेश

पापा की परी या परा हो या दादी-नानी के नाती-पोते, दादी-नानी की कहानियां या लोरियां, आज बीते जमाने की बात हो गई हैं। दादी-नानी की कहानियां और लोरियों में सकारात्मक संदेश छिपा होता था। ये कोई मनोरंजन का माध्यम न होकर बच्चों के मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक समझ और जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देती थीं। अब वैश्विक अध्ययनों से साफ हो गया है कि इसके नकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। हांलाकि यह जेनरेशन जेड यानी 1996-2010 की पीढ़ी इस तथ्य को समझ नहीं पा रही है पर वैश्विक अध्ययनों ने साफ कर दिया है कि हालात यही रहे तो भावी पीढ़ी से संवेदनशीलता और अच्छे-बुरे की बात करना कोई मायने नहीं रखेगी।

दरअसल, आज के बच्चों की दुनिया दादी-नानी की कहानियां या लोरियों के स्थान पर मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर खुराफाती, हिंसात्मक, नकारात्मक, नित नये दुष्चक्र रचते और संबंधों को तार-तार करते सीरियलों या इसी तरह के एपिसोड से दो-चार हो रही है। बच्चों में हिंसा, बदले की भावना, ईर्ष्या, मिल बांटने के स्थान पर एकलखोरी और न जाने कितनी ही नकारात्मकता मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर चलने वाले सीरियलों, एपिसोडों और प्रसारित होने वाले गेम्स के माध्यम से परोसी जा रही है। परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बच्चों में रेवेंज की भावना कूट-कूट कर भरती जा रही है तो सहनशक्ति तो कोई मायने ही नहीं रखती। रिश्ते तार-तार हो रहे हैं, यह एक अन्य बात है। जेन जेड से सामाजिक समरसता की भावना से दूर होती जा रही है।

अपने में सिमटती यह पीढ़ी देश और समाज को क्या सकारात्मक दे पाएगी, यह सवालों के घेरे में आने लगा है। दरअसल, दादी-नानी की कहानियां भले ही उनमें से कुछ कपोल-कल्पना के आधार पर हो या फिर राजा-रानी की कहानियां हों, बच्चों के कोमल मन को संदेश देती थीं। इसके साथ ही उस जमाने में बच्चों को पढ़ने-पढ़ाने की आदत डाली जाती थी। लाइब्रेरी का कांसेप्ट तो बदल ही चुका है। आज लाइब्रेरी का अर्थ किराये के स्थान पर बनी केबिननुमा दड़बे में अपने घर से ले जाई गईं किताबों को रटने तक सीमित हो गया है। मोहल्लों में पांच-सात घरों की दूरी पर ही इस तरह की लाइब्रेरी मिल जाएगी जबकि एक जमाने में लाइब्रेरी के मायने ज्ञानवर्द्धक पुस्तकें, समाचार पत्र-पत्रिकाएं आदि को वहां बैठ कर पढ़ना और आवश्यकता होने पर लाइब्रेरी की सदस्यता प्राप्त कर पुस्तक आदि घर लाकर पढ़ना होता था। आज तो पढ़ने-पढ़ाने की आदत ही समाप्त होती जा रही है।

एक समय था जब वार्षिक परीक्षाओं के बाद बारी-बारी से दादी-नानी के घर धमाचौकड़ी होती थी। मजे की बात यह कि सभी मिजाज के हम-उम्र बच्चे होने से आपसी तालमेल की शिक्षा भी मिल जाती थी। फिर रात को दादी-नानी के साथ सोने और सोने से पहले कहानियां सुनने का सिलसिला चलता था। इससे कोमल मन को अलग तरह का ही संदेश मिलता था। चंदामामा, चंपक सहित बहुत सी बच्चों की पत्रिकाएं घर में होना और बच्चों के पास होना गौरव की बात माना जाता था।

खैर, यह बीते जमाने की बात हो गई है। अब तो गुगल गुरु ने लगभग सभी की पढ़ने-पढ़ाने की आदत को ही बदल कर रख दिया है। डिजिटल युग के इस दौर में सोशल मीडिया के माध्यम समूचे समाज को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। शहरीकरण के साथ ही संयुक्त परिवार का स्थान एकल परिवार ने ले लिया है, तो समय की कमी, अंधी प्रतिस्पर्धा, माता-पिता और परिजनों का लिखने-पढ़ने से परहेज, बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में ही जुटा देने और होमवर्क और ट्यूशन कल्चर पढ़ाई की दशा-दिशा को ही बदल दिया है।

अब तो स्कूलों में भी सभी संदेश मोबाइल पर ही देने का चलन चल गया है, और इससे स्कूल की डायरी का भी कोई महत्त्व नहीं रह गया है। ऐसे में मोबाइल ही माध्यम हो जाने से मोबाइल गेम्स से लेकर सोशल मीडिया के माध्यमों द्वारा बालमन को सीधे-सीधे प्रभावित किया जा रहा है। मनोविज्ञानियों और शिक्षा-समाज के क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों का दायित्व इससे और अधिक बढ़ गया है। एक समय था जब बच्चों को कोर्स की पुस्तकों के इतर मानसिक-चारित्रिक विकास वाले साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता था। आज पंचतंत्र, हितोपदेश, ईसप की कहानियां जेन जेड पीढ़ी भी नहीं जानती होगी तो फिर देश-विदेश के अन्य उत्कृष्ट साहित्य को पढ़ने-पढ़ाने की तो दूर की बात होगी। सोशल मीडिया, इंटरनेटी आभासी दुनिया, एकल और प्रतिस्पर्धात्मक पारिवारिक स्थिति से बालपन प्रभावित हो रहा है। अवकाश के दिनों में दादा-दादी या नाना नानी के पारिवारिक माहौल के स्थान पर किसी पिकनिक या पर्यटन स्थल पर जाना प्राथमिकता हो गया है। मानवीय संवेदनायुक्त नई पीढ़ी के लिए अभी से गंभीर सोच की आवश्यकता है। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों या स्क्रीन पर परोसी जा रही सामग्री में बदलाव लाना होगा ताकि नई पीढ़ी को संस्कारित किया जा सके।

प्रस्तुति : डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

व्यंग्य | विनोद कुमार विक्की

अपराध का भी सीजन होता है भाई

मुझ अकिंचन को अब तक यही ज्ञात था कि सीजन सिर्फ शीत, वसंत, बरसात, गर्मी, लग्न, पितृ पक्ष आदि का ही होता है। मौसम के अनुरूप ही इन सीजन में विशिष्ट गतिविधियां एवं विशिष्ट जीव-जंतुओं के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। वसंत में कोयल, बरसात में मेंढक, चुनावी सीजन में नेता का दिखाई देना तथा लग्न में वैवाहिक कार्यक्रम, पितृ पक्ष में श्राद्ध एवं तर्पण की गतिविधियां सहज ही देखने और सुनने को मिल जाती हैं। यद्यपि सीजन सदैव प्राकृतिक घटनाओं से प्रेरित और प्रभावित होता है, तथापि हाल के दिनों में मानवीय कृत्यों से प्रेरित कोरोना एवं युद्ध जैसे कृत्रिम सीजन को देखने और भुगतने का सौभाग्य भी हम मानवों को प्राप्त हुआ है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, हर सीजन का रीजन होता है। आज के प्रसंग में रीजन सहित ऐसे नये-नवेले सीजन की चर्चा करने वाला हूं, जिसकी खोज इसी जुलाई माह में आर्यभट्ट की भूमि पर हुई है। देश का एक ऐसा अद्भुत प्रदेश जहां अप्रैल-मई-जून के त्रैमासिक सीजन में मानसून आवे न आवे, लेकिन मर्डरर और अनलिमिटेड मर्डर का सीजन आ जाता है।

इस सीजन में प्राकृतिक बरसात की बजाय मानवकृत रक्तपात की घटनाएं घटित होने लगती हैं। हाहाकार और त्राहिमाम वाले इस सीजन में अपराध और अपराधियों का मनोबल भ्रष्टाचार और महंगाई की तरह बढ़ जाते हैं। ना, ना, ना... ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा तो इस प्रदेश के कानून के रखवालों का मानना है।

दरअसल, प्रदेशवासियों को इस नवसृजित सीजन स्वरूप दिव्य ज्ञान की प्राप्ति जुलाई माह के उत्तरार्द्ध में प्रदेश महारक्षक के मुखारविंद से उच्चारित शब्दों एवं अभिव्यक्ति से हुई। प्रदेश वासी प्राकृतिक बाढ़, सुखाड़ तथा मानव जन्य पलायन सीजन से तो वर्षों से परिचित और अवगत थे, लेकिन अब जाकर उन्हें पता चला कि इस प्रांत में अपराध का भी एक सीजन होता है।

आशय यह है कि इस सीजन में मेहनतकश बेरोजगार असमाजिक कृषकों द्वारा अपराध की बुआई, कट्टा, बम बारूद की सिंचाई और लेवी, रंगदारी, हत्या स्वरूप फसलों की जम कर कटाई की जाती है। प्रदेश रक्षकों के मुताबिक बरसात आने पर आपराधिक घटनाएं बंद हो जाती हैं। हालांकि जल-जमाव अथवा रेन कोट की अनुपलब्धता के कारण 'मासूम' अपराधी बरसात में अपने आपराधिक कृत्यों को अंजाम नहीं दे पाते, यह शोध का विषय है। बहरहाल, प्रवासी मुकद्दर वाले इस प्रदेश में पहले से ही आधी आबादी रोजी-रोजगार के लिए विभिन्न प्रांतों में जीवन व्यतीत कर रही है। यदि अपराध का त्रैमासिक सीजन कानून सम्मत है, तो भी रही-सही आबादी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपराध सीजन अर्थात अप्रैल-मई-जून माह में प्रदेश से बाहर त्रैमासिक प्रवासी के रूप में तथा शेष नौ माह मौलिक प्रदेश में जीवन का आनंद लेते हुए अपनी जान और माल की रक्षा करने का शानदार विकल्प अभी उनके पास है। ■

राग रंग | आलोक पराड़कर

नाटकों की बरसात

देश के तमाम हिस्से सावन की बरसात में भींगे हुए हैं, लखनऊ में बारिश के बीच नाटकों की प्रस्तुतियां भी खूब हो रही हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी ने एक पखवाड़े के भीतर ही पांच नाटकों के सात प्रदर्शन किए हैं। इन्हें नगर के गाडगे जी महाराज सभागार, कला मंडपम और अकादमी के ब्लैक बॉक्स थिएटर में प्रस्तुत किया गया। 7 जुलाई को 'किस्सा किस्सों का', 9 जुलाई को 'चंदा बेड़नी', 14 जुलाई को 'एक और द्रोणाचार्य', 16 एवं 17 जुलाई को 'मकान नंबर 7, मनाली' मंचित किए गए जबकि 17 जुलाई को ही 'संक्रमण' के दो प्रदर्शन भी हुए। इनमें से अधिकतर नाटक अकादमी की बाल एवं युवा कार्यशाला में तैयार किए गए। केवल 'मकान नंबर 7, मनाली' अकादमी के रंगमंडल की प्रस्तुति थी।

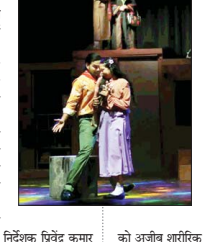

अमूमन कार्यशालाओं के समापन पर एक ही नाटक मंचित होता रहा है, लेकिन युवा कार्यशाला में इस बार तीन नाटक तैयार किए गए जिससे सभी प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिल सके। 21 मई से 16 जुलाई तक चली कार्यशाला में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक वामन केंद्रे, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक टीकम जोशी, फिल्म-टीवी कलाकार डॉली अहलूवालिया एवं अनिल रस्तोगी, पंजाब विश्वविद्यालय के भारतीय रंगमंच विभाग की अध्यक्ष नवदीप कौर, ध्वनि विशेषज्ञ एस. मनोहरन, संगीत विशेषज्ञ तेंजिदर गिल, नृत्य संरचनाकार शिल्पिका वारदोलोई को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था जबकि अकादमी के अध्यक्ष डॉ. रतिशंकर त्रिपाठी, निदेशक विपिन कुमार, प्रशिक्षक शुभदीप राहा एवं सुमित श्रीवास्तव तथा रंगमंडल के प्रबंधक एवं कार्यशाला के निर्देशक प्रिवेंद्र कुमार सिंह ने भी प्रशिक्षण दिए।

'किस्सा किस्सों का' बाल कार्यशाला की प्रस्तुति थी, जिसे कार्यशाला के प्रशिक्षक वॉल्टर पीटर ने निर्देशित किया था। यह कार्यशाला 1 से 30 जून तक आयोजित की गई थी । युवा कार्यशाला में तैयार 'चंदा बेड़नी' को नीरज कुशवाहा ने निर्देशित किया जो प्रसिद्ध रंगकर्मी अलख नंदन का चर्चित नाटक है, जिसमें प्रेम का समाज की जातिगत व्यवस्था से टकराव है। इसे नौटंकी शैली में मंच पर उतारा गया। प्रिवेंद्र कुमार सिंह के निर्देशन में मंचित 'एक और द्रोणाचार्य' शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है। शंकर शेष के इस नाटक में प्रोफेसर अनिरुद्ध और महाभारत के द्रोणाचार्य की कहानियां समानांतर चलती हैं। दोनों कहानियों में शिक्षक अपने स्वार्थ के लिए सिद्धांतों से समझौता करता और अन्याय को प्रोत्साहित करता है। 'संक्रमण' लखनऊ के ही कथाकार कामतानाथ की कहानी है, जिसे कई प्रसिद्ध कलाकारों ने पूर्व में प्रस्तुत किया है। अक्षय कुमार मेश्राम के नाट्य रूपांतरण और निर्देशन में प्रस्तुत यह नाटक दिखाता है कि किस प्रकार समय के बदलाव के साथ हम वही व्यवहार करने लगते हैं, जिसके हम कभी खिलाफ होते हैं। अकादमी का रंगमंडल 1988 में स्थापित हुआ था। कुछेक वर्षों के किंचित व्यवधानों के बाद यह पुनः सक्रिय है।

अकादमी के प्रशिक्षक शुभदीप राहा के निर्देशन में रंगमंडल द्वारा प्रस्तुत 'मकान नंबर 7, मनाली' आधुनिक नाटकों के पुरोधा इब्सन के 'जॉन ग्रैब्रियल बोर्कमैन' का भारतीय परिवेश में रूपांतरण है। मनाली के बर्फीले मौसम में चिट फंड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी की सजा काट कर लौटे विक्रम का पत्नी चंद्रा और प्रेमिका ईशा, जो चंद्रा की बहन है, के साथ अतीत और भविष्य को लेकर वाद-विवाद होता है। बेटे राज को लेकर उनके सपने हैं, लेकिन वह इन्हें छोड़ तलाकशुदा अमीर स्त्री सोनिया के साथ विदेश चला जाता है। नाटक का अंत चौंकाता है। वैसे शुभदीप के नाटक प्रायः अपनी बुनावट में रहस्य-रोमांच लिए होते ही हैं। वे कलाकारों से काफी मेहनत भी कराते हैं। तीनों मुख्य पात्रों का अभिनय सशक्त है, और दर्शकों को बांधे रखता है, वहीं मंच अभिकल्पना, संगीत और इन सबके साथ प्रकाश व्यवस्था, जो अकादमी के इन सभी नाटकों में हिमांशु बी. जोशी की थी, नाटक को और प्रभावी बनाती है। लेकिन पूरे नाटक का एक स्थायी भाव चीखने-चिल्लाने का दिखता है। तीनों मुख्य कलाकारों को अजीब शारीरिक मनोदशा में और कभी-कभी पागलों जैसा व्यवहार करते दिखाया गया है। चंद्रा और ईशा, दोनों अपनी शारीरिक मुद्राओं का औचित्य भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसी प्रकार विक्रम के स्वप्न में आए पात्रों की हरकतें भी अजीब हैं। यह सब कुछ अतिरंजित लगता है। शायद इसी कारण कलाकारों के अच्छे अभिनय, प्रभावी मंच एवं प्रकाश व्यवस्था से अपनी पूरी बुनावट में नाटक का जो गहरा असर दर्शकों पर होना चाहिए, उसमें कहीं कमी रह जाती है। नाटक के दोनों प्रदर्शनों की प्रमुख भूमिकाओं में अप्सरा खान, श्रुतिकीर्ति सिंह, अर्घ्य सामंत, अनिल चौधरी, अंशू साहू, वैष्णवी सेठ, भावना द्विवेदी, आशुतोष जायसवाल, अमित हरिश्चंद्र, श्वेता सोधिंया, अमृता सिंह थे। ■

कैनवस | जय त्रिपाठी

कला जीवन में लोक चेतना

कलाकारों, कला लेखकों और कला प्रेमियों को एक साथ लाती कला गोष्ठी ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान का महत्त्वपूर्ण मंच होती है जो कलाकार और कला के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कुछ इसी प्रारूप के साथ विगत सप्ताह आयोजित कला गोष्ठी पूरी तरह से गंभीर मंथन का स्वरूप लेकर विचारों, शोधों और रचनाओं को साझा करते हुए नये विचारों को जन्म दिलाती गई। डॉ. हरिवंश राय बच्चन का कथन भी है कि 'गोष्ठी एक ऐसा मंच है जहां विचारों का आदान-प्रदान होता है, और ज्ञान की वृद्धि होती है।' इसी दिशा को और गति देते हुए एक नई कंचन कला दीर्घा की ओर कदम बढ़ाती है। इस दीर्घा का शुभारंभ लोक कलाकारों के चित्रों की प्रदर्शनी एवं लोक कला गोष्ठी के विशेष सत्र के आयोजन द्वारा किया गया। विगत कई वर्षों से गुरुग्राम स्थित 'विमला आर्ट फोरम' की संस्थापक एवं संरक्षक कंचन मेहरा एवं दिलीप शर्मा की रचनात्मक दूरदर्शिता के साथ इस फोरम को निरंतर एक नई दिशा देने को प्रयासरत रही है जो यह भाव देता है कि कलाकारों को समाज के प्रति जागरूक होना चाहिए और अपनी कला के माध्यम से समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। संक्षेप में कहें तो कला को मानव भावों से परिपूर्ण और समाज को बेहतर बनाना है।

हिन्दी साहित्य के महान विद्वान समादृत आलोचक, निबंधकार, साहित्य-इतिहासकार और अनुवादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल कला और नैतिकता को एक दूसरे से अलग नहीं मानते थे। उनका मानना था कि कला को नैतिक मूल्यों का समर्थन करना चाहिए और समाज को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहिए। कुछ इसी भाव से देश के मूर्धन्य कलाकार, कला चिंतक अशोक भौमिक ने अपने बेबाक राय रख कर लोक कलाकारों की मूल कठिनाइयों पर सवाल खड़े किए और विश्व को एक देश के स्वरूप में देखने की बात कही...कि लोक कलाकारों की जीवन स्थिति की दिशा में सरकारों ने कोई पहल नहीं की और न ही की जाती है जैसा चिंतनीय पहलू को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया। लोक चित्रों से सुसज्जित गैलरी के शुभारंभ के साथ आयोजित कला चर्चा में पूरी तरह से गंभीर मंथन में भौमिक ने लोक कलाकारों और आधुनिक कलाकारों में भेद को न करने को कहते हुए कहा कि हम लोक कलाकारों को समानता का दर्जा देने की बात करते हैं किंतु उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें कलाकार का दर्जा दिया जाए और न ही कभी खुद को कलाकार कहलाने का आग्रह किया। भौमिक ने कला पुरस्कारों को भी निशाना बनाया। लोक कलाओं और आधुनिक कला के उद्देश्य में अंतर को स्पष्ट करते हुए वह कहते हैं कि लोक कलाएं जीवन से सीधी जुड़ी होती हैं। आधुनिक कलाकार की पहचान है, उसके नाम से होती है किंतु लोक कलाकार के साथ ऐसा नहीं हुआ। वहीं लोक कला व कलाकारों के सर्वागीण विकास का बीड़ा उठाने का संकल्प लिए युवा पीढ़ी के सुनील कुमार ने लोक कला व कलाकारों की संवेदनशील दृष्टि व उनकी संभावना पर विचार पर प्रकाश डाला।

लोक कलाकारों के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए उनकी आर्थिक स्थिति की बात करते हुए शांति देवी और जमुना देवी की कठिन कला यात्रा का उदाहरण दिया। इन जैसी कलाकारों ने सामाजिक संरचना को भी रचा है, और कहा कि अनेक लोक कलाकार महाराष्ट्र में होते हुए दलित आंदोलन से लेकर गिरीश कर्नाड के नाटकों तक से प्रभावित रहे जो बदलाव का संकेत है। कला पत्रिका 'आर्ट न्यूज इंडिया' के संपादक एवं वरिष्ठ कलाकार वेद भारद्वाज ने समकालीन कलाकारों व लोक कलाकारों के स्वरूप पर विचार करते हुए अपनी बात कही। भारद्वाज ने लोक कलाओं की समस्याओं की बात करते हुए उसमें बदलाव न होने की बात कही। उन्होंने कहा कि आधुनिक कलाकार और कला बाजार लोक कलाओं को बदलने से रोकते हैं, और चाहते हैं कि लोक कलाकार वही सब रचते रहें जो हजारों सालों से रास्ते आए हैं। देश के वरिष्ठ कलाकार कला लेखक सुमन कुमार सिंह ने लोककला के स्वरूप की निरंतर निश्चित यात्रा के विषय में भी हमें सोचना होगा, इस ओर ध्यान आकर्षित किया। सुमन कुमार सिंह ने इस अवसर पर लोक कलाओं के साथ लोक जीवन की परंपराओं के विस्मरण की बात कही। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में अच्छा काम हो रहा है। फिर भी लोक मानने वाले विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग शामिल हैं। गहन मंथन से यह विमर्श आया कि इस तरह के संवाद होने की अधिक आवश्यकता है। कुल मिलाकर भारतीय लोक कला को मुख्यधारा की कलात्मक चेतना में लाया जाने वाला यह प्रयास संभावना जगाता है। ■

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

बम धमकियां-असहज होता समाज

दिल्ली, बैंगलुरु और कुछ अन्य महानगरों में लगातार बम रखे जाने की धमकियां भले ही फर्जी साबित हो रही हैं लेकिन ऐसी धमकियों ने न केवल पुलिस प्रशासन को परेशान कर दिया है बल्कि स्कूली बच्चों और अभिभावकों को भी असहज बना दिया है। वैसे तो फर्जी धमकियों का सिलसिला उड़ानों तक भी पहुंच चुका है। पुलिस और सुरक्षा एजैंसियों को ऐसी धमकियों के बाद पूरी कवायद करनी पड़ती है तुरन्त बम खोजी दस्ते बुलाने पड़ते हैं। चप्पे-चप्पे की तलाशी लेनी पड़ती है। चाहे कुछ मिले न मिले ऐसी धमकियों को नजरंदाज भी नहीं किया जा सकता। स्कूलों में बम होने का ई-मेल मिलते ही क्लास रूम खाली करवाए जाते हैं। बच्चों को सतर्कतापूर्वक बाहर निकाला जाता है। अभिभावक खबर पाते ही बदहवास हो कर स्कूलों की तरफ भागते हैं। बच्चों को सुरक्षित जगह पर इकट्ठा करना, अभिभावकों को जानकारी देना, स्कूलों के लिए सिरदर्द बन चुका है तो दूसरी तरफ माता-पिता अपना काम छोड़कर बच्चों की चिंता में स्कूलों की तरफ बार-बार भागना मुसीबत बन चुका है। स्कूलों को धमकियां पहले भी मिलती रही हैं। कभी यह कहा गया कि यह कुछ स्कूली बच्चों की शरारत है। कभी कुछ गिरफ्तारियों की भी खबर आती है। कई बार धमकियों की गुत्थी सुलझाने का दावा भी किया जाता रहा है। अभी तक यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि यह कोई शरारत है, साजिश है या फिर कोई बड़ा प्रयोग है। पिछले वर्ष दिल्ली समेत एनसीआर के स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल रूस से भेजे जाने की पुष्टि हुई थी। भारत की सुरक्षा एजैंसियां ऐसे ई-मेल के मामले में उलझ कर रह गई हैं। एजैंसियां तय नहीं कर पा रहीं कि इतनी बड़ी संख्या में धमकियां मिलने का क्या कारण है? क्या ऐसा करने वाले लोग भारत के भीतर हैं या भारत के दुश्मन किसी प्रकार का बड़ा प्रयोग कर रहे हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि किसी स्कूल में बम धमाका हो जाए तो क्या हो सकता है। कोई एक व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता। हो सकता है कि कोई संगठित गिरोह इसके पीछे हो। धमकी भरे ई-मेल के स्रोत को ढूंढना आज के दौर में आसान नहीं है। ऐसा करने वाले लोग डार्क वेब और बीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कई परतें होती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी इतनी जटिल हो चुकी है कि अगर धमकी किसी विदेशी सर्वर का इस्तेमाल करके भेजी गई है तो स्रोत ढूंढना बहुत मुश्किल है।

कभी यह कहा गया कि यह कुछ स्कूली बच्चों की शरारत है। कभी कुछ गिरफ्तारियों की भी खबर आती है। कई बार धमकियों की गुत्थी सुलझाने का दावा भी किया जाता रहा है। अभी तक यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि यह कोई शरारत है, साजिश है या फिर कोई बड़ा प्रयोग है। पिछले वर्ष दिल्ली समेत एनसीआर के स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल रूस से भेजे जाने की पुष्टि हुई थी। भारत की सुरक्षा एजैंसियां ऐसे ई-मेल के मामले में उलझ कर रह गई हैं। एजैंसियां तय नहीं कर पा रहीं कि इतनी बड़ी संख्या में धमकियां मिलने का क्या कारण है? क्या ऐसा करने वाले लोग भारत के भीतर हैं या भारत के दुश्मन किसी प्रकार का बड़ा प्रयोग कर रहे हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि किसी स्कूल में बम धमाका हो जाए तो क्या हो सकता है।

देश के धार्मिक स्थलों को भी आरडीएक्स से उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं। स्वर्ण मंदिर परिसर को उड़ाने की धमकी देने के मामले में बीटेक इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठता है कि क्या बीटेक इंजीनियर मानसिक रूप से अस्वस्थ तो नहीं। निष्कर्ष कुछ भी हो ऐसी धमकियों से धार्मिक तनाव पैदा होने का खतरा बना रहता है। बम की धमकियों और अफवाहों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे सामाजिक अशांति, हिंसा और यहां तक कि आर्थिक नुक्सान भी हो सकता है। स्कूलों में बम की धमकियों का नकारात्मक प्रभाव न केवल बच्चों पर बल्कि उनके माता-पिता और समाज पर भी पड़ रहा है। बम की धमकियां मानसिक रूप से हर किसी पर दबाव बना रही हैं। ऐसे लगता है कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो समाज ही दबाव में आ जाएगा। स्कूली बच्चों के अभिभावक कह रहे हैं कि ऐसी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह भेड़िया आया, भेड़िया आया जैसी स्थिति भी हो सकती है। ऐसे में अभिभावक तो फिक्रमंद रहेंगे ही, दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधकों के लिए भी सुरक्षा एक बड़ा मसला बन चुका है।

स्कूल परिसरों में डर का वातावरण बन चुका है। दहशत फैलाने वाले एक साथ 50-50 स्कूलों को धमकाते हैं तो डर में शिक्षा व्यवस्था कैसे बाधा रहित बन पाएगी। कई तरह की बातें सुनाई दे रही हैं कि स्कूलों के आसपास बम निरोधी दस्ते, मैडिकल टीमें, एम्बुलैंस और पुलिस की टीमें तैयार होनी चाहिए। स्कूलों के आगे हॉकर्स नहीं होने चाहिए। स्कूलों के बाहर जगह खाली होनी चाहिए ताकि कोई भी इमरजैंसी होने पर स्कूल खाली करवाने में दिक्कत न आए लेकिन यह सब बातें दिल्ली जैसे महानगर में सम्भव हो सकती हैं? दिल्ली के स्कूलों के बाहर रेहड़ी-पटरी वालों और ई-रिक्शा का जमघट देखकर ही बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। धमकियों का यह सिलसिला अब बेलगाम हो चुका है। इनके पीछे कौन है उसकी पहचान होनी चाहिए। इनके पीछे अगर कोई शरारती दिमाग काम कर रहा है तो उसका भी ईलाज किया जाना जरूरी है। स्कूल प्रबंधकों को अपने स्टाफ को भी सेफ्टी ट्रेनिंग देनी होगी, तो दूसरी ओर पुलिस प्रशासन को भी साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए मजबूत नेटवर्क बनाना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूली बच्चों और अभिभावकों को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाया जाए ताकि बार-बार पैदा हो रहे ऐसे हालातों में वह मजबूती से निपट सकें। न तो हम भयभीत समाज चाहते हैं और न ही हम लापरवाह समाज चाहते हैं, इसलिए सजगता बहुत जरूरी है।

संयुक्त परिवार की महत्ता

"दुनिया के शोर में हम सभी खुद को इतना खो चुके हैं,
कि अपने अंतर्मन की आवाज से बहुत दूर हो चुके हैं,
संयुक्त परिवार की महत्ता को खो चुके हैं,
और एकल परिवारों में बच्चे जीवन जीने के लिए
मजबूर हो चुके हैं...।।"

गीता पाढा

क्या श्रृंगला विदेश मंत्री बनेंगे ?

देखो अपनी ख्वाहिशों के बोझ में,
मैं जला-बुझा हूं बहुत
बकी है ये हसरत कि रोशनी बन कर
जलूं सुबह होने तक'

क्या डा. हर्षवर्द्धन श्रृंगला के रूप में देश को नया विदेश मंत्री मिल सकता है? पूर्व विदेश सचिव श्रृंगला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पिछले दिनों राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।

डा. श्रृंगला कई कारणों से पीएम मोदी के बेहद भरोसेमंदों में शुमार होते हैं। अमेरिका से भी इनके निजी ताल्लुकात बेहतर बताए जाते हैं, जब अमेरिका में बतौर भारतीय राजदूत इनका कार्यकाल पूरा हुआ था तब तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनके लिए व्हाइट हाउस में 'फेयरवैल पार्टी' रखी थी। कहते हैं जब ये अमेरिका में भारत के राजदूत थे तो इन्होंने 2019 में 'हाउडी मोदी' की संकल्पना को मूर्त रूप देने का काम किया था। यह वही दौर था जब मोदी व ट्रंप का दोस्ताना अपने परवान पर था। श्रृंगला अपने रिटायरमेंट के बाद भी समय-समय पर मोदी को भारत की विदेश नीति को लेकर ब्रीफ करते रहे हैं। मोदी ने श्रृंगला को ही भारत में आयोजित होने वाले जी-20 का चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया था। पिछले दिनों 'ऑपरेशन सिंदूर' की वकालत करने भारतीय संसदों के जो प्रतिनिधिमंडल विदेश गए थे, उनमें विशेष तौर पर श्रृंगला को भी शामिल किया गया था। सरकार श्रृंगला को एस. जयशंकर की कुर्सी पर बिठाना चाहती है।

मानसून सत्र के लिए विपक्ष का हमलावर रुख

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक आहूत है, इस सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष पर खासा हमलावर रहने वाला है, इस बात के संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। एक ओर जहां संयुक्त विपक्ष सरकार को घेरने को चाक चौबंद तैयारियों में जुटा है, वहीं इन बातों से बेपरवाह मोदी के नेतृत्व वाला सत्ता पक्ष मानसून सत्र में विधेयकों की बारिश करना चाहता है। सूत्र बताते हैं कि सोमवार से शुरू होने वाले इस सत्र में सत्ता पक्ष कम से कम

8 विधेयकों को लेकर आना चाहता है। इसमें जीएसटी बिल, मणिपुर संशोधन बिल, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक इसके अलावा इसी सत्र में न्यू इंकम टैक्स बिल भी लाया जा सकता है। इस मसले पर भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली लोकसभा प्रवर समिति की रिपोर्ट सत्र शुरू होते ही पेश की जा सकती है। वहीं विपक्ष पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में चुनाव पूर्व चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण (सर) जैसे मुद्दों को सदन में उछालने की तैयारियों में है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को आधार बनाकर भी सरकार को घेरा जा सकता है जिसमें ट्रंप ने दावा किया था कि 'भारत-पाक के दरम्यान उन्होंने ही युद्ध विराम करवाया था।' इसके अलावा अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर भी विपक्ष सरकार से कई गंभीर सवाल पूछ सकता है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने भले ही फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए नए सिरे से न्याय की गुहार लगाई हो, पर माना जाता है कि उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सदन एक समिति के गठन की सिफारिश कर सकता है। समिति के लिए भी तीन महीनों की तय समय सीमा में अपनी रिपोर्ट देनी जरूरी होगी। विपक्ष न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग लाने के लिए कमर कस चुका है, पर गेंद फिलहाल उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पाले में है जो शायद ही विपक्ष की मांगों पर कान धरें। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की तैयारी है, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर काफी हो-हल्ला मचा सकता है। विपक्ष पहले भी पहलगाम हमले को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग के साथ प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख चुका है, पर विपक्ष की डिमांड अनसुनी करते हुए सरकार ने संसद के मानसून सत्र की घोषणा कर दी। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए एक के बाद एक कई बैठकें कर रहा है, पहले सोनिया गांधी के घर एक बैठक हुई, इसके बाद कई विपक्षी पार्टियों का कांग्रेस के साथ ऑनलाइन बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ, इनमें से एक बैठक में हैरतअंगेज तरीके से शिवसेना उद्धव की पार्टी भी शामिल हुई, कई कयासों को धत्ता बताते कि उसने अंदरखाने से भाजपा से हाथ मिला लिया है।

क्या इस भाजपा सीएम की गद्दी जाने वाली है?

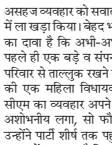

अभी कुछ समय पहले ही तो इस अनजाने से भगवा चेहरे की ढोल-नगाड़ों की थाप पर ताजपोशी हुई थी, कई हैवीवेट नेताओं, नेत्रियों को चित्त करते इन्होंने सियासी बियावां से सत्ता के

जगमगाते रंगमंच का सफर तय किया था। अब इनकी छोटी-छोटी गलतियां इन पर भारी पड़ने लगी हैं, पहले एक चैनल की महिला रिपोर्टर के साथ इनकी सीडी की गुपचुप चर्चा सुनी गई। फिर इनकी बेजा आदतों से परेशान होकर इनकी पार्टी की ही कुछ महिला विधायकों ने पार्टी शीर्ष के समक्ष इनके असहज व्यवहार को सवालों के कठघरे में ला खड़ा किया। बेहद भरोसेमंद सूत्रों का दावा है कि अभी-अभी कुछ रोज पहले ही एक बड़े व संपन्न राजनैतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली भाजपा की एक महिला विधायक को अपने सीएम का व्यवहार अपने प्रति किंचित अशोभनीय लगा, सो फौरन यह बात उन्होंने पार्टी शीर्ष तक पहुंचा दी।

सूत्रों का दावा है कि एक दफे जब यह महिला विधायक अपने सीएम से किसी कार्यवश मिलने पहुंची तो सीएम साहब ने उन्हें छेड़ते हुए कह दिया-'क्या बात है आजकल तो आप मिलती ही नहीं?' महिला विधायक ने फौरन प्रतिवाद करते हुए कहा-'क्या बात करते हैं सर, पिछले कुछ दिनों में ही मैं आप से चार बार मिल चुकी हूं।' इस पर सीएम साहब ने चुटकी लेते हुए कहा-'आप जब भी मिलती हो कोई काम लेकर ही आती हो, कभी बिना काम के भी मिला करो।' यह बात और सीएम साहब की भाव-भंगिमाएं विधायक महोदया को बेहद नागवार गुजरी और उन्होंने फौरन इस बात की शिकायत दिल्ली स्थित पार्टी के एक बड़े नेता से कर दी। फिर क्या था अगले ही कुछ रोज में सीएम साहब को दिल्ली से बुलावा आ गया, उनकी जबर्दस्त क्लास लगाई गई, उनके परफॉरमेंस और लोकप्रियता में लगातार गिरते ग्राफ का हवाला देकर उनसे रुखसती के लिए तैयार रहने को कहा गया है। पर भगवा राज में 'यथास्थितिवाद' से निपटना भी तो एक बड़ी चुनौती है।

'रामराज्य'' की रेस में सीता

जैसे-जैसे भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा के पल धीरे-धीरे करीब आ रहे हैं, मैदान में कई नए रणबांकुरे भी चहलकदमी करते देखे जा रहे हैं। जैसे अभी कुछ रोज पहले ही एकदम से अचानक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नई दिल्ली स्थित उनके घर पहुंच गए।

समझा जाता है कि इन दोनों नेताओं ने डेढ़ घंटे तक किसी अहम विषय पर गंभीर मंत्रणा की, फिर नड्डा वापिस लौट आए। एक प्रमुख टीवी न्यूज एजेंसी ने बकायदा इस खबर को चला भी दिया, पर महज़ डेढ़ मिनट के अंदर इस खबर को हटा लिया गया। कहने वाले अब दावा कर रहे हैं कि निर्मला सीतारमण को भाजपाध्यक्ष बना भाजपा एक तीर से कई शिकार कर सकती है, एक तो भाजपा पहला महिला अध्यक्ष देने का श्रेय ले सकती है। निर्मला खुद तमिलनाडु से हैं और इसके पति आंध्र से ताल्लुक रखते हैं। इस दाव से भाजपा दक्षिण में अपना भगवा गढ़ मजबूत करने का उपक्रम भी साध सकती है। बाकी जवाब तो समय ही देगा।'

... और अंत में

बिहार में अकड़ों के नेता के तौर पर भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले प्रशांत किशोर तेजी से उभर रहे हैं। कहा जाता है कि पिछले दिनों पीके ने अपनी नवगठित 'जन सुराज पार्टी' की संभावनाओं को टटोलने के लिए बिहार में एक राज्यव्यापी जनमत सर्वेक्षण करवाया। उसके नतीजों ने उन्हें एक नई राजनैतिक संजीवनी दी है। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जन सुराज पार्टी का वोट शेयर मौजूदा तारीख में 6 फीसदी के आसपास आ गया है। पहले यह वोट शेयर 2 फीसदी बताया जा

रहा था, पीके जानते हैं कि 6 फीसदी वोट शेयर के निहितार्थ बहुत गहरे हैं, वे सिर्फ लालू-कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि भाजपा-जदयू के लिए भी एक चुनौती बन कर उभर रहे हैं।

राज्य की बदली बयार को देखते हुए नीतीश भी भाजपा के सम्मुख अड़ गए हैं कि 'सीट शेयरिंग से पहले उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए', नीतीश ने सीटों के बंटवारे को लेकर 'सीटिंग-गेटिंग' का फार्मूला मानने से इंकार कर दिया है। पीके पहले भविष्यवाणी कर चुके हैं कि इस बार नीतीश 25 सीटों पर ही सिमट जाएंगे। प्रशांत इस बात से भी खुश हैं कि बिहार के लोग उन्हें पीके के बजाए इन दिनों 'पांडेय जी' का संबोधन दे रहे हैं, जो कि उनके जातीय मान्यता की स्वीकार्यता को दर्शाता है।

बेटियों बच के रहो...

श्रीमती किरण चोपड़ा
डायरेक्टर- पंजाब केसरी दैनिक समाचार लि.
चेयरपर्सन- वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब
मुख्य संरक्षिका- चौपाल
सदस्या- राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल, एकल
संरक्षिका- भारतीय लोक विकास परिषद
f/kiranchopra01
kiranchopra@punjabkesari.com
kiranchopradesk@gmail.com

समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे समाज को क्या हो रहा है। रोज नई घटनाएं सामने आती हैं। कहीं बेटी को मार दिया, कहीं रेप हो गया। जहां बेटियां आगे बढ़ रही हैं वहीं बेटियों के साथ अन्याय या दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं।

अभी मैंने अपने बच्चों के साथ बैठकर नेटफ्लिक्स पर डिप्लोमेट पिक्चर देखी। क्या पिक्चर है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यही सोचकर ऐसे ही भारतीय लड़कियां कैसे फंसती हैं और उनका क्या नतीजा होता है। यह पिक्चर सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें सुषमा जी के विदेश मंत्री होने के नाते उनकी एफर्ट और कन्सर्न बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है। इसलिए अभी तक लोग उन्हें याद करते हैं और भारतीय एम्बेसडर का भी बहुत ही अच्छा रोल और मेहनत दिखाई गई है। अगर यह एम्बेसडर हैं तो मैं तो इनको मिलना चाहूंगी। ऐसी पिक्चर देखकर मेरे दिल-दिमाग में इतना असर हुआ कि मैं सो नहीं पाई कि ऐसे न जाने कितनी लड़कियां ऐसे लोगों के जाल में फंसती होंगी। एक तो अपनी सूझबूझ और भारत सरकार (सुषमा जी और एम्बेसडर) की मेहनत से बच गई। न जाने कितनीं बच ही नहीं पाती होंगी।

अभी इस फिल्म से ही नहीं उभर पा रही थी कि मैंने अखबार में एक यूपी के बाबा के बारे में पढ़ा, टीवी में भी देखा कि कैसे एक बाबा एक अवैध धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह गरीब और भोली-भाली लड़कियों को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहा था। वो एक संगठित गिरोह चला रहा था जो गरीब और दलित वर्ग की लड़कियों को निशाना बनाता था। वह उन्हें आर्थिक लालच और विदेश भेजने का सपना दिखाकर धर्म परिवर्तन कराता था। उसे कई इस्लामिक देशों से भारी फंडिंग मिल रही थी। इस फंडिंग का उपयोग वह अपने धर्मांतरण रैकेट को चलाने और लड़कियों को बहला-फुसलाने के लिए करता था। यही नहीं उसने अपने युवाओं की एक कमांडो फोर्स भी तैयार कर रखी थी जो उसके इशारे पर वारदातों को अंजाम देते थे।

धन्यवाद और शुक्र है यूपी एटीएस जिसने इसे गिरफ्तार किया। जांच में कई बातें सामने निकल कर आ रही हैं। एक साधारण व्यापार से शुरूआत करने वाले व्यक्ति ने एक धार्मिक गिरोह का निर्माण किया, जिसमें महिलाओं को धर्म परिवर्तन के नाम पर आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रभावित किया गया। बहुत सी महिलाओं और लड़कियों ने दुपट्टा बांधे यानि मुंह ढककर आपबीती सुनाई।

मेरा दिल यह सच देख-सुनकर इतना दुखी है कि समझने की कोशिश भी कर रही हूं तो यही समझ आ रहा है कि गरीबी, बेरोजगारी और कुछ उम्र ऐसी जो लड़कियां प्यार में बह जाती हैं। प्यार, शादी कोई गुनाह नहीं परन्तु गलत उम्र में गलत लड़कों के हाथ में फंसना बहुत ही गलत है। मां-बाप अगर सख्त होते हैं तो इनकी गलती नहीं। हर माता-पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं उनकी भली चाहते हैं, उनकी सुरक्षित शादी चाहते हैं। मुझे लगता है मां-बाप को अपने बच्चों के साथ ऐसे रिश्ते कायम रखने चाहिए ताकि वो अपनी हर बात उनसे शेयर करें। अगर उन्हें किसी दूसरे धर्म का लड़का या लड़की भी पसंद है तो वह माता-पिता से डरें नहीं उन्हें बताएं। माता-पिता हैं जांच-पड़ताल तो कर लेंगे कि सही है कि नहीं।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

इसके लिए माता-पिता को बेटी के साथ विश्वास और मित्रता वाला रिश्ता रखना होगा ताकि वो खुलकर बात कर सकें। अपने बच्चों की खासकर बेटियों की दिनचर्या, दोस्ती, सोशल मीडिया में किसके साथ जुड़े हैं, सहज तरीके से जानकारी रखें परन्तु संदेह की नजर से नहीं समझदारी से अपने बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की समझ दें। इसमें जबरदस्ती पूजा-पाठ करवाना नहीं, बल्कि धार्मिक गरिमा और आत्मसम्मान को समझाना जरूरी है। उन्हें प्रेम और प्रेम जाल का फर्क समझाना पड़ेगा, उनको समझाना होगा कि अगर कोई कहे घरवालों से मत बताना, ''तुम्हारे लिए धर्म बदल लूंगा/तुम धर्म बदल लो तो वह एक तरह का इशारा है कि वह व्यक्ति सच्चा नहीं। प्रेम में भी सेल्फ-रिस्पेक्ट जरूरी है, जो तुमसे तुम्हारी पहचान छीन लें वह प्रेम नहीं धर्म और संस्कृति आत्म-गौरव है जो इसे बदलवाना चाहता है। वह आपका भला नहीं चाहता, इसलिए धर्म कोई वस्तु नहीं जो प्रेम के लिए बदल दिया जाए, इसलिए बेटियों अपने आप को बचाकर रखो। आप अपने लिए अपने माता-पिता के लिए गर्व हो। अपने आप को 'प्रतिभा' में बांधों और हैवानों से बचो।

मोदी सरकार की शिक्षा परफॉर्मेंस नम्बर वन

शहज़ाद पूनावाला,
राष्ट्रीय प्रवक्ता,
भारतीय जनता पार्टी

पिछले 11 सालों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। चाहे वो नीतियों में बड़े सुधार हों, नए संस्थानों की शुरुआत हो, डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल हो या शिक्षा को वैश्विक स्तर तक ले जाने की बात—हर कदम एक साफ़ दिशा की ओर बढ़ा है, जिसका मकसद है एक ज्ञान-आधारित, सशक्त समाज बनाना। 2014 से शुरू हुई यह यात्रा सिर्फ सुधार नहीं, एक नई सोच लेकर आई है कि शिक्षा का असली मतलब क्या होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान की यह ड्रीम टीम सिर्फ पुरानी गड़बड़ियों को ठीक ही नहीं कर रही है, बल्कि देश के युवाओं को वैश्विक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने लायक भी बना रही है।

इस बदलाव की सबसे अहम कड़ी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो पिछले 34 सालों बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह नए सिरे से गढ़ती है। यह नीति समग्र, समावेशी और कौशल-आधारित शिक्षा पर आधारित है। इसमें नया 5+3+3+4 ढांचा लागू किया गया है, जिससे बच्चों की उम्र और विकास के अनुसार पढ़ाई को ढाला गया है। इसके तहत बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाई का मौका, प्रयोगधर्मी और अनुभव-आधारित शिक्षा, और बहुभाषा सीखने पर ज़ोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के लागू होने से देश भर के क्लासरूम्स बदल रहे हैं। 'जादुई पिटारा' जैसी पहलों से प्री-प्राइमरी स्तर पर सीखना आसान बना है। स्कूलों में कोडिंग, डिज़ाइन थिंकिंग और वित्तीय साक्षरता जैसे विषयों को जोड़ा गया है। निपुण भारत मिशन के ज़रिए छोटे बच्चों में पढ़ने और गणना की क्षमता में काफी सुधार हुआ है। पहले जो शिक्षा रट्टा आधारित थी, अब वह बच्चों को सोचने और समझने वाली बना रही है।

लंबे समय तक भाषा का अभिजात्य रवैया शिक्षा से लाखों बच्चों को दूर रखता था। अब यह बाधा तोड़ी जा रही है। 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 104 किताबें स्थानीय भाषाओं में तैयार की गई हैं, और पहली बार कक्षा 1 से 12 तक के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा भी विकसित की गई है।

मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि यह रही है कि उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 2014 के 760 से बढ़कर 2024 में 1213 हो गई—यानि 60 प्रतिशत की वृद्धि। कॉलेजों की संख्या भी 21 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ी है। इसका मतलब है कि शिक्षा अब सिर्फ शहरों में नहीं, गांव-गांव तक पहुंच रही है। इस दौरान सरकार ने 42 नए केंद्रीय संस्थान शुरू किए।

लड़कियों की शिक्षा और आर्थिक मदद दी गई है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाओं ने सच में असर दिखाया है। लड़कियों का सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोलमेंट 75.5 प्रतिशत से बढ़कर 78 प्रतिशत हुआ है। (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित) क्षेत्रों में लड़कियों की भागीदारी 23 प्रतिशत बढ़ी है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीमें गरीब परिवारों की लड़कियों को पढ़ाई का मौका दे रही हैं। आज के दौर में केवल पढ़ाई काफी नहीं, स्किल ज़रूरी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.63 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। आईटीआई संस्थानों की संख्या 46 प्रतिशत बढ़ी है जिससे गांव-कस्बों के छात्रों को भी आधुनिक तकनीकी शिक्षा मिल रही है।

भारत प्राचीन समय में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों के लिए जाना जाता था। अब हम उस विरासत को फिर से जगा रहे हैं। विश्व रैंकिंग में भारत की 54 संस्थाएं 2026 में शामिल हैं, जबकि 2015 में सिर्फ 11 थीं। हमारे आईआईटीएस की औसत रैंक 224 से घटकर 186 हो गई है, यानि वैश्विक स्तर पर बड़ी छलांग।

एक और बड़ा सुधार है परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों पर सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति। पब्लिक एग्ज़ामिनेशन (अनफेयर मीन्स रोकथाम) कानून 2024 के तहत पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, साथ ही संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।

इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार करेगी। अब नकल माफिया और राजनीतिक संरक्षण वाले गिरोहों पर लगाम कसने से यह साबित होता है कि सरकार योग्यता और ईमानदारी को सबसे ऊपर मानती है।

शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने शिक्षा नीति को लागू कराने, संस्थानों तक पहुंच बढ़ाने, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और डिजिटल शिक्षा को मज़बूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनकी मेहनत से यह नीति सिर्फ कागज़ों में नहीं रह गई, बल्कि स्कूलों, कॉलेजों और गांवों तक असर दिखा रही है।

पीएम मोदी कुशल प्रशासक और आध्यात्मिक व्यक्ति : स्वामी शक्ति शरणानंद सरस्वती

मोतिहारी, (पंजाब केसरी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के मोतिहारी जिले के अपने दौरे के दौरान स्वामी शक्ति शरणानंद सरस्वती उर्फ चंचल बाबा से मुलाकात की थी।

पीएम से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए चंचल बाबा ने कहा है कि वह एक कुशल प्रशासक के साथ ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। स्वामी शक्ति शरणानंद सरस्वती ने कहा, हमारी मुलाकात कुछ देर तक चली। प्रधानमंत्री का आकर्षण और दृढ़ संकल्प अद्भुत है। यही उनके लगातार काम करने की वजह है। वह एक बेहतरीन प्रशासक होने के साथ-साथ आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं।

उन्होंने कहा कि पीएम से मुलाकात के दौरान मोतिहारी के उद्योग धंधों को लेकर भी चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान चंचल बाबा ने पीएम से कहा था कि लोग दुनिया जीतने के लिए युद्ध करते हैं। लेकिन, आपने बिना किसी युद्ध के दुनिया जीत ली। भगवान राम के रास्ते पर चलते हुए आपने इस देश के लिए जो किया है, वो कोई नहीं कर सका।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी चंचल बाबा से हुई मुलाकात का जिक्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया था। पीएम ने लिखा, आज मुझे मोतिहारी में स्वामी शक्ति शरणानंद सरस्वती जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

उस्तरा

महेश गर्ग 'बेधड़क'

चार दिन की जिंदगी है

जिंदगी में घोल के रस, कंठ से गाया करें
चार दिन की जिंदगी है, क्यों इसे जाया करें
टेंशनों को दूर करके काम का लेवें मजा
सुबह शाम डंड पेलें, ठूंस कर खाया करें।

बाल-बोध

बच्चे काबिल हों
पत्नी भली हो
चेहरे पर मुस्कराहट हो
जिंदादिली हो
आंखों में चमक हो
जेब में माल हो
फिर क्या जरूरी है कि
सिर पर बाल हों।

चूरण

बॉस : मीटिंग में तुम्हारी आंखें क्यों बंद थीं?
कर्मचारी : सर, मैं आंतरिक विचार-विमर्श कर रहा था!
बॉस : और वो खर्राटे?
कर्मचारी : सिस्टम अपडेट हो रहा था, सर!

सोनू को आम के पेड़ पर चढ़ता देख अंकल थैला लेकर नीचे पहुंच गए, सोनू पेड़ पर चढ़ा और सेल्फी लेकर उतर गया...
अंकल : सोनू बेटा, आम का क्या हुआ?
सोनू : अंकल, मैं तो मैंगोलेस एडवेंचर फोटो खींचने गया था!

गधे सड़क जाम कर धरना दे रहे थे...
रिपोर्टर : ये धरना किसके खिलाफ है?
गधों का नेता : इन्सानों के!
वे हर मूर्ख को 'गधा' कह देते हैं, यह तो हमारी इन्सल्ट है!

पोल खुल गई वाला मौसम

आम आदमी मोबाइल की टॉर्च से बरसात में सड़क ढूंढता है। उधर, व्यवस्था दांत भींचे और जबड़े सटाए हुए अंधेरों का सतत उत्पादन कर रही होती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पोल खुल गई वाला समाचार रोज छप रहा है।

बात-बेबात

अरविंद तिवारी

इस बरसात में हम कई जिलों की यात्रा पर थे। मानसून लगभग पूरे देश को अपने आगोश में ले चुका है। लोक संस्कृति में रुचि रखने के कारण हम यात्रा के दौरान उस जिले की लोकल खबरों को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। इस यात्रा में हमने हर जिले के अखबार में लोकल पन्ने पर एक ही शीर्षक से समाचार छपा हुआ देखा- 'नगर निगम की पोल खुल गई!' बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक एक ही खबर। ऐसा लगता है, जैसे पूरे देश के अखबारों ने तय कर लिया है कि बरसात के मौसम में नगर पालिका या नगर निगम की 'पोल खुल गई' वाला समाचार रोज छापना है। कहीं नाला उफान पर है तो कहीं शहर की चिकनी सड़क बरसाती पानी के साथ भाग गई। मुझे लगा, कहीं अखबार वाले पिछले साल की खबरों को तो नहीं छाप रहे! पर लोगों से बात करने पर पता चला नहीं अभी जो स्थिति है, पिछले साल से भी बदतर है। बरसात के साथ ही 'पोल खुल गई' वाला मौसम हर साल आता है।

एक शहर का लोकल पत्रकार टकराया। हमने पूछा, एक ही शीर्षक वाली खबर सारे देश के अखबारों के लोकल पन्ने पर क्यों है। कम से कम आप तो इसे 'कलई खुल गई' शीर्षक से छाप सकते थे। उसने मुझे घूरा और कहा, लोग अब पीतल के बर्तन नहीं रखते, जिनमें कलई होती थी। हम आम आदमी की समझ वाले शीर्षक देते हैं। कलई को लेकर भी भ्रम है। कोई कलई खुलना कहता है तो कोई कलई उतरना। हम इस दुविधा में नहीं पड़ते। हमने एक आम पाठक से पूछा, क्या बरसात में नगर निगम की पोल खुल गई के बारे में आप जानते हैं। उसने कहा, नहीं। इस बरसात में हमारे घर के सामने बिजली का पोल उखड़ गया है, शायद इसलिए पोल खुल गई वाला समाचार छपा है।

बरसात आती है तो सब झूमने लगते हैं। बाढ़ के दौरान नगर आयुक्त को फोन करना चाहें कि आपके मोहल्ले में नाव चाहिए तो वह फोन हरगिज नहीं उठाएगा। दरअसल, उसकी गलती नहीं है। सारी गलती शायर की मानी जाएगी, जिसने लिखा है- 'आई बरसात तो सब झूमने लगे, सावन ने पेड़-पौधों को भी मोर कर दिया।' ये सरकारी मोर केवल नाचते ही नहीं, अपने घर में बैठकर पकौड़े भी खाते हैं, पर पब्लिक को कोई शायरी मुसीबत में अच्छी नहीं लगती। इस बीच एक खबर यह भी छपी कि एक गांव में बाढ़ का पानी घरों में घुसा तो गांव वालों ने सरपंच को ही पीट दिया। यह सुविधा अभी तक शहरों को नहीं मिली है। आशा है इसी तरह का माहौल रहा तो शहर भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं।

बहरहाल, धुआं जब आंखों को चुभने लगे तो हवन कुंड से दूर हो जाना लाजिमी है। इसमें पंडित जी से पूछने की जरूरत नहीं होती। शहर के बाशिंदे अब खुद नाव का इंतजाम कर रहे हैं। बरसात के दिनों में दुनिया के सब छल-प्रपंच जिम्मेदार व्यवस्थापक अधिकारी के कार्यालय में शिफ्ट हो जाते हैं। आखिर उन्हें भी तो सुरक्षित स्थान चाहिए। आम आदमी मोबाइल की टॉर्च से बरसात में सड़क ढूंढता है। उधर, व्यवस्था दांत भींचे और जबड़े सटाए हुए अंधेरों का सतत उत्पादन कर रही होती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पोल खुल गई वाला समाचार रोज छप रहा है। बरसात में कीचड़ होना ही होना है। इसमें कोई कुछ नहीं कर पाता।

बरसात में पब्लिक परेशान है, इसका सियासी नेताओं को बेहद अफसोस है। उनकी अफसोस वाली किस्तबंदी देखते ही बनती है। पत्रकार रोज-रोज पोल खोलने वाले समाचार छाप रहे हैं। वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। पर जिम्मेदार मुख्य अधिकारी उन्हें बुद्धू समझता है। पर ये अधिकारी यह भूल जाते हैं, अपने ही वृत्त में खेली जा रही लुका-छिपी अंततः पकड़ में आ ही जाती है।

बाबू रामधीन भीखमखेड़वी

रामाधीन कलकत्ता में अपने दोस्तों के बीच बाबू रामधीन भीखमखेड़वी के नाम से मशहूर हो गए थे।

श्रीलाल शुक्ल

बाबू रामाधीन का एक जमाने तक गांव मे बड़ा दौर-दौरा रहा। उनके मकान के सामने एक छप्पर का बंगला पड़ा था, जिसमे गांव के नौजवान जुआ खेलते थे, एक ओर भंग की ताजी पत्ती घुटती थी। वातावरण बड़ा काव्यपूर्ण था। उन्होने गांव में पहली बार कैना, नैस्टर्शियम, लार्कस्पर आदि अंग्रेजी फूल लगाए थे। इनमें लाल रंग के कुछ फूल थे, जिनके बारे में वे कभी-कभी कहते थे, 'यह पॉपी है और यह साला डबल पॉपी है।'

भीमखेड़वी के नाम से ही प्रकट था कि वे शायर भी होंगे। अब तो वे नही थे, पर कलकत्ता के अच्छे दिनों में वे एकाध बार शायर हो गए थे। उर्दू कवियों की सबसे बड़ी विशेषता उनका मातृभूमि-प्रेम है। इसलिए बंबई और कलकत्ता में भी वे अपने गांव या कस्बे का नाम अपने नाम के पीछे बांधे रहते हैं और उसे खटखटा नहीं समझते। अपने को गोंडवी, सलोनवी और अमरोहवी कहकर वे

उर्दू कवि बंबई और कलकत्ता में भी अपने गांव या कस्बे का नाम अपने नाम के पीछे बांधे रहते हैं और उसे खटखटा नहीं समझते।

इधर-उधर से

कलकत्ता-बंबई के कूप-मंडूक लोगों को इशारे से समझाते हैं कि सारी दुनिया तुम्हारे शहर ही में सीमित नहीं है। जहां बंबई है, वहां गोंडा भी है।

जिसे अपने को बंबई मे 'संडीलवी' कहते हुए शर्म नहीं आती, वहीं कुर्ता-पायजामा पहनकर और मुंह में चार पान और चार लिटर थूक भरकर न्यूयार्क के फुटपाथों पर अपने देश की सभ्यता का झंडा खड़ा कर सकता है। एक प्रकार से यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जन्मभूमि के प्रेम से ही देश-प्रेम पैदा होता है। जो कलकत्ता में अपने को बाराबंकवी कहते हुए हिचकता है, वह यकीनन विलायत में अपने को हिंदुस्तानी कहते हुए हिचकेगा।

इसी सिद्धांत के अनुसार रामाधीन कलकत्ता में अपने दोस्तों के बीच बाबू रामाधीन भीखमखेड़वी के नाम से मशहूर हो गए थे। यह सब दानिश टांडवी की सोहबत में हुआ था। वे टांडवी की देखा-देखी उर्दू कविता में दिलचस्पी लेने लगे।

('राग दरबारी' से)

आड़े-तिरछे

रेखांकन : दुर्गादत्त पांडेय

मैं प्रलोभन को छोड़कर हर चीज का विरोध कर सकता हूं।
ऑस्कर वाइल्ड

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

Job Alert

Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

आरपीएससी ने जारी किया विज्ञापन

पुलिस सब इंस्पेक्टर (एसआई) व अन्य पद खाली

RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग — 1015 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 08 सितंबर, 2025
आयु-सीमा : न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : rpsc.rajasthan.gov.in

डीआरडीओ-आरएसी में करें आवेदन ■ 152 पद

साइंटिस्ट के पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025
पात्रताएं बीई, बीटेक व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें rac.gov.in

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ■ 84 पद

प्लाटून कमांडर के पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त, 2025
आयु-सीमा न्यूनतम आयु 20 व अधिकतम आयु 25 वर्ष
यहां आवेदन करें rssb.rajasthan.gov.in

मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी ■ 346 पद

जूनियर इंजीनियर, फायरमैन व अन्य पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि : 21 अगस्त, 2025
योग्यताएं : बीई, बीटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : mppgcl.mp.gov.in

रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ■ 40 पद

अप्रेंटिसशिप के लिए करें आवेदन
आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त, 2025
वेतनमान रुपये 12,000 से रुपये 14,000 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें railtel.in

एसजीपीजीआईएमएस, लखनऊ ■ 22 पद

पार्ट टाइम/एक्सटर्नल गेस्ट फैकल्टी बनने का मौका
वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि 30 जुलाई, 2025
पात्रताएं एमए, एमएससी, एमफिल आदि निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें sgpgims.org.in

यहां भी रोजगार के अवसर ...

- भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित : महाप्रबंधक के पदों पर रिक्तियां।
  आवेदन की अंतिम : 01 अगस्त, 2025
  ■nccf-india.com
- डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश : शिक्षक के पदों पर नियुक्ति पाने का अवसर।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 27 जुलाई, 2025
  ■aktu.ac.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

SCHOLARSHIP ALERT

यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स इंडिया स्कॉलरशिप-2025

ससेक्स विश्वविद्यालय की ओर से यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स इंडिया स्कॉलरशिप-2025 भारत के उन प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है, जो सितंबर 2025 से शुरू होने वाले पूर्णकालिक मास्टर्स डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य प्रतिभाशाली भारतीय छात्रों के लिए ससेक्स में विश्वस्तरीय शिक्षा को अधिक सुलभ और आसान बनाना है। चयनित छात्रों को ट्यूशन शुल्क में जीबीपी 4,000 की छूट मिलेगी। छात्रों का चयन शैक्षणिक योग्यता व अन्य सहायक दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा, छात्रों के पास शैक्षणिक प्रतिलेख व प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, नागरिकता का प्रमाणपत्र (जैसे पासपोर्ट), व्यक्तिगत विवरण, विश्वविद्यालय स्वीकृति पत्र, अंग्रेजी भाषा प्रवीणता (यदि अंग्रेजी आवेदक की पहली भाषा नहीं है) और पाठ्यक्रम विवरण जैसे दस्तावेज होने चाहिए।

- आवेदन की अंतिम तिथि : 01 सितंबर, 2025
- आवेदन लिंक : tinyurl.com/ms2j755j

वंचित तबके के होनहारों के लिए आर्थिक मदद

एचडीएफसी बैंक की ओर से ईसीएसएस प्रोग्राम 2025-26 की पहल की जा रही है। इसका उद्देश्य वंचित पृष्ठभूमि के मेधावी और आर्थिक रूप से जरूरतमंद छात्रों की सहायता करना है। आवेदन के लिए जरूरी है कि छात्र वर्तमान में निजी, सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा एक से बारहवीं, डिप्लोमा, आईटीआई या पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हों। साथ ही, आवेदकों ने पिछली योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 55 फीसदी अंक प्राप्त किए हों। आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम होनी चाहिए। उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षा का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। कक्षा एक से छह तक के चयनित छात्रों को 15,000 रुपये तथा उससे ऊपर के छात्रों को 18,000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा।

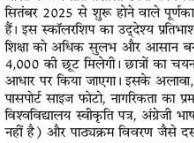

- आवेदन की अंतिम तिथि : 04 सितंबर, 2025
- आवेदन लिंक : hdfcbankecss.com

स्नातक में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए वजीफा

सोनी म्यूजिक ग्रुप की ओर से ग्लोबल स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वैश्विक समुदाय में अग्रणी संगीत और संगीत व्यवसाय शिक्षा संस्थानों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देना है। यह छात्रवृत्ति उन छात्रों के लिए है, जो शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 के दौरान संगीत या संगीत व्यवसाय से संबंधित अध्ययन के क्षेत्रों में किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक स्नातक छात्र के रूप में नामांकन करने की योजना बना रहे हैं। आवेदन के लिए जरूरी है कि आवेदकों ने अपनी पिछली कक्षा में 4.0 पैमाने पर 3.0 या उससे अधिक का जीपीए हासिल किया हो। चयनित छात्रों को डिग्री प्रोग्राम को पूरा करने के लिए आवश्यक ट्यूशन और अनिवार्य शुल्क के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 3,000 अमेरिकी डॉलर से 20,000 अमेरिकी डॉलर तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। यह कॉलेज/विश्वविद्यालय के स्थान, प्रकार और सोनी म्यूजिक ग्रुप ग्लोबल स्कॉलर की अपेक्षित वित्तीय आवश्यकता के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।

- आवेदन की अंतिम तिथि : 08 अगस्त, 2025
- आवेदन लिंक : iie.org

आज का दिन

20 जुलाई, 2005

कनाडा में समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी थी। ऐसा करने वाला कनाडा दुनिया का चौथा देश बन गया था। इससे पहले नीदरलैंड, बेल्जियम और स्पेन समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे चुके थे।

- 1847 : जर्मनी के खगोलशास्त्री थियोडोर ने धूमकेतु ब्रोरसेन-मेटकॉफ की खोज की थी।
- 1903 : फोर्ड मोटर कंपनी ने पहली कार बाजार में उतारी थी।
- 1951 : जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला प्रथम यरुशलम में हुए हमले में मारे गए थे।
- 1956 : फ्रांस ने ट्यूनीशिया को स्वतंत्र देश घोषित किया था।

व्रत त्योहार

आज : श्रावण कृष्ण पक्ष दशमी। **कल :** कामिका एकादशी, रोहिणी व्रत, वर्षा ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, उत्तर गोले।
राहुकाल : प्रातः 07.30 से 09.00 तक।

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2082, 30 आषाढ़ मास शक 1947, श्रावण मास 06 प्रविष्टे, 25 मुहर्रम हिजरी 1447, श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी 09.38 तक उपरांत द्वादशी, रोहिणी नक्षत्र 21.06 तक उपरांत मृगशिरा नक्षत्र, वृद्धि योग 18.38 तक उपरांत ध्रुव योग, बालव करण 09.38 तक उपरांत कौलव करण, चंद्रमा वृष राशि में दिन-रात।

- सूर्योदय : 05.40
- सूर्यास्त : 19.14

(भारतीय मानक समयानुसार)

amarujala.com/astrology

राशिफल

■ पं. विनोद त्यागी

मेष : पारिवारिक समस्याओं में उलझे रहेंगे। आर्थिक चिंतन बना रहेगा। व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे।

वृष : प्रभावी व्यक्ति से जान-पहचान बढ़ेगी। विकास के नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापारिक लाभ से खुशी होगी।

मिथुन : आत्मबल बढ़ेगा। बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी प्राप्ति संभव है। व्यापार में धन लाभ होगा।

कर्क : पूर्व नियोजित कार्य में सफलता मिलेगी। दोस्ती में कोई कार्य बनेगा। परिवार में आनंद रहेगा।

सिंह : मनोत्साह बना रहेगा। आमोद-प्रमोद के अवसर मिलेंगे। व्यवसाय में विस्तार और उत्तम लाभ होगा।

कन्या : मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। अकारण विवाद संभव है। अपने ही धन की प्राप्ति में विलंब होगा।

तुला : आत्मबल बनाए रखें। आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतें। नए कार्य में सोच समझकर निर्णय लें।

वृश्चिक : भविष्य के प्रति आशान्वित रहेंगे। नौकरी प्राप्ति का अवसर मिल सकता है। अर्थ प्राप्ति संभव है।

धनु : सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। चली आ रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शत्रु परास्त होंगे। व्यवसाय में लाभ होगा।

मकर : आत्मविश्वास बनाए रखने पर कार्य सफल होंगे। कॅरिअर में उन्नति का अवसर मिल सकता है।

कुंभ : मानसिक उथल पुथल बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में श्रम की अधिकता रहेगी। व्यवसाय में यथेष्ट लाभ होगा।

मीन : धार्मिक आयोजन में व्यस्त रहेंगे। नई योजना सफल होगी। व्यावसायिक क्षेत्र में सावधानी बरतें।

जन्मदिन

नसीरुद्दीन शाह, अभिनेता

इस वर्ष अटके कार्यों में सफलता मिलेगी। राजनैतिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। विरोधी परास्त होंगे। न्याय क्षेत्र में विजय मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। जमीन-जायदाद में वृद्धि हो सकती है। विकास मार्ग प्रशस्त रहेगा। परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा। रोजगारपरक परीक्षाओं में सफलता मिलेगी।

सुडोकू

6			2		8	1		
							6	
			1		4		7	2
	3		9				5	
2	6		4		7		9	8
	5				6		2	
5	1		8		2			
	4							
		8	6		5			3

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

6	7	5	2	9	8	1	3	4
1	2	4	5	7	3	8	6	9
9	8	3	1	6	4	5	7	2
8	3	7	9	2	1	4	5	6
2	6	1	4	5	7	3	9	8
4	5	9	3	8	6	7	2	1
5	1	6	8	3	2	9	4	7
3	4	2	7	1	9	6	8	5
7	9	8	6	4	5	2	1	3

डेली हेल्थ कैप्सूल

किस समय कौन-सा मेवा खाएं

ड्राई फ्रूट खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसका सेवन किस समय करें, ताकि बेहतर परिणाम मिल सके।

ड्राई फ्रूट्स या सूखे मेवे (बादाम, काजू, किशमिश, खजूर, अखरोट, पिस्ता, अंजीर, खुबानी आदि), वे फल होते हैं, जिन्हें पानी निकालकर सुखाया जाता है। सूखे हुए रूप में भी ये पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं। सूखे मेवों को उनके प्राकृतिक रूप में खाया जा सकता है या उन्हें विभिन्न व्यंजन में मिठाई, डेजर्ट, स्मूदी आदि में इस्तेमाल किया जा सकता है। सूखे मेवों को अपनी नियमित डाइट में अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे- विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सिडेंट और फाइबर आदि। जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सूखे मेवों को सुबह खाली पेट या नाश्ते के साथ खाना सबसे अच्छा माना जाता है। सुबह खाली पेट ड्राई फ्रूट्स खाने से शरीर को दिन भर के लिए ऊर्जा मिलती है और पोषक तत्वों का अवशोषण भी बेहतर होता है। आप इन्हें नाश्ते के साथ भी खा सकते हैं या फिर दिन में स्नैक्स के रूप में भी ले सकते हैं, मगर रात में ड्राई फ्रूट्स खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन में समस्या हो सकती है। सूखे मेवों का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन इनका सेवन एक सीमित मात्रा (25-50 ग्राम) में ही करना चाहिए।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

सुबह खाली पेट ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने से पोषक तत्व शरीर द्वारा बेहतर तरीके से अवशोषित होते हैं और आसानी से पच जाते हैं। वहीं रात के समय खाने से आपको परेशानी हो सकती है।

-प्रीता जैन
आहार विशेषज्ञ

प्रेम के जरिये तांबे के टुकड़े को भी सोने में बदला जा सकता है।

-रूमी

टंप के टैरिफ का कहर तांबे पर टूट पड़ा है। अमेरिका में तांबे की आपूर्ति पर 50 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। चिली दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है, जो विश्व को करीब 28 फीसदी तांबे की आपूर्ति करता है। तांबे की कीमतों में उतार-चढ़ाव चिली की सियासत को हिला देता है, क्योंकि चिली 'बॉर्न विद कॉपर स्पून' है।

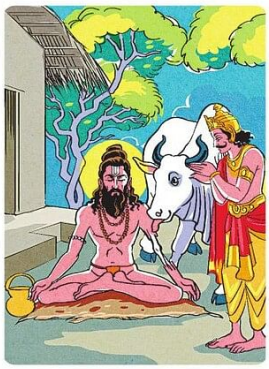

ट्रंप का टैरिफ और चिली का तांबा

अंशुमान तिवारी
वरिष्ठ पत्रकार

तांबे पर टैरिफ बढ़ने से कनाडा से भारत तक और ब्राजील से चीन तक पूरा तांबा बाजार झनझना गया। अब अमेरिका में तांबा महंगा हो गया है और शेष दुनिया में सस्ता। इससे सर्वाधिक नुकसान चिली को होगा, जिसकी अर्थव्यवस्था की धड़कन तांबा है। तांबे को लेकर अमेरिका बनाम चिली के वे पुराने दिन कभी भी लौट सकते हैं।

यह काम केवल राजनेता ही कर सकते हैं कि जब आप सबसे ज्यादा भूखे हों, तब वे रोटी पर टैक्स लगा दें। कॉपर यानी तांबे के साथ यही हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहनों और नई बिजली आपूर्ति ग्रिड के लिए तांबे की मांग से तप रही दुनिया पर ट्रंप के टैरिफ फट पड़े। अमेरिका में तांबे की आपूर्ति पर 50 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी।

कनाडा से भारत तक और ब्राजील से चीन तक पूरा तांबा बाजार झनझना गया। अब अमेरिका में कॉपर महंगा हो गया है और शेष दुनिया में सस्ता, क्योंकि जब तांबा अमेरिका में नहीं जाएगा, तो अन्य देशों में पहुंचेगा। इससे सबसे ज्यादा झटका किसे लगा? चिली को, दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक, विश्व का करीब 28 फीसदी कॉपर यहीं से आता है। कॉपर की कीमतों में उतार-चढ़ाव चिली की सियासत को हिला देता है, क्योंकि चिली 'बॉर्न विद कॉपर स्पून' है।

टाइम मशीन
अतीत से सुनें वर्तमान की धड़कन ▪ हर पखवाड़े

आइए, बैठिए टाइम मशीन में, चलते हैं चिली, यह देखने कि कॉपर ने किस तरह देश की सियासत को उलट-पलट दिया। टाइम मशीन हमें अटाकामा रेगिस्तान के ऊपर ले जा रही है। यह दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल है, जो 15 करोड़ साल पुराना है। साल में 15 मिलीमीटर बारिश भी यहां चमत्कार है। एक तरफ एंडीज की हिमाच्छादित चोटियां, दूसरी ओर ठंडा प्रशांत महासागर। लेकिन जरा नीचे तो देखिए...यह है चुक्कीकमाटा। दुनिया की सबसे बड़ी खुली तांबा खदान। 4.3 किमी लंबी, 3 किमी चौड़ी और 3,000 फीट गहरी। यह चिली की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। टाइम मशीन की घड़ी बता रही है कि हम 1952 में पहुंच गए हैं। चुक्कीकमाटा की विशाल खदान चमक रही है, लेकिन मजदूरों का जीवन अंधेरे में है। अमेरिकी कंपनी अनाकोंडा माइनिंग खदान की मालिक है। खदान के पास मजदूरों का शहर है-मकान, स्कूल, सॉकर मैदान, लेकिन मजदूरों की दशा अच्छी नहीं है। उस युवा को देख रहे हैं आप, जो मोटरसाइकिल पर सवार है? सही पहचाना आपने... यह चे ग्वेरा हैं, जो अपनी *मोटरसाइकिल डायरीज* के लिए दक्षिण अमेरिका की यात्रा में चुक्कीकमाटा आए हैं। 24 साल का यह युवा डॉक्टर मजदूरों से मिल रहा है। उसे पता चलता है कि अनाकोंडा न्यूनतम वेतन देने से इन्कार करती है, जबकि कंपनी लाखों डॉलर कमा रही है। चे अपनी डायरी में लिखते हैं : 'यह तांबा चिली का खून है, पर इसकी चमक विदेशी जेबों में जा रही है।' याद रखिएगा कि चुक्कीकमाटा में चे ग्वेरा की यह यात्रा क्यूबा क्रांति की प्रेरणा बनेगी।

अरे उधर तो देखिए...कौन है वहां? हां...वह पाब्लो नेरुदा ही हैं। उनकी एक कविता चर्चा में है। नोबेल पुरस्कार के लिए उनकी मंजिल अभी दूर है, पर उनके साहित्य की बुनियाद चुक्कीकमाटा में रखी गई है। लोग बात कर रहे हैं कि कुछ वक्त पहले नेरुदा यहां आए थे, उन्होंने एक रात मजदूरों के साथ बिताई। उन्हें एक बच्चे की कहानी मिली है, जो खदान की धूल से बीमार था। नेरुदा की कविता *नाइट इन चुक्कीकमाटा* अनाकोंडा को 'हरी राक्षसी' कहती है। उनकी पंक्तियां गूंजती हैं :

In the clustered heights,
beneath the moon of hardness-excavator-
you open the mineral's lunar craters.

चे और नेरुदा की आवाजें मजदूर आंदोलनों को हवा देती हैं। हड़तालें शुरू होती हैं। चुक्कीकमाटा में अनाकोंडा के खिलाफ नारे गूंज रहे हैं। टाइम मशीन के कोआर्डिनेट्स बता रहे हैं कि अब हम 1966 में हैं। चुक्कीकमाटा सियासत के केंद्र में है। राष्ट्रपति एडुआर्डो फ्रे मोंतालवा ने तांबा खदानों का राष्ट्रीयकरण शुरू कर दिया है। कॉपर कॉरपोरेशन ऑफ चिली (कोडेल्को) का गठन होता है। चुक्कीकमाटा का आंशिक राष्ट्रीयकरण हो रहा है, मगर चिली के लोग पूछ रहे हैं कि अगर खदानें चिली की हैं, तो फिर अमेरिकी कंपनियों को हिस्सा क्यों मिल रहा है?

आप भी महसूस कर रहे हैं न आंदोलन की तपिश...महिलाएं आवाज लगा रही हैं, 'तांबा चिली का है, न कि अनाकोंडा का।' मजदूरों की हड़तालें तेज हो रही हैं। चुक्कीकमाटा राष्ट्रीयकरण की मांग का प्रतीक बन रही है।

अब हम 1970 में आ गए हैं। सैंटियागो में उतरिए। यहां बड़ी गहमा-गहमी है। सल्वाडोर अलांदे 'चिलियनाइजेशन ऑफ कॉपर' के नारे पर चुनाव जीत गए हैं। उनका वादा है पूर्ण राष्ट्रीयकरण। चुक्कीकमाटा पर अनाकोंडा का कब्जा समाप्त होने का एलान हो गया है। सरकारी कंपनी कोडेल्को खदान की मालिक है। सड़कों पर जश्न है। मजदूर कह रहे हैं, 'यह तांबा हमारा है, हमारी धरती का खजाना।'

लेकिन अमेरिका नाराज है। अनाकोंडा का दावा है कि राष्ट्रीयकरण से उसे 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। व्हाइट हाउस में सियासी साजिशें शुरू होती हैं। चुक्कीकमाटा की यह जीत चिली और अमेरिका के रिश्तों को खराब कर रही है। अब हम चिली के एक काले दौर की ओर बढ़ रहे हैं। मशीन की घड़ी बता रही है कि यह 1973 का साल है। चुक्कीकमाटा खतरे में है। अगस्तो पिनोचे ने सत्ता हथिया ली है। सल्वाडोर अलांदे का तख्तापलट हो गया है। नेरुदा की कविताएं प्रतिबंधित हो गई हैं। चुक्कीकमाटा का मजदूर शहर उजाड़ दिया जाता है, क्योंकि खदान का विस्तार इसे निगल रहा है। मजदूरों को कालमा शहर में बसाया जाता है। पिनोचे तांबे की खदानों का निजीकरण नहीं करते। कोडेल्को चुक्कीकमाटा को चलाता रहता है, क्योंकि तांबा चिली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

टाइम मशीन की घड़ी और आपके मोबाइल की घड़ी का समय अब एक हो गया है। हम 2025 में ट्रंप के युग में लौट रहे हैं। चुक्कीकमाटा की खदान आज भी चिली की धड़कन है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के 50 फीसदी तांबा टैरिफ ने नया संकट खड़ा कर दिया है। तांबे की कीमतें वैश्विक बाजार में गिर रही हैं, क्योंकि अमेरिका अब चिली का तांबा कम खरीदता है।

चिली की अर्थव्यवस्था, जो तांबे पर 40 फीसदी निर्भर है, डगमगा रही है। टाइम मशीन सैंटियागो में विश्राम करेगी। आप तांबे के भविष्य पर नजर रखिए। क्या तांबे की गिरती कीमतें चिली को मंदी में धकेलेंगी? कीमतों में 20 फीसदी की गिरावट से चिली की जीडीपी में दो से तीन फीसदी की कमी आ सकती है। तांबे को लेकर अमेरिका बनाम चिली के वे पुराने दिन कभी भी लौट सकते हैं।

फिर मिलते हैं, अगले सफर पर...

अलमात्मीयं विदितं-विदितं
धनिकस्य याचकोऽवहितः।
चन्द्रं ब्रवीति चटकं-चटकं
चन्द्रं च लोभलोलमना॥

स्वयं को जान लेना पर्याप्त है। कोई भिखारी भी धनिक को प्रसन्न करना जानता है। वह लोभ से विचलित होकर दानदाता की प्रसन्नता के लिए चंद्रमा को चातक पक्षी और चातक पक्षी को ही चंद्रमा कहता है।

-श्रीहरिहरसुभाषितम् (6.28)

प्रस्तुति : शास्त्री कोसलेंद्रदास

खुद को गले लगाकर तो देखें

क्रिस्टीना कैरन
द न्यूयॉर्क टाइम्स

अपने बचपन के दर्दों और अधूरी ख्वाहिशों को अगर वर्तमान की नजर से देखा जाए, या कहें कि खुद को गले लगाकर देखा जाए, तो कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं खुद-ब-खुद हल हो जाएंगी।

टेक्सास के फोर्ट वर्थ में रहने वाली 54 वर्षीय फिटनेस कोच लॉरा वेल्स ने जब पहली बार खुद को गले लगाने की कोशिश की, तो उन्हें लगा कि यह बेवकूफी है। फिर उन्हें एहसास हुआ कि 'इससे वाकई मदद मिलती है।' अपने भीतर के आहत बच्चे की पुनः परवरिश उन तरीकों में से एक है, जिससे उन भावनात्मक जरूरतों को पूरा किया जाता है, जिनकी बचपन में उपेक्षा की गई थी। पुनः परवरिश का विचार दशकों से प्रचलित है, लेकिन हाल के वर्षों में यह चलन फल-फूल रहा है। पुनः परवरिश में रोगी को अपने भीतर के आहत बच्चे को खोजने और उसे प्यार का एहसास दिलाने में सक्षम बनाया जाता है, ताकि वह स्वयं के प्रति एक मजबूत भावना और दूसरों के साथ बेहतर संबंध विकसित कर सके। यह कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। पेशेवर परामर्शदाता और इस विषय पर एक नई पुस्तक की लेखिका निकोल जॉनसन ने कहा कि मैं हमेशा लोगों से कहती हूं कि अपने भीतर के बच्चे की पुनः परवरिश करना असुविधाजनक और अजीब होता है। पुनः परवरिश (पुनर्पालन) की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जब चिकित्सक जैकी शिफ ने सिजोफ्रेनिया से पीड़ित अपने मरीजों को अपने साथ रहने और फिर बचपन में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक देखभालकर्ता की भूमिका निभाई और अपने मरीजों को गोद में उठाया। उन्हें डायपर पहनने और बोतल से दूध पीने में भी मदद की। शुरू में उनकी अपारंपरिक पद्धति की प्रशंसा हुई, लेकिन जब उनकी देखभाल में एक मरीज की मौत हो गई, तो उन्हें नैतिकता के उल्लंघन का दोषी पाया गया और उनकी पद्धति की व्यापक रूप से आलोचना की गई।

1970 के दशक में, मनोचिकित्सक म्यूरियल जेम्स ने पुनर्पालन की नई अवधारणा प्रस्तुत की। उनका मानना था कि यह एक स्व-निर्देशित प्रयास होना चाहिए, जहां चिकित्सक नहीं, बल्कि रोगी अपने भीतर के बच्चे के लिए एक प्रेमपूर्ण अभिभावक की भूमिका निभाए। पुनर्पालन का यही वह रूप है, जो आज सबसे अधिक स्वीकृत और प्रचलित है। कुछ पुनर्पालन रणनीतियों को स्वतंत्र रूप से निपटाया जा सकता है, लेकिन डॉ. बेट ने कहा कि किसी चिकित्सक से मदद लेना सबसे अच्छा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, पुनर्पालन एक तकनीक है, न कि चिकित्सा। वेल्स के लिए अपने भीतर के बच्चे की पुनः परवरिश मददगार साबित हुई है।

©The New York Times 2025

जानना जरूरी है
संस्कृति के पन्नों से

आशुतोष गर्ग
लेखक एवं अनुवादक

त्वष्टा ने तपस्या कर ब्रह्मा जी से ऐसा पुत्र मांगा, जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। इसके बाद वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। देवताओं के आग्रह पर वृत्रासुर के वध के लिए महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां वज्र बनाने के लिए दान कर दीं।

दधीचि ने क्यों दान कीं अपनी अस्थियां

इंद्र को अपने गुरु विश्वरूप पर संदेह हुआ, तो उन्होंने उनकी हत्या कर दी। विश्वरूप तपस्वी ब्राह्मण थे। यह समाचार जब उनके पिता त्वष्टा को मिला, तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठे। त्वष्टा ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से वर मांगा, 'मुझे ऐसा पुत्र दीजिए, जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो और जो देवताओं के लिए भय का कारण बने।' ब्रह्मा ने त्वष्टा को इच्छा-पूर्ति का वरदान दे दिया, जिसके फलस्वरूप त्वष्टा की यज्ञ-अग्नि से एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ। उसका नाम वृत्रासुर था। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह प्रतिदिन सौ धनुष (लगभग चार सौ हाथ) तक बढ़ जाता था। उसकी शक्ति को देखकर पाताललोक के असुर, जिनमें से कई अमृत-मंथन के समय मारे जा चुके थे और जिन्हें शुक्राचार्य ने पुनः जीवित कर दिया था, वृत्रासुर के पास आ गए। सभी ने वृत्रासुर को अपना अधिपति मान लिया।

धूप आने दो

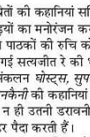

वृत्रासुर ने अपना प्रभुत्व बढ़ाते हुए तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसकी शक्ति से त्रस्त होकर अनेक ऋषि-मुनि भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पीड़ा बताई। ब्रह्मा जी बोले, 'यह असुर त्वष्टा की तपस्या से उत्पन्न हुआ है। कोई उपाय खोजना होगा, जिससे यह मारा जा सके।' देवताओं ने कहा, 'जब इंद्र को ब्रह्महत्या से मुक्त कर फिर से स्वर्ग का राजा बनाया गया, तब हमसे एक भूल हो गई। हमने अपने दिव्य अस्त्र-शस्त्र महर्षि दधीचि के आश्रम में रख दिए थे। अब वे अस्त्र हमारे पास नहीं हैं, तो हम वृत्रासुर से युद्ध कैसे करें?' ब्रह्मा ने देवताओं को सुझाव दिया और कहा, 'तुम महर्षि दधीचि के पास जाओ और उनसे उनकी अस्थियां मांग लो। दधीचि की अस्थियों से वज्र बनाया जा सकता है और उसी से वृत्रासुर का वध संभव हो पाएगा।'

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

● देवताओं ने दधीचि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में इंद्र ने संकोच से कहा, 'वृत्रासुर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। उसकी हत्या करना क्या उचित होगा?'

तब ब्रह्मा ने समझाया, 'यदि कोई ब्राह्मण भी आततायी हो, लोगों को क्षति पहुंचाता हो, तो उसे मारना धर्मसम्मत है। ऐसे व्यक्ति की हत्या ब्रह्महत्या नहीं मानी जाती।' वृत्रासुर पूर्वजन्म में चित्ररथ नामक राजा था। एक बार वह आकाश मे विहार करता हुआ कैलास पर्वत पहुंचा। वहां उसने भगवान शिव को पार्वती के साथ बैठे देखा, तो उपहास करते हुए बोला, 'शिव जैसे योगी को भी स्त्री का मोह हो गया है।' यह सुन देवी पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने चित्ररथ को शाप दे दिया, 'तू दैत्य बनकर जन्म लेगा।' वही चित्ररथ अब वृत्रासुर के रूप में जन्मा था।

इस बीच, सभी देवता दधीचि के आश्रम पर पहुंचे। दधीचि का आश्रम अत्यंत शांत था। वहां शेर और हिरण, सांप और नेवले, बिल्ली और चूहे-सभी एकसाथ प्रेम से रहते थे। किसी को किसी से भय नहीं था। दधीचि अपनी पत्नी सुवर्चा के साथ रहते थे। उनके चेहरे पर करुणा की अद्भुत झलक थी। देवताओं ने दधीचि को प्रणाम कर कहा, 'हे मुनिवर! हम सब एक भारी संकट में हैं। कृपया हमारी सहायता करें।' दधीचि बोले, 'मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए?' देवता बोले, 'यदि हमें आपकी अस्थियां मिल जाएं, तो उनसे वज्र बनाकर वृत्रासुर का वध किया जा सकता है।' दधीचि मुस्कराकर बोले, 'यह कोई कठिन बात नहीं है। परोपकार के लिए शरीर त्यागना मेरा सौभाग्य होगा। तुम मेरी अस्थियां ले सकते हो।' उन्होंने पत्नी को भीतर भेज दिया और बोले, 'कुछ क्षण रुकिए, मैं अभी शरीर त्याग देता हूं।' यह कहकर दधीचि तुरंत ध्यान में लीन हो गए और समाधि में चले गए। फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने दधीचि के मृत शरीर से अस्थियां प्राप्त कर लीं और उनसे बने वज्र नामक घातक अस्त्र से इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। इस तरह महर्षि दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनका यह बलिदान आज भी त्याग, परोपकार और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है।

अध्ययन कक्ष

घोस्ट्स, सुपरनैचुरल एंड टेल्स ऑफ अनकैनी

लेखक : सत्यजीत रे
प्रकाशक : इंडिया पफिन
मूल्य : 399 रुपये (पेपरबैक)

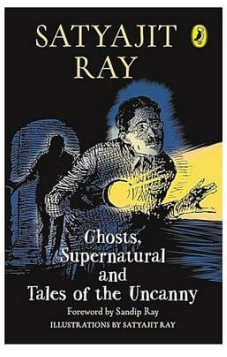

अतीत की फुसफुसाहटों में छिपी रहस्यमय दुनिया

बांग्लादेश में सत्यजीत रे का घर गिराए जाने और बांग्लादेश द्वारा अब इस खबर का खंडन किए जाने के बीच एक बार फिर सुर्खियों में आए महान फिल्मकार का 2025 में प्रकाशित भुतहा कहानियों का संकलन उनकी रहस्यात्मक दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण देता है।

भूत-प्रेतों की कहानियां सदियों से अनेक पीढ़ियों का मनोरंजन करती आ रही हैं। युवा पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर लिखी गई सत्यजीत रे की भूत-प्रेत की कहानियों के संकलन *घोस्ट्स, सुपरनैचुरल एंड टेल्स ऑफ अनकैनी* की कहानियां न तो उतनी हिंसक हैं और न ही उतनी डरावनी, बल्कि आनंददायक डर पैदा करती हैं।

बच्चों के साथ-साथ सभी उम्र के पाठकों लिए मनोरंजक ये कहानियां बताती हैं कि किस प्रकार वर्ग संघर्ष, औपनिवेशिक खुमार, पशु क्रूरता, बचपन की बुरी यादें और अपराध बोध हमारे जीवन में आगे चलकर भयावहता पैदा करते हैं। इन कहानियों में कोई भी बच्चा भूत-प्रेत से ग्रस्त नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, निर्दयता और क्रूरता उनका स्वभाव बन जाती है। इसमें औपनिवेशिक खुमार भूत-प्रेतों की कहानियों में एक दिलचस्प विषय बनकर सामने आया है।

'इंडिगो (नील)' शीर्षक कहानी में सत्यजीत रे कल्पना करते हैं कि उपनिवेशवादी का अपराधबोध कैसा दिख सकता है, जबकि 'द फर्स्ट-क्लास कम्पार्टमेंट' में, एक भारतीय जो हर भारतीय चीज का उपहास करता है, उसे अपनी जगह की याद तब आती है, जब एक गोरा साहब का भूत उसे उस कूपे से नीचे फेंकने की धमकी देता है, जिसमें वह यात्रा कर रहा है। इतिहास के भूत इतनी आसानी से नहीं मरते।

रे की भूत-प्रेत की कहानियां पाठकों को देश के कोने-कोने में ले जाती हैं। उनकी कहानियों के सभी नायक पुरुष हैं, जो छोटे कस्बों और गांवों में इन क्रूर, डरावने भूतों से मुठभेड़ करते हैं। बेहद बेचैन और आनंदित करने वाले रे के भूत मन के प्रेत हैं, न कि असली। यह रोमांचकारी संग्रह पाठकों को कल्पना के उन अंधेरे कोनों में ले जाता है, जहां वास्तविकता अलौकिकता के साथ नृत्य करती है। किस्सागोई में माहिर सत्यजीत रे सहज प्रतिभा के साथ भयावह वातावरण और बेचैन कर देने वाली कथा-स्थितियों को रचते हैं।

भुतहा घरों और हमशक्लों से लेकर रूप बदलने वालों और अतीत की फुसफुसाहटों तक, प्रत्येक कहानी एक ऐसी दुनिया का द्वार है, जहां साधारण हमेशा असाधारण से प्रभावित होता है। रे की भूत-प्रेतों की ये कहानियां बेचैन करने के बावजूद काव्यात्मक हैं, जिनमें भयावहता के बजाय शांत रहस्यमयता है। इस पुस्तक में रहस्य, जादू और भयावहता एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे खोलने का साहस कीजिए-और जो है और जो हो सकता है, उसके बीच की रेखा को धुंधला कर दीजिए।